मूल्य 5 रुपये

चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 02 मार्च –08 मार्च 2015 | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

शारदा चिट फंड घोटाले का आतंकी कनेक्शन है

सुदीप्तो सेन

"ढाका से जुड़ रहा है इस पूरे मामले का तार!"

"तृणमूल सांसद आरोपों के घेरे में"

"लोन लेकर फरार एविएशन कंपनी का दफ्तर बांग्लादेश में!"

प्रभात रंजन दीन

सीबीआई भले ही यह कहती रहे कि पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित शारदा चिट फंड घोटाले के तार बांग्लादेश से नहीं जुड़ रहे, लेकिन चौथी दुनिया के पास जो खबर है, उसके मुताबिक शारदा चिट फंड घोटाले के तार बांग्लादेश से भी जुड़े है. सूत्र बताते हैं कि घोटाले से संबद्ध जिस एविएशन कंपनी को राष्ट्रीयकृत बैंक ने हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए सैकड़ों करोड़ का कर्ज दिया था, उस कंपनी का मुख्य कार्यालय बांग्लादेश में है. सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय, दोनों ही एजेंसियां अब इस नतीजे पर पहुंची हैं कि पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित शारदा चिट फंड घोटाले से कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों के भी लिंक है. इनमें यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया अव्वल है. चौथी दुनिया ने अपने हिंदी–अंग्रेजी–उर्दू तीनों भाषा संस्करणों के पांच जनवरी–ग्यारह जनवरी के अंक में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के शारदा–लिंक का खुलासा कर चुका है. शारदा घोटाले के संबंध में पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस के जिस सांसद केडी सिंह के घर और ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, उस केडी सिंह की संदेहास्पद भूमिका के बारे में भी चौथी दुनिया के उस अंक में खास जिक्र है.

शारदा घोटाले का धन हवाला के जरिए बांग्लादेश में इस्लामी बैंक में जमा कराए जाने का कोई ठोस सबूत सीबीआई को हासिल नहीं हो पाया है. जबकि बांग्लादेश सरकार ने खुद भारत सरकार को इस बारे में जानकारी दे रखी है कि शारदा घोटाले के पैसे का गुपचुप लेनदेन बांग्लादेश की जमीन पर भी हो रहा है और तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद के कुछ आतंकी संगठनों से भी लिंक है. इसमें बांग्लादेश सरकार ने भारत सरकार से मदद भी मांगी थी और अपना पक्ष रखने का भी आग्रह किया था. केंद्र सरकार आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार भी कर चुकी है कि तृणमूल सांसद अहमद हसन इमरान के खिलाफ बांग्लादेश सरकार से भारत सरकार के गृह मंत्रालय को गंभीर रिपोर्ट प्राप्त हुई है. हसन इमरान के बांग्लादेशी आतंकी संगठन जमात–उल–मुजाहिदीन से जुड़े होने की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी गई है. इस रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर मामले की जांच शुरू कराई. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), तृणमूल सांसद हसन इमरान से दो बार पूछताछ कर चुका है. सीबीआई भी मामले की जांच कर रही है, लेकिन उसे आतंकी संगठनों से जुड़ता हुआ कोई ठोस सबूत या सुराग हासिल नहीं हुआ है. सीबीआई का कहना है कि शारदा चिटफंड घोटाले के 60 करोड़ रुपये हवाला के मार्फत बांग्लादेश इस्लामिक बैंक को भेजे जाने की सूचनाओं का कोई सुबूत नहीं मिला है. शारदा चिटफंड कंपनी के मालिक सुदीप्तो सेन के पूर्वोत्तर के कई आतंकी संगठनों से गहरे लिंक रहे है. असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और मिजोरम तक शारदा ग्रुप का पैसा पहुंचता रहा है. सुदीप्तो सेन ने असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के मंत्रिमंडल के एक मंत्री हेमंत विश्वकर्मा के जरिए नगालैंड के अलगाववादी संगठन एनएससीएन (आईएम) के साथ समझौता किया था, जिससे पूर्वोत्तर में उसका धंधा निर्बाध चलता रहे. आतंकवादी संगठन उल्फा के प्रमुख परेश बरुआ को भी शारदा से धन मिल रहा था. यह मदद बांग्लादेशी लिंक की पुष्टि करती है. परेश बरुआ वर्षों से बांग्लादेश में ही छुप कर रह रहा था. नगालैंड के एनएससीएन और असम के उल्फा के अलावा सलफा, आसू जैसे कई अलगाववादी संगठनों तक शारदा ग्रुप का पैसा पहुंचता था. अब वह कश्मीरी आतंकी संगठनों तक पहुंच बनाने की फिराक में था. कश्मीर में ही उसे सोनमर्ग से गिरफ्तार किया गया था.

> शारदा घोटाले का धन हवाला के जरिए बांग्लादेश में इस्लामी बैंक में जमा कराए जाने का कोई ठोस सबूत सीबीआई को हासिल नहीं हो पाया है. जबकि बांग्लादेश सरकार को इस बारे में जानकारी दे रखी है कि शारदा घोटाले के पैसे का गुपचुप लेनदेन बांग्लादेश की जमीन पर भी हो रहा है और तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद के कुछ आतंकी संगठनों से भी लिंक है.

बहरहाल, सीबीआई सूत्रों का कहना है कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जिस एविएशन कंपनी को सैकड़ों करोड़ रुपये का लोन दिया गया था, उसका कार्यालय बांग्लादेश में है. इस एविएशन कंपनी से तृणमूल कांग्रेस के सांसद हसन इमरान और केडी सिंह का जुड़ा होना बताया जा रहा

(शेष पृष्ठ 2 पर)

स्व. प्रभाष जोशी को ज़लील मत कीजिए शेखर गुप्ता जी पेज-03

बिहार में फिर से नीतीश राज पेज-04

कृषि क्षेत्र के कायाकल्प की ज़रूरत है पेज-07

साई की महिमा पेज-12

शारदा चिट फंड घोटाले का आतंकी कनेक्शन है

पृष्ठ एक का शेष

है. इन सांसदों का शारदा चिट फंड कंपनी से संबंधों का खुलासा हो चुका है. शारदा चिट फंड कंपनी के मालिक सुदीप्तो सेन को भी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने भारी ऋण दे रखे है. कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित बैंक की शाखा में रात के ढाई बजे शारदा चिटफंड कंपनी के मालिक के 13 लॉकर खुलवाए जाने और महत्वपूर्ण दस्तावेज वगैरह हटाए जाने के मामले की जांच चल रही है. जांच के घेरे में वह शीर्ष अधिकारी भी है जिसके आदेश पर देर रात में लॉकर खुलवाए गए थे.

शारदा स्कैम से जुड़ी जिस एविएशन कम्पनी को विमान और हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऋण दिए जाने की बात सामने आ रही है, उस एविएशन कंपनी के शारदा चिटफंड घोटाला से लिंक तो पाए ही जा रहे हैं, साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि उसी एविएशन कंपनी के विमान चुनाव प्रचार अभियान में ममता बनर्जी के काम आते रहे है. वैसे, आधिकारिक तौर पर एलकेमिस्ट नाम की कंपनी के चार्टर्ड विमानों का इस्तेमाल करने में ममता बनर्जी का नाम सामने आ चुका है. शारदा चिटफंड मामले से एलकेमिस्ट के लिंक पाए गए है. एलकेमिस्ट कंपनी के मालिक तृणमूल कांग्रेस के सांसद केडी सिंह ही है. एलकेमिस्ट कंपनी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लेकर फरार हुई एविएशन कंपनी के बीच कोई सूत्र जुड़ते हैं कि नहीं, इसकी छानबीन चल रही है. चौथी दुनिया ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर दीपक नारंग से पूछा था कि क्या बैंक की किसी शाखा में रॉयल एविएशन या एयर रॉयल एविएशन का खाता है? क्या तृणमूल कांग्रेस के सांसद केडी सिंह इनमें से किसी फर्म के मालिक हैं? सीबीआई ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कुछ अधिकारियों से पूछताछ क्यों की है? और बैंक ने सरकारी जमीनों के एवज में जो ऋण दे रखे हैं, उनकी वसूली के क्या उपाय किए हैं? इन सवालों के जवाब में नारंग ने बस इतना ही कहा था कि आई एम नॉट अवेयर (मेरी जानकारी में नहीं है).

बहरहाल, आयकर विभाग ने पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस के सांसद केडी सिंह के घर, दफ्तर और अन्य ठिकानों पर छापे मारे. इनमें दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता समेत कुछ अन्य ठिकाने शामिल है. आयकर के छापे के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय भी केडी सिंह से एक ब्रिटिश संस्था में अपने ट्रस्ट के निवेश करने के बारे में पूछताछ करेगा. केडी सिंह के ट्रस्ट ने एक ब्रिटिश संस्था में 30 मिलियन डॉलर (करीब 1.86 अरब रुपये) का निवेश किया है. वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) ने इस बारे में अपनी रिपोर्ट प्रवर्तन निदेशालय (इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट) को दी है. ब्रिटिश संस्था से चीन की एक कंपनी ने बीमा पॉलिसी खरीदी थी. ब्रिटिश संस्था की मूल कंपनी इक्विटी प्राइवेट लिमिटेड है. इसके पीछे केडी सिंह के ट्रस्ट का नाम सामने आया है. इसमें एफआईयू को दो भारतीयों के नाम मिले थे. एफआईयू की रिपोर्ट में उजागर हुआ है कि केडी सिंह के ट्रस्ट ने भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) और केंद्र सरकार को इसकी औपचारिक जानकारी नहीं दी थी. केडी सिंह की कंपनी में वित्तीय अनियमितता को लेकर छापामारी हो चुकी है. उसमें गैर खाते के 22 करोड़ रुपये जब्त किए गए थे. बीते साल भी जून महीने में केडी सिंह के एलकेमिस्ट समूह के दफ्तरों और विभिन्न ठिकानों पर छापामारी हुई थी. पश्चिम बंगाल के सात ठिकानों के अलावा देश भर के 20 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की थी.

उल्लेखनीय है कि शारदा चिटफंड घोटाले के आतंकी लिंक की तलाश में खुफिया एजेंसियां असम के परिवहन मंत्री रहे हेमंत विश्वशर्मा और उसकी पत्नी रिनिकी विश्वशर्मा से भी पूछताछ कर चुकी है. इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के नेता व पश्चिम बंगाल के खेल एवं परिवहन मंत्री मदन मित्रा, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव शंकुदेव पांडा, बांग्ला फिल्म अभिनेत्री व तृणमूल कांग्रेस की बीरभूम से सांसद शताब्दी राय, तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य सृंजय बोस, विधाननगर नगरपालिका की अध्यक्ष के पति व तृणमूल नेता समीर चक्रवर्ती, तृणमूल से निलंबित राज्यसभा सांसद कुणाल घोष, कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह, आईपीएस अधिकारी रजत मजूमदार समेत कई प्रमुख हस्तियों पर शारदा चिटफंड कंपनी घोटाले में लिप्त होने का संदेह है. इनके खिलाफ सीबीआई छानबीन कर रही है. इनमें से कई लोग गिरफ्तार भी हो चुके है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी संदेह के दायरे में है. जब राज्य सरकार को शारदा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, शारदा रियलिटी इंडिया लिमिटेड, केडी सिंह की एलकेमिस्ट इन्फ्रा रियलिटी लिमिटेड, रोजवैली होटल एंड इंटरटेनमेंट लिमिटेड समेत कई अन्य चिटफंड कंपनियों की गैरकानूनी गतिविधियों की रिपोर्ट पहले ही दी जा चुकी थी, तो उस फाइल को मुख्यमंत्री ने रोक कर क्यों रखा. यह सवाल ममता को परेशानी में डालने वाला है. यूपीए सरकार में ताकतवर मंत्री रहे पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी समेत कई अन्य हस्तियां भी एकदिन चपेटे में आएंगी.

शारदा चिटफंड घोटाले में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की संलिप्तता भी सीबीआई की जांच के घेरे में है. इसके सूत्र उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी जुड़ते है. सीबीआई ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के जिन अफसरों से कोलकाता में पूछताछ की थी, उनमें से कई अधिकारी लखनऊ से ही स्थानांतरित होकर गए है. बैंक की बहुत सारी संदिग्ध गतिविधियां सीएमडी अर्चना भार्गव के कार्यकाल में हुई. लखनऊ और कोलकाता इन गतिविधियों के केंद्र में रहा और बैंक के अरबों रुपये डुबो कर अर्चना भार्गव ने स्वैच्छिक अवकाश लेकर नौकरी छोड़ दी. बैंक प्रबंधन ने भी उन्हें जाने दिया. अब सीबीआई उनके कार्यकाल में लिए गए फैसलों की छानबीन कर रही है. शारदा चिटफंड कंपनी के मालिक सुदीप्तो सेन से लेकर विजय माल्या, रॉबर्ट वाड्रा, पवन बंसल, सुब्रत राय सहारा जैसी तमाम विवादास्पद हस्तियों को सीएमडी अर्चना भार्गव और एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर दीपक नारंग के कार्यकाल में ही बड़े-बड़े लोन हल्के-फुल्के तरीके से बांटे गए थे. सीबीआई से पूछताछ के बाद यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के जिन 27 अफसरों के खिलाफ चार्जशीट जारी हुई उनमें पूर्व सीएमडी अर्चना भार्गव या मौजूदा एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर दीपक नारंग का नाम शामिल नहीं है. प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठान लैंको को वक्फ की जमीन पर करोड़ों रुपये का लोन दे देने वाले तत्कालीन सीएमडी मधुकर और बिना किसी पूंजीगत आधार के किंग फिशर के लिए विजय माल्या को करोड़ों का लोन देने वाले ईडी दीपक नारंग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. बैंक के विजिलेंस विभाग ने मधुकर के रिटायरमेंट के पहले घर और दफ्तर की तलाशी लेकर औपचारिकता पूरी कर ली और मधुकर आराम से रिटायर हो कर नेपथ्य में चले गए. विजय माल्या को किंग फिशर के लिए मिले लोन की कुल राशि 76 सौ करोड़ रुपये है, जबकि उसके एवज में मात्र 90 करोड़ का किंग फिशर विला और 150 करोड़ का किंग फिशर हाउस की सम्पत्ति ही बैंकों के पास गिरवी है. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 336 करोड़ रुपये का लोन रिलीज़ होते ही किंग फिशर ने बैंक के शीर्ष प्रबंधन की मिलीभगत से उस बड़ी धनराशि को एक प्राइवेट बैंक के खाते में ट्रांसफर करा दिया. लेकिन ऐसे बेधड़क गैर कानूनी कृत्य पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. विडंबना यह है कि करोड़ों रुपये का लोन लेकर भागने के आरोप में डेक्कन क्रॉनिकल के मालिक टी. वेंकटराम रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन विजय माल्या को छुआ भी नहीं जाता. बिना कोई चार्ज फ्रेम किए सुब्रत राय सहारा को गिरफ्तार कर जेल में ठूंस दिया जाता है, लेकिन हजारों करोड़ रुपये दबाए बैठे नामचीन पूंजीपतियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती. इन पूंजी संस्थानों के प्रभाव में आकर उन्हें भारी-भरकम लोन देने वाले बैंकों के आला अफसरों पर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती. वही बैंक पहले गैर-वाजिब तरीके से कर्ज देते हैं और बाद में अपनी खाल बचाने के लिए प्रतिष्ठानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा देते है. कानून और न्याय व्यवस्था के इसी सड़ियल स्वरूप का फायदा उठाया जा रहा है. डेक्कन क्रॉनिकल को भी अनाप-शनाप लोन देने में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया शामिल है, लेकिन दोषी बैंक अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. बैंकों के शीर्ष प्रबंधन के गैर पेशेवर तौर-तरीकों का आलम यह है कि भारी ऋण-बोझ से दबे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में डेब्ट-रिकवरी के लिए डीजीएम अनुराग श्रीवास्तव को तैनात कर रखा है, जिन्हें ऋण आवंटन का कोई अनुभव नहीं है फिर वे रिकवरी कैसे कर पाएंगे. इन्हीं वजहों से बैंक का नुकसान बढ़ता जा रहा है और बैंक के बंद होने की आशंका गहरा गई है. ■

कई मीडिया संस्थानों में लगा है घोटालेबाजों का पैसा

शारदा चिटफंड घोटाले ने मीडिया संस्थानों के पीछे लगे बेजा धन के हथकंडों या कहें बेजा धन और बेजा धंधों को बचाने के लिए मीडिया संस्थान खड़ा करने की करतूतों का भी खुलासा किया है. शारदा चिटफंड कंपनी के मालिक सुदीप्तो सेन ने सीबीआई के सामने यह कबूल किया है कि उसने अखबार और न्यूज चैनल में भारी पूंजी निवेश कर रखा है. बांग्ला अखबार प्रतिदिन के मालिक और तृणमूल सांसद सृंजय बोस के प्रभाव में सुदीप्तो सेन ने 30 करोड़ रुपये में चैनल 10 नाम से एक न्यूज चैनल खरीदा था. प्रतिदिन अखबार इस न्यूज चैनल की सहयोगी संस्था के रूप में काम कर रहा था. 15 लाख रुपये मासिक वेतन पर टीवी चैनल के सीईओ पद पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद कुणाल घोष को बिठाया गया था. 20 लाख रुपये महीने के करार पर मिथुन चक्रवर्ती को चैनल का ब्रैंड अंबैसडर बनाया गया था. समाजसेवा के विभिन्न कार्यों का हवाला देकर कुणाल घोष को डेढ़ लाख रुपये माहवार अलग से दिए जाते थे. उसके चलने के लिए कीमती गाड़ी, पेट्रोल और ड्राइवर का वेतन भी शारदा समूह ही देता था. वाम मोर्चा के शासनकाल में ही सुदीप्तो सेन ने मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा था. बांग्ला अखबार सकालबेला, एखन समय, अंग्रेजी अखबार द बंगाल पोस्ट, उर्दू अखबार कलम और आजाद हिंद व हिंदी अखबार प्रभात वार्ता शारदा के पैसे से ही शुरू हुआ था. सुदीप्तो ने कई टीवी चैनलों का नेटवर्क भी खरीद रखा था. असम में तरुण गोगोई मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों ने स्थानीय अखबार और टीवी चैनल में हिस्सेदारी में शारदा समूह की मदद की. पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह और उनकी पत्नी मनोरंजना सिंह के जरिए भी पूर्वोत्तर भारत में टीवी चैनल खोले जाने का खुलासा हुआ. इसी सिलसिले में मतंग सिंह और मनोरंजना सिंह तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम और सुदीप्तो सेन की मुलाकात में माध्यम बनीं. नलिनी चिदंबरन के दबाव में ही मनोरंजना सिंह के चैनल के लिए सुदीप्तो ने करोड़ों रुपये दिए थे. इसी तरह शारदा प्रकरण से जुड़े तृणमूल सांसद केडी सिंह ने अपना पैसा मीडिया में लगाया. तहलका मैगजिन में केडी सिंह का पैसा इतना लगा कि उसका स्वामित्व भी केडी सिंह के ही हाथ में आ गया. लाखों रुपये नगद के साथ दिल्ली हवाई अड्डे पर पकड़े जा चुके रिपब्लिक ऑफ चिकन चेन के अलावा एलकेमिस्ट जैसी विवादास्पद कंपनियों के मालिक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसद केडी सिंह तहलका के मालिक बनते ही मीडिया की सुर्खियों में आ गए. हालांकि कागजी तौर पर तहलका का चेयरमैन केडी सिंह के बेटे करनदीप सिंह को दिखाया गया है. हैदराबाद के प्रमुख अखबार प्रतिष्ठान डेक्कन क्रॉनिकल पर फिलहाल यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के करोड़ों का लोन लेकर गायब होने का आरोप है, लेकिन सीबीआई सूत्र बताते हैं कि इस मीडिया संस्थान पर भी शारदा चिटफंड स्कैम के छींटे पड़ने की संभावना है. ■

शारदा चिटफंड घोटाले में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की संलिप्तता भी सीबीआई की जांच के घेरे में है. इसके सूत्र उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी जुड़ते हैं. सीबीआई ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के जिन अफसरों से कोलकाता में पूछताछ की थी, उनमें से कई अधिकारी लखनऊ से ही स्थानांतरित होकर गए हैं. बैंक की बहुत सारी संदिग्ध गतिविधियां सीएमडी अर्चना भार्गव के कार्यकाल में हुईं. लखनऊ और कोलकाता इन गतिविधियों के केंद्र में रहा और बैंक के अरबों रुपये डुबो कर अर्चना भार्गव ने स्वैच्छिक अवकाश लेकर नौकरी छोड़ दी.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 06 अंक 52
दिल्ली, 02 मार्च-08 मार्च 2015
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

महत्वपूर्ण चीन

दिलीप चेरियन

चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के एजेंडे पर बहुत महत्वपूर्ण है. मोदी ने पिछले साल सितंबर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी की और अब फिर से वे मई में चीन यात्रा के लिए तैयारी कर रहे है. इस बीच उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल दिल्ली और बीजिंग की यात्रा लगातार कर रहे है. डोभाल वहां अन्य बातों के अलावा चीनी अधिकारियों से विवादास्पद सीमा मुद्दे पर बातचीत में व्यस्त है. अब, कथित तौर पर, खुफिया ब्यूरो (आईबी) ने डोभाल के पर्यवेक्षण के तहत सीधे एक नया और अलग चीन डेस्क बनाया है. इसे एक संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी हेड करेन्गे. कईयों के लिए यह खबर किसी आश्चर्य के रूप में सामने आया क्योंकि अभी तक चीन के बारे में जानकारी एकत्र करने का काम आमतौर पर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) करता रहा है. लेकिन मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से इस काम को शीर्ष प्राथमिकता पर रखा गया था. अब तक चीन को भारतीय खुफिया तंत्र में दूसरे देशों के साथ ही रखा गया था. कहा जा रहा है कि पूर्व आईबी प्रमुख एसए इब्राहिम ने यह विचार दिया था. ■

संजीव चतुर्वेदी की मुश्किलें

हरियाणा काडर के भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को अब तक विभिन्न सरकारों द्वारा इधर से उधर घुमाया गया है. हरियाणा में कांग्रेस सरकार द्वारा उन्हें कई बार परेशान किया गया. उसके बाद उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद से मोदी सरकार द्वारा हटाया गया. इससे एक राजनीतिक तूफान भी आया. अब लगता है कि इस अधिकारी को कोई ऐसा मिल गया है, जो वास्तव में उसे अपने साथ रखना चाहता है. खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, संजीव चतुर्वेदी को दिल्ली की एंटी करप्शन ब्यूरो का मुखिया बनाना चाहते है. सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल ने पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिख कर चतुर्वेदी को उनके वर्तमान कर्तव्य से मुक्त कर के दिल्ली भेजने के लिए कहा है. लेकिन, पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह इतना आसान भी नहीं है. इसके लिए चतुर्वेदी को स्वास्थ्य मंत्रालय (अपनी पिछली पोस्टिंग) और केंद्रीय सतर्कता आयोग से क्लियरेंस लेनी होगी. बाबू के प्रति मोदी सरकार का जो रवैया है, उससे यह सब कहना जितना आसान लगता है, वास्तव में होना उतना ही मुश्किल है. ■

अखिलेश, व्हाट्स एप्प और भ्रष्ट बाबू

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के लिए एक आश्चर्यजनक हथियार है. यह व्हाट्स एप्प है. संदेश और वीडियो साझा करने के लिए एक लोकप्रिय सेलफोन एप्प. वार्षिक आईएएस वीक के अवसर पर अधिकारियों को संबोधित करते हुए यादव ने यह कह कर बाबुओं को चौंका दिया कि रिश्वत लेते हुए एक वरिष्ठ बाबू का वीडियो उनके पास है. लेकिन उन्होंने उस बाबू का नाम नहीं लिया. यादव ने कहा कि इस वीडियो को उन्होंने अपने व्हाट्स एप्प पर सुरक्षित रख लिया है और इसे राज्य के मुख्य सचिव आलोक रंजन को भी दिखाया गया था. यादव ने इस मुद्दे पर आगे तो कुछ नहीं कहा लेकिन स्पष्ट रूप से बाबुओं को परेशान छोड़ दिया. जाहिर है, यादव 2017 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए अपने प्रशासन में भ्रष्ट बाबुओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिखना चाहते है. अब, बाबू और बाबू मामलों को देखने वाले लोग, मुख्यमंत्री के कब्जे वाली वीडियो में दिख रहे कथित बाबू की पहचान सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं. यादव ने यह नहीं बताया है कि वे या उनके मुख्य सचिव ने दोषी के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? ■

dilipcherian@gmail.com

साउथ ब्लॉक

राजेश की जगह राजेश

मणिपुर-त्रिपुरा कैडर व 1988 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश कुमार आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव पद के लिए एक मजबूत दावेदार है. अभी वे अपने मूल कैडर में कार्यरत है. वे हरियाणा कैडर व 1988 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर की जगह ले सकते है.

मोहन लाल बनेंगे निदेशक

भारतीय वन सेवा के 1993 बैच के अधिकारी मोहन लाल पशुपालन, डेयरी व मत्स्य विभाग के नए निदेशक होंगे.

बेचैन बाबू

कई वरिष्ठ बाबू आजकल बेचैन दिख रहे है. वजह, भारत सरकार कई खाली पदों पर सचिवों की नियुक्ति करने जा रही है. यह उम्मीद की जा रही है कि कई शीर्ष अधिकारियों को इधर से उधर किया जा सकता है. यह भी अफवाह है कि एक शीर्ष बाबू को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है.

प्रधान एनडीएमए के सलाहकार

बिहार कैडर व 1987 बैच के आईएएस अधिकारी बिंबधर प्रधान को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का सलाहकार नियुक्त किया जा सकता है. एनडीएमए, गृह मंत्रालय के अधीन आता है. प्रधान उत्तर प्रदेश कैडर व 1985 बैच की आईएएस अधिकारी अनिता भटनागर की जगह नियुक्त होंगे.

कौन बनेगा केवीआईसी का सीईओ

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के अधीन खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग (केवीआईसी) का अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने के लिए कम से कम छह अधिकारी अभी रेस में शामिल है. इनके नाम है, एमपी कैडर व 1983 बैच के आईएएस अधिकारी एम के गोयल, राजस्थान कैडर व 1985 बैच के आईएएस अधिकारी मधुकर गुप्ता, 1983 बैच के आईईएस अधिकारी अरूण कुमार झा, एमपी कैडर व 1989 बैच के आईएएफएस अधिकारी प्रशांत यादव, 1991 बैच के आईआरएस अधिकारी ओपी शर्मा और 1991 बैच के ही आईआरएस अधिकारी कृष्ण कुमार व्यास. ■

शेखर गुप्ता इंडिया टुडे के राष्ट्र हित नामक कॉलम के आख़िरी हिस्से पुनश्च में लिखते हैं कि 27 साल गुज़र चुके हैं. मैं इलाहाबाद की अपनी रिपोर्टर डायरी से एक अंश ज़ाहिर कर ही सकता हूं. वीपी सिंह ने चुनावों में साफ–सुथरी फंडिंग और कम से कम ख़र्च करने पर ज़ोर दिया था. मोटरसाइकल पर प्रचार करना उनका प्रिय शगल था. एक सुबह, जब वे रणनीति बनाने में लगे थे तो खादी पहने, जनसत्ता के संपादक प्रभाष जोशी अंदर आए. उनके पास एक सूटकेस था जिसमें साढ़े सात लाख रुपये नगद थे. उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल ने प्रचार अभियान के लिए यह योगदान भेजा है. वीपी सिंह गुस्से से बौखला गए, यह पैसा मैं कैसे ले सकता हूं. मेरा पूरा प्रचार इस तरह की राजनीति के खिलाफ है.

स्व. प्रभाष जोशी को ज़लील मत कीजिए शेखर गुप्ता जी

स्वर्गीय प्रभाष जोशी के जीते जी उनकी नैतिकता, सादगी और दक्षता पर किसी ने उंगली नहीं उठाई. उनकी मौत के बाद उन पर कीचड़ उछालना एक तो शर्मनाक है और यह काम घिनौना हो जाता है, जब कोई शख्स इसके लिए झूठ बोलता हो. अगर कीचड़ उछालने वाला सहयोगी और सहकर्मी रहा हो तो यह नीचता की श्रेणी में आ जाता है. वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने स्वर्गीय प्रभाष जोशी की नैतिकता और सादगी का माखौल उड़ाया है. चौथी दुनिया की तहक़ीक़ात से यह साबित होता है कि शेखर गुप्ता द्वारा उद्धृत घटना झूठी है. शेखर गुप्ता द्वारा अंकित सारे गवाहों ने उनकी रिपोर्ट को झूठा और बकवास बताया है.

सभी फोटो– *प्रभात पाण्डेय*

मनीष कुमार

स्वर्गीय प्रभाष जोशी हिंदी पत्रकारिता के सिरमौर थे. उनकी मौत के बाद उन्हें राजनीतिक दलों का दलाल साबित करने की साजिश हो रही है. इंडिया टुडे जैसी विश्वसनीय पत्रिका ने प्रभाष जोशी को नेताओं के बीच रुपये से भरा सूटकेस ले जाने वाला घोषित कर दिया है. यह कोई भूल नहीं है. यह किसी अनुभवहीन पत्रकार की करतूत नहीं है. यह काम अंग्रेजी के वरिष्ठ संपादक शेखर गुप्ता की कलम से हुआ है. प्रभाष जोशी पर आरोप यह है कि उन्होंने हरियाणा के किसान नेता स्वर्गीय चौधरी देवी लाल का रुपये से भरा सूटकेस लेकर देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वी.पी. सिंह के पास पहुंचाया था. शेखर गुप्ता ने अपने लेख के जरिए प्रभाष जोशी और वी. पी. सिंह के व्यक्तित्व पर कालिख पोता है. समस्या ये है कि इस कहानी के तीन किरदार हैं. प्रभाष जोशी, वी.पी. सिंह और चौधरी देवी लाल. तीनों के तीनों स्वर्गीय हैं. इंडिया टुडे में छपे झूठ को चैलेंज करने वाले आज जिंदा नहीं है. हो सकता है कि शेखर गुप्ता ने शायद ये सोचा होगा कि चूंकि तीनों अपने आप को डिफेंड करने के लिए जिंदा नहीं है इसलिए कुछ भी कहानी बना कर सनसनी फैलाकर नाम कमाया जा सकता है. प्रभाष जोशी को कलंकित कर दिया गया लेकिन पत्रकारिता–जगत चुप है. किसी ने इस झूठ पर सवाल नहीं उठाया. क्या पत्रकारों, खासकर हिंदी पत्रकारों, ने इंडिया टुडे पढ़ना बंद कर दिया है या फिर इस ग्रुप और शेखर गुप्ता जैसे ताकतवर पत्रकार के झूठ के ख़िलाफ आवाज उठाने की किसी की हिम्मत नहीं बची. विचित्र स्थिति है. पत्रकारिता के शीर्ष पर रहने वाले महान–महान संपादक ही अगर सनसनी फैलाने के लिए झूठी रिपोर्ट लिखने लगें तो यह मान लेना चाहिए कि देश की पत्रकारिता आधारभूत रूप से कलंकित हो चुकी है.

पहले ये देखते हैं कि शेखर गुप्ता ने लिखा क्या? शेखर गुप्ता इंडिया टुडे राष्ट्र हित नामक कॉलम लिखते हैं. 18 फरवरी के अंक में उन्होंने इस घटना का वर्णन किया है. लेख के आख़िरी हिस्से पुनश्च में वो लिखते हैं कि 27 साल गुज़र चुके हैं. मैं इलाहाबाद की अपनी रिपोर्टर डायरी से एक अंश ज़ाहिर कर ही सकता हूं. वीपी सिंह ने चुनावों में साफ–सुथरी फंडिंग और कम से कम ख़र्च करने पर ज़ोर दिया था. मोटरसाइकल पर प्रचार करना उनका प्रिय शगल था. एक सुबह, जब वे रणनीति बनाने में लगे थे तो खादी पहने, जनसत्ता के संपादक प्रभाष जोशी अंदर आए. उनके पास एक सूटकेस था जिसमें साढ़े सात लाख रुपये नगद थे. उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल ने प्रचार अभियान के लिए यह योगदान भेजा है. वीपी सिंह गुस्से से बौखला गए, यह पैसा मैं कैसे ले सकता हूं. मेरा पूरा प्रचार इस तरह की राजनीति के खिलाफ है. जोशी हंसे और वीपी सिंह को वह कहा जो देवीलाल ने कहा था–राजा साहब (वीपी सिंह) को कह देना कि प्रचार के लिए पेट्रोल पर चलने वाले वाहनों की जरूरत होती है, जो पैसे से आते हैं. वह वाहन हवा–पानी पर चलना शुरू कर देंगे तो पैसे की जरूरत नहीं रहेगी. तब तक चुप रहें और जो मिल रहा है, उससे काम चलाएं.

इसके बाद, शेखर गुप्ता आगे लिखते हैं संयत व खामोश वीपी सिंह ने फिर वही किया. इसलिए हास्यास्पद दो करोड़ रुपये के योगदान पर आम आदमी पार्टी की मौजूदा शर्मिंदगी से तुलना कोई संयोगवश नहीं है. उस 1988 की कहानी का कोई गवाह है? कई अन्य रिपोर्टर (मेरे अलावा यानि शेखर गुप्ता के अलावा) लेकिन उनका नाम लेना मेरे लिए ठीक न होगा. उनके कुछ पत्रकार–रणनीतिकारों के बारे में भी मैं ज्यादा से ज्यादा केवल इतना कहूंगा कि उनमें से एक इस साल के पद्म पुरस्कारों की सूची में शामिल है.

इस कहानी को अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो शेखर गुप्ता जो कह रहे हैं उससे यही प्रतीत होता है कि जब ये घटना हुई उस वक्त वीपी सिंह के साथ शेखर गुप्ता के साथ–साथ कई और पत्रकार मौजूद थे. वो उन्हें वीपी सिंह के पत्रकार–रणनीतिकार बताते हैं. सबके सामने खादी के कपड़े पहने प्रभाष जोशी वहां आते हैं और सबके सामने ही वीपी सिंह को सूटकेस देते हैं व बिना किसी झिझक के कहते हैं कि ये सूटकेस चौधरी देवी लाल ने भिजवाया है. मतलब यह कि प्रभाष जोशी ने सबके सामने सूटकेस दिया और वहां बैठे सारे लोगों को बताया भी कि इस सूटकेस में साढ़े सात लाख रुपये हैं. राजनीतिक दलों के नोटों से भरे सूटकेस को पहुंचाने का काम कोई अच्छी बात तो है नहीं. यह एक अनैतिक काम है. साधारण सा व्यक्ति भी यह काम सार्वजनिक नहीं करेगा. सार्वजनिक रूप से सूटकेस को देना और पूरी डायलॉगबाजी तो कोई पेशेवर दलाल ही कर सकता है. पत्रकारों की मौजूदगी में तो पेशेवर राजनीतिक दलाल भी एक ठिठक जाएगा. ऐसा करने की हिम्मत नहीं होगी. यह काम तो वही कर सकता है जिसके लिए यह काम आम बात है. इस बिंदू को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस अंदाज में शेखर गुप्ता ने इस घटना का सजीव वर्णन किया है, उसमें यह नहीं बताया गया है कि जब वो आए तो लोगों को देखकर थोड़ा ठिठके या परेशान हुए. इसलिए यह कहा जा सकता है कि अपने लेख में शेखर गुप्ता ने इसे ऐसा रंग देने की कोशिश की है कि जैसे प्रभाष जोशी राजनीतिक दलों के लिए पैसे लेने–देने का काम करते थे. यह बात इसलिए भी कहा जा सकती है क्योंकि शेखर गुप्ता ने लिखा कि सूटकेस में साढ़े सात लाख रुपये नगद थे. क्या सबके सामने प्रभाष जोशी ने सूटकेस खोल कर दिखाया या गिनती की या फिर एक पेशेवर की तरह सबके सामने सूटकेस के अंदर की सारी डिटेल सबके सामने दे दी और जब वीपी सिंह गुस्से से बौखला गए तब प्रभाष जोशी हंसकर उन्हें समझाने लग गए. पूरी घटना को हास्यास्पद रूप में पेश करने के लिए शेखर गुप्ता ने बताया कि वीपी सिंह ने पहले गुस्सा दिखाया लेकिन फिर भी पैसे रख लिए. ये तो व्यवहारिक बुद्धि की बात है कि क्या प्रभाष जोशी जैसी शख्सियत का व्यक्ति किसी नेता का नोटों से भरा सूटकेस किसी दूसरे नेता के पास ले जाने का काम कर सकता है? हक़ीक़त यह है कि दुराभाव से ग्रसित होकर इस लेख के जरिए शेखर गुप्ता ने प्रभाष जोशी जी पर कीचड़ उछाला है साथ ही वीपी सिंह को भी बदनाम करने की कोशिश की.

इस घटना की सच्चाई का पता कभी नहीं चलेगा. इस कहानी के सारे किरदार अब हमारे साथ नहीं है. लेकिन शेखर गुप्ता ने अपने लेख में एक गलती कर दी. एक काल्पनिक घटना को विश्वसनीय बनाने के लिए शेखर गुप्ता ने सुबूत के तौर पर कुछ लोगों की ओर इशारा कर दिया. उन्होंने लिखा कि उस वक्त उनके अलावा कई अन्य रिपोर्टर भी मौजूद थे. हालांकि उनका नाम तो शेखर गुप्ता ने नहीं बताया लेकिन उन्हें वीपी सिंह का पत्रकार–सलाहकार की संज्ञा देकर एक परोक्ष संकेत जरूर दिया. उन्होंने लिखा कि इस घटना के गवाह में से एक इस साल के पद्म पुरस्कारों की सूची में शामिल है.

यहीं से इस लेख की सच्चाई की तहक़ीक़ात शुरू होती है. इस साल के पद्म पुरस्कारों में तीन पत्रकारों के नाम हैं: राम बहादुर राय, रजत शर्मा और स्वपनदास गुप्ता. मतलब यह कि शेखर गुप्ता के लेख के मुताबिक इन्हीं तीनों नामों में से कोई एक उस घटना के दौरान मौजूद था. चौथी दुनिया ने इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा से संपर्क साधा. उनसे यह पूछा कि क्या आप 1988 के चुनाव के दौरान इलाहाबाद में मौजूद थे और क्या आपके सामने प्रभाष जोशी जी ने वीपी सिंह को रुपये से भरा एक सूटकेस दिया था. उनका कहना साफ था कि उन्हें इस घटना के बारे कोई जानकारी नहीं है क्योंकि 1988 के समय तक तो वो वीपी सिंह से कभी मिले ही नहीं थे. शेखर गुप्ता के पहले गवाह ने इस घटना की गवाही नहीं दी. चौथी दुनिया ने पद्म पुरस्कार की लिस्ट में दर्ज दूसरे पत्रकार स्वपनदास गुप्ता से बात की. इस घटना के संदर्भ में उनसे भी यही सवाल पूछा गया. सवाल खत्म होते ही उन्होंने इस पूरी कहानी को बकवास बता दिया.

शेखर गुप्ता के गवाहों की लिस्ट में बचा एक नाम राम बहादुर राय का है. चौथी दुनिया ने जब उनसे संपर्क साधा. उन्होंने भी इस घटना को ही नकार दिया. उन्होंने बताया कि वो तो इलाहाबाद में थे ही नहीं. वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय ने कहा शेखर गुप्ता के लिखे को मुझसे जोड़ दिया गया है. कई पत्रकार मित्रों ने यही समझा. उन्होंने बताया कि लगता है, आपका ही परोक्ष उल्लेख है. शेखर गुप्ता के कॉलम को पढ़ इससे पहले ही मुझे यह बात बताई गई. जिनका–जिनका फोन आया, उनसे मैंने कहा कि मैं 1988 के उस इलाहाबाद उपचुनाव में नहीं जा सका था. दो कारण थे. पहला यह कि नवभारत टाइम्स के प्रबंधन का मुझे न भेजने का निर्णय था. दूसरा कारण पारिवारिक था. जब मुझे प्रबंधन के निर्णय की सूचना दी गई तो मैंने सोचा और फिर वहां न जाने का विचार पक्का किया. मेरी सोच जो तब थी वही आज भी है. राजनीतिक काम–काज छोड़कर पत्रकारिता में आया था. अख़बार के निर्णय को न मानकर अगर इलाहाबाद जाता तो वह पत्रकारिता के विपरीत होता और राजनीतिक कार्यकर्ता के अनुरूप मेरा वह आचरण माना जाता. जो मैं नहीं चाहता था. विश्वनाथ प्रताप सिंह की राजनीति का मैं प्रशंसक था और आज भी हूं. मैं मानता हूं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपनी राजनीति से समाज सुधार को जो अंजाम दिया वैसा उदाहरण खोजना मुश्किल है. लेकिन उनका प्रशंसक होना एक बात है और पत्रकारिता का फ़र्ज निभाना बिल्कुल दूसरी बात है. मैं नवभारत टाइम्स में तब विशेष संवाददाता था. अख़बार ने जो फैसला किया, उसे मानकर इलाहाबाद नहीं गया. लेकिन बनारस के कई मित्र वहां पहुंचे थे जो प्रोफेसर थे. उनसे चुनाव के उतार–चढ़ाव की जानकारी मिलती रहती थी.

मतलब यह कि अगर राम बहादुर राय इलाहाबाद में मौजूद ही नहीं थे तो वो इस घटना का साक्ष्य नहीं हो सकते. दरअसल, यहां मामला ही दूसरा है. हमारी तहक़ीक़ात से पता चला कि इस चुनाव के दौरान प्रभाष जोशी जी इलाहाबाद गए ही नहीं. उस वक्त हेमंत शर्मा जी को जनसत्ता के संवाददाता के रूप में इलाहाबाद भेजा गया. हेमंत जी इस वक्त इंडिया टीवी से जुड़े हैं. वो चुनाव के दौरान 25 दिनों तक इलाहाबाद में रहे. उनका कहना है कि 1988 के चुनाव के दौरान जनसत्ता के संपादक स्वर्गीय प्रभाष जोशी जी इलाहाबाद आए ही नहीं. सूटकेस और रुपये की बात ही दूर है. शेखर गुप्ता इलाहाबाद में थे. वो खुद को इस घटना का साक्ष्य भी बता रहे हैं. वो ये भी कह रहे हैं जब यह घटना घटी तो वहां पत्रकार भी मौजूद थे. शेखर गुप्ता की मानें तो इलाहाबाद में मौजूद दूसरे सभी पत्रकारों को प्रभाष जोशी के बारे में पता था सिर्फ जनसत्ता के संवाददता को छोड़ कर. यह कैसे हो सकता है कि संपादक शहर में हों और संवाददाता को पता न हो. जबकि जो लोग जनसत्ता या प्रभाष जी को नजदीक से जानते हैं वो इस बात को जानते हैं प्रभाष जी के साथ हेमंत जी की घनिष्टता आखिरी वक्त तक रही. इंडिया टुडे में छपा शेखर गुप्ता का लेख हर हिसाब से झूठा साबित हो रहा है.

अब तो बस यही बच गया है कि शेखर गुप्ता को वीपी सिंह के पत्रकार–रणनीतिकारों का नाम बताना चाहिए जो इस घटना के गवाह थे. अगर शेखर गुप्ता इस घटना के गवाहों को पेश नहीं कर सकते तो इसका मतलब साफ है कि उन्होंने न सिर्फ पत्रकारिकता को कलंकित किया बल्कि स्वर्गीय प्रभाष जोशी और स्वर्गीय वीपी सिंह की छवि पर कीचड़ उछालने का काम किया है. अगर गवाह या सुबूत पेश नहीं किया जाता है तो इंडिया टुडे को माफी मांगनी चाहिए. शेखर गुप्ता से तो यह उम्मीद भी नहीं की जा सकती है. पिछले कुछ सालों में शेखर गुप्ता संपादक के रूप में कई गूफ–अप कर चुके हैं. भारतीय सेना और थलसेना अध्यक्ष के खिलाफ मुहिम चलाई थी. हथियार के सौदागरों और यूपीए सरकार के मंत्रियों के पक्ष में कहानियां गढ़ने का भी आरोप लगा. बाबा रामदेव के हवाले से इबोला वायरस का इलाज भी ढूंढ निकाला. अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का सार्वजनिक रूप से विरोध किया. टीवी चैनलों पर वो किसी कांग्रेसी कैंपेनर की तरह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कैंपेन करते नजर आए. वैसे, हर पत्रकार को यह आजादी है कि वो अपने हिसाब से किसी भी विचार या संगठन का विरोध या समर्थन कर सकता है लेकिन उसका आधार झूठ या मिथ्या नहीं होना चाहिए. पत्रकारिता जगत में शेखर गुप्ता की करतूतों पर खामोशी इस बात का संकेत है कि अगर आप बड़े बड़े उद्योगपतियों और नेताओं के नजदीकी पत्रकार हैं तो आपको झूठ बोलने और सनसनी फैलानी की खुली आजादी है.■

अब तो बस यही बच गया है कि शेखर गुप्ता को वीपी सिंह के पत्रकार–रणनीतिकारों का नाम बताना चाहिए जो इस घटना के गवाह थे. अगर शेखर गुप्ता इस घटना के गवाहों को पेश नहीं कर सकते तो इसका मतलब साफ है कि उन्होंने न सिर्फ पत्रकारिकता को कलंकित किया बल्कि स्वर्गीय प्रभाष जोशी और स्वर्गीय वीपी सिंह की छवि पर कीचड़ उछालने का काम किया है. अगर गवाह या सुबूत पेश नहीं किया जाता है तो इंडिया टुडे को माफी मांगनी चाहिए. शेखर गुप्ता से तो यह उम्मीद भी नहीं की जा सकती है. पिछले कुछ सालों में शेखर गुप्ता संपादक के रूप में कई गूफ–अप कर चुके हैं.

(पेज 9 पर –संपादकीय लेख जब तोप मुकाबिल हो में इस विषय पर संतोष भारतीय जी ने कुछ जबरदस्त खुलासे किए हैं साथ ही शेखर गुप्ता की पत्रकारिता का विश्लेषण किया.. जरूर पढ़ें)

manishbph244@gmail.com

> इधर खबर आ रही है कि जीतन राम मांझी नई पार्टी लांच करने वाले है और पूरे बिहार में घूमकर अपनी पीड़ा सुनाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है. लेकिन सवाल है कि क्या मांझी अकेले दम पर यह सब करने में सफल हो सकेंगे या पर्दे के पीछे से भाजपा उन्हें नीतीश कुमार के खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश रच रही है? जाहिर है, बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के शासन में ही पहली बार विकास शब्द को जमीन पर उतरते देखा है. ऐसे में जीतन राम मांझी के आठ महीने के कार्यकाल में कानून–व्यवस्था की बिगड़ी सूरतेहाल को दुरुस्त करना या कुल मिला कर कहें तो आगे आने वाले समय में अपने सुशासन को पटरी पर लाना नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा चैलेन्ज होगा.

बिहार में फिर से नीतीश राज

अब आगामी चुनाव से पहले नीतीश कुमार को लालू प्रसाद के साथ एक मजबूत गठबंधन बना कर इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग करनी होगी जिससे कि मौजूदा प्रकरण (मांझी के इस्तीफे के बाद से महादलित मतदाता के खिसकने की बात) से हुए संभावित नुकसान की भरपाई की जा सके. नीतीश कुमार के लिए अपनी नई सरकार का गठन और इसे चुनाव तक चलाना भी एक बड़ी चुनौती होगी. अपने सहयोगी दल राजद और कांग्रेस को संतुष्ट करना भी नीतीश कुमार के लिए एक चुनौती होगी. जीतन राम मांझी ने पिछले कुछ दिनों में जो बिना सोचे-समझे धड़ाधड़ फैसले लिए है, जैसे कृषि कार्य हेतु भूमि क्रय करके गरीबों को भूमि की व्यवस्था, पुलिस कर्मियों को 12 महीने के बदले 13 महीने का वेतन, निजी उच्च विद्यालयों के अधिग्रहण की नीति की सैद्धांतिक स्वीकृति आदि. जाहिर है, ऐसे निर्णयों की समीक्षा भी करने की जरूरत है.

सरोज सिंह

लगभग नौ महीने पहले की बात है. नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी ली और सारे कयासों को झूठलाते हुए महादलित समाज से आने वाले जीतनराम मांझी को अपनी कुर्सी पर बैठा दिया. सबको चौंकाने वाली इस घटना से नीतीश कुमार की इमेज एक ऐसे राजनेता की बनी जिसने लोकतंत्र में नैतिकता को जिंदा रखने का साहस दिखाया. एक महादलित को अपनी कुर्सी सौंपकर नीतीश उस समय समाज के अंतिम पायदान पर जीवन बसर करने वाले बिहार के लगभग 20 से 22 फीसदी महादलित लोगों के महानायक के तौर पर उभरे. जीतन राम मांझी को आगे कर नीतीश कुमार ने ऐसा दांव खेला कि उनके विरोधी चारो खाने चित हो गए. नीतीश कुमार इसके बाद अपनी पार्टी को संगठित करने में लग गए और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ मोर्चा बनाने को प्राथमिकता देने लगे. सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन सत्ता की राजनीति यहां ऐसी उलझी कि शुरू में भाजपा से समर्थन मिलने की उम्मीद के बाद भी अंत में जीतन राम मांझी को इस्तीफा देना पड़ा. अब बात यहां से शुरू की जा सकती है कि इस पूरे प्रकरण में नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी ने क्या खोया और क्या पाया? 2010 में प्रचंड बहुमत के साथ दूसरी बार सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार के लिए यह पूरा घटनाक्रम चुनौती भरा रहा. उन्होंने खुद यह सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाकर मैंने गलती की. अब श्री मांझी के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने फिर से अपनी सरकार को दोबारा हासिल कर लिया है. यह नीतीश कुमार को भी पता था कि अपनी सदस्यता खोकर थोक में विधायक जीतन राम मांझी के समर्थन का दुस्साहस नहीं करेंगे. डर बस केवल इतना ही था कि कहीं सहयोगी दलों में बड़ी टूट न हो जाए. 19 फरवरी की रात तक ऐसा नहीं हुआ और देर रात ही यह मौटे तौर पर लग गया था कि श्री मांझी के पास इस्तीफा देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है.

अब आगामी चुनाव से पहले नीतीश कुमार को लालू प्रसाद के साथ एक मजबूत गठबंधन बना कर इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग करनी होगी जिससे कि मौजूदा प्रकरण (मांझी के इस्तीफे के बाद से महादलित मतदाता के खिसकने की बात) से हुए संभावित नुकसान की भरपाई की जा सके. नीतीश कुमार के लिए अपनी नई सरकार का गठन और इसे चुनाव तक चलाना भी एक बड़ी चुनौती होगी. अपने सहयोगी दल राजद और कांग्रेस को संतुष्ट करना भी नीतीश कुमार के लिए एक चुनौती होगी. जीतन राम मांझी ने पिछले कुछ दिनों में जो बिना सोचे–समझे धड़ाधड़ फैसले लिए है, जैसे कृषि कार्य हेतु भूमि क्रय करके गरीबों को भूमि की व्यवस्था, पुलिस कर्मियों को 12 महीने के बदले 13 महीने का वेतन, निजी उच्च विद्यालयों के अधिग्रहण की नीति की सैद्धांतिक स्वीकृति आदि. जाहिर है, ऐसे निर्णयों की समीक्षा भी करने की जरूरत है. जाहिर है, ये फैसले मांझी ने अपनी डूबती नैया को देख कर खुद के लाभ के लिए कम, आने वाली सरकार को परेशानी में डालने के लिए ज्यादा किए थे. मांझी ये जानते थे कि उनके ऐसे लोकलुभावने फैसले को पलटना किसी भी सरकार के लिए मुश्किल होगा. यह चुनावी साल है और इन फैसलों में जरा भी छेड़छाड़ चुनाव के कई गणित को बना और बिगाड़ सकता है. सरकार के खजाने पर इन फैसलों का क्या असर पड़ेगा यह तो बाद की बात है. निश्चित तौर पर ऐसे अदूरदर्शी फैसले एक अदूरदर्शी नेता ही कर सकता है. अब इन फैसलों का बिहार की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकने वाले बुरे प्रभावों से बचाने की जिम्मेदारी भी नीतीश कुमार के कंधे पर है.

इधर खबर आ रही है कि जीतन राम मांझी नई पार्टी लांच करने वाले है और पूरे बिहार में घूमकर अपनी पीड़ा सुनाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है. लेकिन सवाल है कि क्या मांझी अकेले दम पर यह सब करने में सफल हो सकेंगे या पर्दे के पीछे से भाजपा उन्हें नीतीश कुमार के खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश रच रही है? जाहिर है, बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के शासन में ही पहली बार विकास शब्द को जमीन पर उतरते देखा है. ऐसे में जीतन राम मांझी के आठ महीने के कार्यकाल में कानून–व्यवस्था की बिगड़ी सूरतेहाल को दुरुस्त करना या कुल मिला कर कहें तो आगे आने वाले समय में अपने सुशासन को पटरी पर लाना नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा चैलेन्ज होगा. सुशासन ही नीतीश कुमार की सबसे बड़ी पूंजी हैं और सबसे बड़ा चुनावी हथियार भी. महादलित मतदाता के छिटकने की तथाकथित अफवाह के बीच उन्हें अपनी सोशल इंजीनयरिंग को भी मजबूत करना होगा. लालू प्रसाद के साथ महागठबंधन बनाने की कवायद इसी की एक कड़ी है जाहिर है, रास्ते कठिनाईयों से भरे हुए है लेकिन कहते है कि कठिन रास्ते पर चल कर जो अपनी मंजिल पा लेता है वही बड़ा नेता कहलाता है. नीतीश कुमार की असली लड़ाई यही है.

घटनाक्रम

01 फरवरी: भाजपा विधानमंडल दल के नेता सुशील मोदी बोले: नीतीश समर्थक मंत्री बने हैं मांझी की राह में रोड़ा. प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय ने इन बेलगाम मंत्रियों को हटाने की नसीहत दी.

02 फरवरी: मांझी ने पथ निर्माण विभाग के कामकाज से जताई असंतुष्टि. विभागीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने चार दिन पहले अफसरों के तबादले पर जताया था विरोध. पटना में केंद्रीय मंत्री उमा भारती और मुख्यमंत्री मांझी ने एक–दूसरे की तारीफ में काढ़े कसीदे.

03 फरवरी: जदयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच अनबन की बात मानी. इससे पहले शकुनी चौधरी बोले थे : मांझी को हटाने वाला बिहार की राजनीति से मिट जाएगा.

04 फरवरी: जदयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा : मांझी को हटाना एजेंडे में नहीं. महासचिव केसी त्यागी बोले कि मुख्यमंत्री का फैसला विधायक करेंगे.

05 फरवरी: मांझी को मनाने में असफल रहे शरद ने सात फरवरी को बुलाई जदयू विधायक दल की बैठक. बैठक को अनधिकृत करार देते हुए मांझी ने खुली बगावत का किया एलान.

06 फरवरी: मांझी ने राज्यपाल से की मंत्री ललन सिंह और पीके शाही को बर्खास्त करने की सिफारिश.

07 फरवरी: शरद की मौजूदगी में नीतीश चुने गए जदयू विधानमंडल दल के नेता. मांझी द्वारा बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में विधानसभा भंग करने की अनुशंसा के लिए मांझी को अधिकृत करने के प्रस्ताव पर विरोध. नीतीश समर्थक मंत्री बैठक से उठकर चले गए. 15 मंत्रियों को बर्खास्त कर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए मांझी दिल्ली गए.

08 फरवरी: को बुलाई विधायक दल की बैठक. जदयू ने नीतीश की अगुवाई में सरकार बनाने का किया दावा. राजभवन को सौंपे गए पत्र में राजद, कांग्रेस और भाकपा के समर्थन का दावा. मांझी बोले : मैं रबर स्टांप नहीं बना, इसीलिए छटपटाने लगे नीतीश.

09 फरवरी: 130 विधायकों के साथ नीतीश पहुंचे राजभवन. जदयू ने मांझी को पार्टी से किया बाहर. राज्यपाल से मिले मांझी. दोनों पक्षों की सुनने के बाद राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी दिल्ली रवाना

10 फरवरी: दलितों को ठेकों में प्राथमिकता और गरीब सवर्णो को नौकरी में आरक्षण सहित मांझी कैबिनेट ने लोकलुभावन निर्णय लिए. मंत्रियों में विभागों का किया बंटवारा. जदयू ने विधानसभा अध्यक्ष से विपक्ष में बैठने के लिए मांगीं सीटें. नीतीश ने भाजपा पर मांझी को समर्थन देने का लगाया आरोप.

11 फरवरी: समर्थक विधायकों के साथ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने पहुंचे नीतीश. विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नीतीश को विधानमंडल में जदयू के नेता की मान्यता दिए जाने के खिलाफ मांझी समर्थक विधायक राजेश्वर राज पहुंचे हाई कोर्ट अदालत ने कहा : राज्यपाल के निर्णय तक विधानसभा अध्यक्ष के फैसले का महत्व नहीं. भाजपा ने विधानसभा भंग कराकर चुनाव मैदान में उतरने के लिए नीतीश को ललकारा. राज्यपाल ने 20 फरवरी को बहुमत साबित करने की तिथि निर्धारित की.

12 फरवरी: मांझी ने किसानों को मुफ्त बिजली देने सहित तीन लुभावनी घोषणाएं कीं. बोले : इंजीनियर और ठेकेदारों द्वारा मेरे पास भी पहुंचता है कमीशन का पैसा. नीतीश ने राज्यपाल पर हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का लगाया आरोप. मांझी खेमे की ओर से कथित तौर पर विधानसभा अध्यक्ष को गिरफ्तार करने की धमकी.

13 फरवरी: राज्यपाल ने नीतीश पर दबाव की राजनीति का लगाया आरोप. मांझी बोले : नीतीश ने मुझे कठपुतली समझकर महागलती की. सुशील मोदी बोले : जदयू की ओर से भाजपा विधायकों को दिए जा रहे दो–दो करोड़ के ऑफर. विधानसभा अध्यक्ष से विजय चौधरी ने की विधानसभा में नेता विपक्ष के पद की मांग.

14 फरवरी: नीतीश समर्थक जदयू, राजद, कांग्रेस और भाकपा ने राज्यपाल के निर्णय को असंवैधानिक और अमर्यादित करार देते हुए कहा कि राज्यपाल लठगीरी कर रहे हैं. मांझी खेमे ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा.

15 फरवरी: दिल्ली में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी से मुलाकात की. पटना में नीतीश बोले: सत्ता मिलने पर मांझी के फैसलों पर करूंगा विचार.

16 फरवरी : बहुमत साबित करने तक मांझी के नीतिगत निर्णय लेने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक. विधान पार्षद नीरज कुमार ने दायर की थी याचिका. विपक्ष के नेता पद को लेकर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई बैठक सर्वदलीय बैठक बेनतीजा.

17 फरवरी: मांझी खेमे द्वारा मुख्य सचेतक घोषित राजीव रंजन ने मांझी के पक्ष में मतदान के लिए जदयू विधायकों को जारी किया व्हिप. जदयू अध्यक्ष ने मांझी मंत्रिमंडल के सभी सात मंत्रियों को पार्टी से किया निलंबित.

18 फरवरी: मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में हाई कोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने अपने पूर्व के फैसले में संशोधन करते हुए मांझी को निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र बताया. साथ ही निर्देशित किया कि कोई भी निर्णय बहुमत साबित होने के बाद ही होगा प्रभावी.

19 फरवरी: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष से जुड़े मुद्दे पर भाजपा द्वारा दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई. जदयू के बागी विधायकों की इस याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसके तहत विधानसभा में शक्ति–परीक्षण के दौरान मतदान के अधिकार की मांग की गई है.

20 फरवरी: जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा. ■

feedback@chauthiduniya.com

> राजनीतिक रैलियों में, खासकर अगर वो किसी बड़े नेता की हों, भीड़ आना आश्चर्य की बात नहीं है. आश्चर्य की बात ये है की इस शपथ ग्रहण समारोह में आये हज़ारों लोग वहां लाए नहीं गए थे, बल्कि ख़ुद अपनी इच्छा और अपने ही संसाधन से आए थे. आमतौर पर देखा गया है किसी भी बड़ी राजनीतिक रैली में लोगों को लाने–ले जाने के लिए बस, गाड़ी आदि का इंतेज़ाम किया जाता है. पर इस कार्यक्रम में ऐसा कोई इंतेज़ाम नहीं दिखा. यहां तक कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बाहर के शहरों से आए पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए भी कोई इंतेजाम नहीं किए गए थे.

शफ़ीक़ आलम

परमाणु हादसा और मुआवजा

संसदीय कमेटी की रिपोर्ट भी अमेरिकी हित में

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के हालिया भारत दौरे पर दोनों देशों के बीच परमाणु सौदे पर सहमति बन गई. इस सौदे पर दोनों देशों के बीच कुछ बिंदुओं पर मतभेद थे. भारत की संसद ने एक कानून पारित कर दुर्घटना की स्थिति में मुआवज़े का दायित्व सप्लायर (अमेरिकी) कंपनियों के कंधे पर डाला था. लेकिन अमेरिका किसी भी तरह इस प्रावधान के अनुपालन पर राज़ी नहीं था, इसलिए दोनों देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा इस समझौते पर 2008 में हुए हस्ताक्षर के बाद भी यह सौदा अधर में लटका रहा. अब जबकि ओबामा के भारत दौरे पर दोनों देशों के बीच (ब्रेकथ्रू) सहमति बन गई है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010 के उक्त प्रावधान को कैसे परिभाषित किया गया है. इस संबंध में अभी हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा 19 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (फ्रीक्वेंट्ली आस्क्ड क्वेश्चंस) जारी करके अपना पक्ष रखने की कोशिश की गई है.

विदेश मंत्रालय द्वारा यह कहा गया है कि भारत और अमेरिका के बीच परमाणु सिविल दायित्व और 2008 में हुए 123 समझौते पर सहमति बन गई है, जिसकी वजह से भारत परमाणु संयंत्र की स्थापना और परमाणु उर्जा क्षेत्र में सहयोग और खरीद–बिक्री के लिए अमेरिका और दूसरे देशों से बातचीत कर सकता है. यहां यह भी कहा गया है कि भारत परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व (सीएनएलडी) अधिनियम, 2010 या परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व (सीएनएलडी) कानून 2011 में किसी तरह का संशोधन नहीं करेगा. गौरतलब है कि सीएनएलडी अधिनियम की धारा 17 बी के तहत सप्लायर की गलती से हुए परमाणु हादसे की स्थिति में उसे मुआवजा देने के लिए ज़िम्मेदार बनाया गया है. लेकिन मौजूदा सरकार ने सप्लायर को इस दायित्व से बाहर कर दिया है. दलील यह दी है कि सप्लायर कंपनी द्वारा घटिया सामान और उपकरणों का दायित्व सरकार सौदा तय करते समय ही निर्धारित कर लेगी. अब यह सवाल उठना लाज़मी है कि यह सब इतना सरल था तो फिर इस सौदे पर इतने लंबे गतिरोध का क्या मतलब था? क्योंकि इस पूरे सौदे पर अमेरिका की असहमति की यह सबसे बड़ी वजह थी.

चूकि फुकुशीमा परमणु हादसे के बाद यह साबित हो गया है कि परमाणु हादसे की स्थिति में खर्च इतना अधिक हो जाता है कि कोई बीमा कंपनी परमाणु संयंत्र का बीमा करने को तैयार नहीं है. विशेषज्ञों के मुताबिक संयंत्र के रख–रखाव पर भी लागत पहले के मुकाबले पांच गुना अधिक हो गई है. इसलिए कोई सप्लायर कंपनी भी किसी दूसरे देश में संयंत्र में दुर्घटना से होने वाले नुकसान का मुआवजा देने को तैयार नहीं है. साथ ही परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व पर अमेरिका की असहमति इस सौदे के आलोचकों बात को पुख्ता करती है जिसमें वे कहते हैं कि अमेरिका में परमाणु उर्जा शोध लगभग ठप पड़ गया है. अमेरिका में थ्री मॉइल आईलैंड परमाणु दुर्घटना के बाद देश में कोई नया परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं लगा है.

जिसकी वजह से अमेरिका में परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाली कंपनियां खात्मे के कगार पर पहुंच चुकी हैं. इसलिए यह सवाल उठना लाज़मी है कि क्या यह समझौता अमेरिकी कंपनियों में जान फूंकने और उन्हें दिवालिया होने से बचाने कोशिश मात्र नहीं है? जब अमरीका इस बात पर रज़ामंद नहीं है कि उसके देश की कम्पनियों सीएनएलडी की धारा 17 बी के प्रावधान के मुताबिक दुर्घटना का दायित्व उठाए तो भारत सरकार का यह दावा कि सौदा करते समय ही घटिया और खराब उपकरणों और सामान की सप्लायर से ज़मानत ले ली जायेगी संदेह पैदा करता है. सरकार की नियत पर सवाल इसलिए भी उठता है कि 2012 के अधीनस्थ कानून पर संसद की स्थाई समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई (एक्शन टेकेन) की समीक्षा के लिए गठित 2014 की स्थाई समीति ने अपनी रिपोर्ट में कुछ और सवालों को जन्म दिया है, जो साबित करते हैं कि इस सौदे से अमेरिका ही फायदे में रहा है.

चूंकि 2012 की स्थाई समिति ने सीएलएनडी कानून में परमाणु हादसे की सूरत में पीड़ितों को अग्रिम मुआवजा और न्यायिक समीक्षा का प्रावधान नहीं होने पर सवाल उठाया था और इससे सीएलएनडी कानून या अधिनियम में शामिल करने की शिफारिश की थी. लेकिन 2014 एक्शन टेकेन रिपोर्ट में स्थाई समिति ने अपने इस सिफारिश को नज़रंदाज़ करते हुए जो नतीजा निकला है वह विरोधाभास से ग्रसित है. 2012की अधीनस्थ कानून संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों का हवाला देते हुए 2014 की पीएससी कहती है कि कोई पीड़ित दावा आयुक्त (क्लेम कमीशनर) द्वारा दिए गये मुआवजे से संतुष्ट नहीं हो और इसके विरुद्ध न्यायिक समीक्षा करवाना चाहता हो तो दावा आयुक्त द्वारा आवंटित की गई रक़म को अग्रिम मुआवजा मान लिया जायेगा. ख्याल रहे कि 2012 की रिपोर्ट में सीएलएनडी अधिनियम और कानून (नियम) में न्यायिक समीक्षा के अभाव की बात की गई थी. हालांकि एक दूसरी जगह 2014 की स्थाई समिति न्यायिक समीक्षा के लिए सीएलएनडी अधिनियम और कानून के तहत प्रावधान लाने की बात करती है लेकिन समिति बाद में इस नतीजे पर पहुंचती है कि इस मामले को ज्यों का त्यों ही छोड़ दिया जाए. उसी तरह यह रिपोर्ट राइट ऑफ़ रिकोर्स के अपनी पिछली सिफारिश पर सरकार द्वारा की गई अब तक की कारवाई पर समीक्षा के बजाये इससे यहीं छोड़ने की बात करती है. 2014 की स्थायी समिति, सीएलएनडी के नियम 24, जो राईट ऑफ़ रिकोर्स को कवर करती है और जो सीएलएनडी अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों के विरुद्ध है, कार्रवाई की सिफारिश नहीं करती. जबकि समिति ने परमाणु ऊर्जा विभाग के जवाब पर आपत्ति भी जताई थी.

2014 की स्थाई समिति की रिपोर्ट की खामियों पर सवाल उठाते हुए टॉक्सिक वॉच अलायन्स के गोपाल कृष्ण कहते हैं कि सीएलएनडी कानून 2011 की अधिसूचना सीएलएनडी अधिनियम के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री के 18 नवम्बर 2011 की मुलाक़ात से पहले 11 नवंबर 2011 को जारी की गई थी. इस अधिनियम के प्रावधानों की अव–हेलना करते हुए इसे लागू करने में तकरीबन 13 महीने की देर की गई. ज़ाहिर है यह अतिरिक्त समय परमणु संयंत्र सप्लाई करने वाली कंपनियों को कानूनों को प्रभावित करने के लिए दिया गया था. इस संदर्भ में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तत्कालीन सचिव के सुजाता राव ने विज्ञान एव तकनीक और पर्यावरण और वन सम्बन्धी स्थाई समिति के समक्ष 2010 के अपने बयान में कहा था कि सीएलएनडी बिल का मसौदा तैयार करते समय इन विभागों से परामर्श नहीं किया गया था.

लिहाज़ा यह कहा जा सकता है कि 2014 की अधीनस्थ कानून संबंधी संसदीय स्थायी समिति अमेरिका के परमाणु लॉबी के प्रभाव में काम कर रही थी और ज़ाहिर तौर पर सरकार का मकसद हर कीमत पर अमेरिका और अमेरिकी कंपनियों को खुश करने का था. ऐसा लगता है कि इस रिपोर्ट को खास तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साझा बयान के लिए तैयार किया गया था.■

feedback@chauthiduniya.com

आम आदमी का शपथ ग्रहण

मोनिशा भटनागर

5 साल केजरीवाल, इस नारे से गूंजते रामलीला मैदान में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री ने 14 फरवरी 2015 को, एक बार फिर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली. प्रचंड बहुमत पाने वाले अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह को देखने मैं भी रामलीला मैदान पहुंची. अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल भी अपनी पार्टी की अल्पमत की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री की शपथ के लिए रामलीला मैदान को ही चुना था. यह ऐतिहासिक रामलीला मैदान अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन की याद दिलाता है. हालांकि आंदोलन के समय और अब में बहुत फर्क है, लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह का माहौल आंदोलन वाला ही लग रहा था. वही देशभक्ति के गीत, लोगों के हाथों में वही लहराते राष्ट्रीय ध्वज, वही इंकलाब ज़िंदाबाद, भारत माता की जय के नारे, वही उम्मीद और वही उत्साह. कुछ फर्क था तो वो था इंतज़ाम का. लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां, सुरक्षा के लिए 3000 पुलिसकर्मी और सीसीटीवी कैमरे, सजा हुआ मंच और वीआईपी एनक्लोजर भी. यह अलग बात है कि उस वीआईपी एनक्लोजर के अलावा पूरा रामलीला मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था. रामलीला मैदान में मुफ्त में आम आदमी पार्टी कोला बंट रही थी, केजरीवाल के समर्थक अजब–गजब रूप में दिखाई दे रहे थे, 5 साल केजरीवाल के नारे के बीच कहीं–कहीं 50 साल केजरीवाल और केजरीवाल फॉर पीएम के नारे भी सुनाई पड़ रहे थे.

केजरीवाल और उनके मंत्रियों के मंच पर आते ही रामलीला का यह ऐतिहासिक मैदान एक बार फिर केजरीवाल और पार्टी की जय–जयकार से गूंज उठा. केजरीवाल ने जनता को अपने भाषण से भी खुश किया. उनके भाषण में लोगों की रुचि इस बात से दिखी कि भाषण के दौरान इतनी भीड़ एकदम शांत हो उनके हर शब्द को ध्यान से सुन रही थी, और जब उन्होंने 5 साल दिल्ली में ही रहने की बात की तो पूरा रामलीला मैदान तालियों की आवाज़ से गूंज उठा.

2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में महज़ दो साल पुरानी आप पार्टी ने दिल्ली विधानसभा की 70 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज की और केंद्र में बहुमत से सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी को केवल तीन सीटें मिली. रामलीला मैदान में जनसैलाब इसी जीत का प्रतिबिंब लग रहा था. जनता के द्वारा दिलाई गयी जीत का जश्न जनता के साथ मनाने का फैसला पिछली बार की तरह लोगों को इस बार भी बहुत पसंद आया और यही शपथ ग्रहण में हज़ारों की संख्या में आकर लोगों ने साबित किया. इनमे सबसे बड़ा तबका गरीब झुग्गी–झोपड़ी और रेहड़ी–पटरी वालों का था. अरविंद केजरीवाल द्वारा बार–बार कही बात कि, मैं नहीं आप सब मुख्यमंत्री बने हैं लोगों को छू गयी. मैदान में मौजूद ज़्यादातर सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग, जिन्होंने संभवतः आप को वोट दिया होगा, मुख्यमंत्री द्वारा अपने को मुख्यमंत्री कहलाये जाने पर गौरवांवित महसूस कर रहे थे. जनता के साथ इस तरह का इमोशनल कनेक्ट बना पाने में आप पूरी तरह सफल रही है. आप की सफलता का श्रेय सिर्फ रियायती बिजली,पानी और मुफ्त वाई फाई के वादों को नहीं दिया जा सकता. शपथ ग्रहण में आई हुई जनता में एक अलग तरह की भावनात्मकता महसूस हुई. आम आदमी पार्टी की सफलता ऐतिहासिक और अकल्पनीय चुनावी नतीजे तो दर्शाते हैं ही, लेकिन उससे ज़्यादा आप की सफलता पार्टी के प्रति लोगों के मन जगे उत्साह, उम्मीद और विश्वास से झलकती है. केजरीवाल के साधारण पहनावे और बोलचाल की भाषा से एक बड़े वर्ग का जुड़ाव आम आदमी पार्टी के साथ हो गया है. इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग भी रामलीला मैदान में मौजूद थे. वह केजरीवाल की पार्टी के नाम में शामिल आम आदमी थे, जिनके चेहरों पर आप की जीत पर ख़ुशी ही ख़ुशी थी. सबसे दिलचस्प उच्च वर्ग की उपस्थिति थी. इनकी संख्या ज़रूर सबसे कम थी लेकिन दिल्ली के अमीर या संभ्रांतवादी वर्ग की इस तरह के राजनीतिक कार्यक्रम में मौजूदगी उल्लेखनीय है. वैलेंटाइन डे वाले दिन भी बड़ी संख्या में रामलीला मैदान आए नौजवान आम आदमी पार्टी के युवा वोटबैंक और युवाओं में राजनीति के प्रति बढ़ रही रूचि का प्रतीक थे. पूरा माहौल किसी त्यौहार जैसा था जिसमें शामिल हुए लोगों को जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर पहचानना मुश्किल था. समारोह में आई भीड़ और उसका उत्साह अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ऊपर आशाओं के बोझ का सूचक है.

राजनीतिक रैलियों में, खासकर अगर वो किसी बड़े नेता की हों, भीड़ आना आश्चर्य की बात नहीं है. आश्चर्य की बात ये है की इस शपथ ग्रहण समारोह में आये हज़ारों लोग वहां लाए नहीं गए थे, बल्कि ख़ुद अपनी इच्छा और अपने ही संसाधन से आए थे. आमतौर पर देखा गया है किसी भी बड़ी राजनीतिक रैली में लोगों को लाने–ले जाने के लिए बस, गाड़ी आदि का इंतेज़ाम किया जाता है. पर इस कार्यक्रम में ऐसा कोई इंतेज़ाम नहीं दिखा. यहां तक कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बाहर के शहरों से आए पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए भी कोई इंतेजाम नहीं किए गए थे. आप की ट्रेडमार्क सफ़ेद टोपी पहने वहां केवल आप वोटर और समर्थक ही नहीं थे बल्कि वे लोग भी थे जो राजनीति में हुए इस सफल प्रयोग के असर को समझना चाहते थे. इसके अलावा कई ऐसे लोग भी थे जो भारत के अलग अलग शहरों से केवल राजनीति में ऐतिहासिक कहे जाने वाले इस शपथ ग्रहण के गवाह बनने आए थे.

केजरीवाल और उनके मंत्रियों के मंच पर आते ही रामलीला का यह ऐतिहासिक मैदान एक बार फिर केजरीवाल और पार्टी की जय–जयकार से गूंज उठा. केजरीवाल ने जनता को अपने भाषण से भी खुश किया. उनके भाषण में लोगों की रुचि इस बात से दिखी कि भाषण के दौरान इतनी भीड़ एकदम शांत हो उनके हर शब्द को ध्यान से सुन रही थी, और जब उन्होंने 5 साल दिल्ली में ही रहने की बात की तो पूरा रामलीला मैदान तालियों की आवाज़ से गूंज उठा. उनके भाषण में इस तरह के बहुमत के साथ आयी जिम्मेदारी और अहंकार की संभावना का भी जिक्र था. पिछले साल की तरह इस साल भी उन्होंने भाषण का अंत गाने से किया.

जो उम्मीद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने लोगों में जगाई है, वही उम्मीदें रामलीला मैदान में मौजूद जनता के उत्साह में झलक रहीं थी. इस प्रचंड बहुमत से बनी सरकार के ऊपर बहुत लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाने की बड़ी ज़िम्मेदारी है.■

feedback@chauthiduniya.com

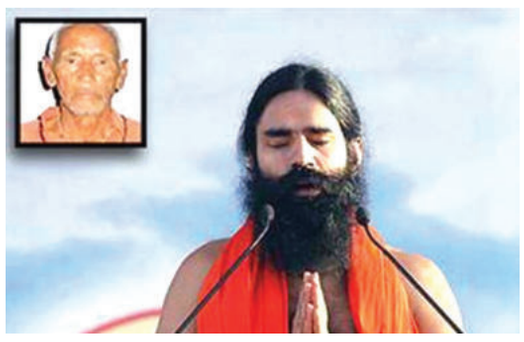

रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण ने 16 जून, 2007 को थाना कनखल में शंकर देव की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि स्वामी शंकर देव कृपालु बाग आश्रम से कहीं चले गए हैं. लंबी जांच के बावजूद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा. बाद में गुमशुदगी का मामला अपहरण में बदल दिया गया और जांच सीबीआई को सौंप दी गई. बताते हैं कि 80 वर्षीय शंकर देव 14 जुलाई, 2007 को कृपालु बाग आश्रम से नित्य की भांति सैर के लिए निकले थे. उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला. जिस दिन यह घटना घटी, उस दिन बाबा रामदेव विदेश दौरे पर थे, जबकि उनके सहयोगी बालकृष्ण भी आश्रम में नहीं थे.

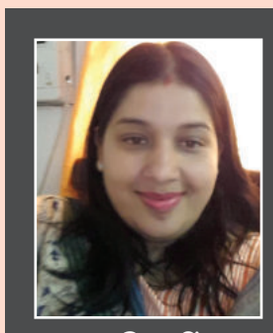
अनामिका सिंह

अनुराधा

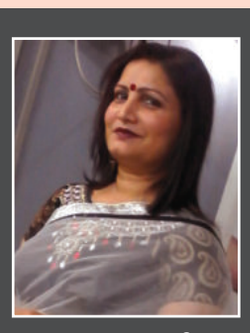
कल्पना कुमारी

मेनका सिंह

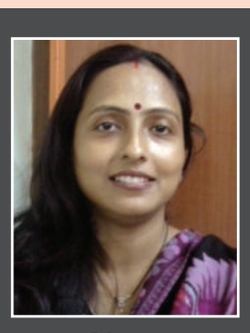
पूर्णिमा रॉय

पुष्पा चोपड़ा

सुनिता प्रकाश

महिला उद्यमिता

प्रगतिशील बिहार की ओर बढ़ते कदम

राधिका

उद्यमी वही नहीं होते हैं जो बड़ी पूंजी के साथ कोई बड़ा व्यवसाय करते हैं, छोटी पूंजी के साथ भी सार्थक काम किया जा सकता है. इस बात को बिहार की महिला उद्यमियों ने सिद्ध किया है. पांच–दस हजार की नौकरी करने वाली ये महिलाएं आज अपना उद्यम चला रही हैं और समाज की महिलाओं को रोजगार प्रदान कर रही हैं. इनके बेहतर काम ने समाज में इनको ख़ास पहचान दी है. महिला उद्यमिता को आर्थिक प्रगति का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत माना गया है. महिला उद्यमी अपने लिए और अन्य लोगों के लिए नए कार्य सृजित करती हैं और समाज को प्रबंध, संगठन एवं व्यवसायिक समस्याओं के भिन्न–भिन्न समाधान उपलब्ध कराती हैं. किंतु फिर भी उद्यमियों में उनकी संख्या काफी कम है. महिला उद्यमियों को अक्सर अपने व्यवसाय शुरू करने और उन्हें बढ़ाने में लिंग–भेद आधारित बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे – भेदभावपूर्ण संपत्ति, विवाह एवं उत्तराधिकार कानून या सांस्कृतिक परंपराएं, औपचारिक वित्त प्रणाली तक पहुंच न होना, सीमित गतिशीलता तथा सूचनाओं व नेटवर्क तक सीमित पहुंच, आदि.

बिहार महिला उद्योग संघ की प्रेसीडेंट पुष्पा चोपड़ा ने अपना रोजगार शुरू किया जो बंधनी सेंटर के नाम से चलता है. रोजगार शुरू करने के बाद उन्हें जो सबसे पहली कठिनाई से जूझना पड़ा वो थी प्रोडक्ट्स का बाजार में जगह बनाना जो कि बहुत हीं मुश्किल काम है. फिर उन्होंने 1995 में बिहार महिला उद्योग संघ की स्थापना की. इस संघ का मुख्य उद्देशय लड़कियों को आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार प्रदान करना था. उन्होंने खुल कर अपने विचार हमारे सामने रखे और कहा कि सबसे पहले बिहार में आने वाले बजट में प्रोडक्ट्स को टैक्स फ्री कर दिया जाए. पुष्पा आगे कहती हैं कि सरकार सिर्फ बातें करती है, और जब काम करने की बारी आती है तो कोई देखने भी नहीं आता है. जो भी चीजें बजट में पेश की जाती हैं वो सिर्फ किताबी बातें बन कर रह जाती हैं. हमें इसका कोई लाभ नहीं मिलता है. उनके अनुसार सबसे बड़ी दिक्कत प्रोडक्ट्स को मार्केट मिलने की है. इन सारी दिक्कतों से निजात पाने के लिए पुष्पा ने हमें कुछ और सुझाव भी दिए.

महिला उद्यमी परिवार एवं समुदायों की आर्थिक संपन्नता, ग़रीबी उन्मूलन और महिला सशक्तीकरण में विशेष रूप से अत्यंत सहयोग दे सकती हैं, और इस प्रकार से विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान कर सकती हैं.

ऐसी ही कुछ महिला उद्यमियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने दम पर एक मुकाम हासिल किया है और खुद को समाज में साबित करने की ताकत दिखाई है. और साथ ही इस पर अपनी राय भी व्यक्त की है कि बिहार में आने वाले बजट में क्या ऐसी चीजें डाली जानी चाहिए जिससे उनके काम को बढ़ावा मिले.

बिहार महिला उद्योग संघ की प्रेसीडेंट पुष्पा चोपड़ा ने अपना रोजगार शुरू किया जो बंधनी सेंटर के नाम से चलता है. रोजगार शुरू करने के बाद उन्हें जो सबसे पहली कठिनाई से जूझना पड़ा वो थी प्रोडक्ट्स का बाजार में जगह बनाना जो कि बहुत हीं मुश्किल काम है. फिर उन्होंने 1995 में बिहार महिला उद्योग संघ की स्थापना की. इस संघ का मुख्य उद्देशय लड़कियों को आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार प्रदान करना था. उन्होंने खुल कर अपने विचार हमारे सामने रखे और कहा कि सबसे पहले बिहार में आने वाले बजट में प्रोडक्ट्स को टैक्स फ्री कर दिया जाए. पुष्पा आगे कहती हैं कि सरकार सिर्फ बातें करती है, और जब काम करने की बारी आती है तो कोई देखने भी नहीं आता है. जो भी चीजें बजट में पेश की जाती हैं वो सिर्फ किताबी बातें बन कर रह जाती हैं. हमें इसका कोई लाभ नहीं मिलता है. उनके अनुसार सबसे बड़ी दिक्कत प्रोडक्ट्स को मार्केट मिलने की है. इन सारी दिक्कतों से निजात पाने के लिए पुष्पा ने हमें कुछ और सुझाव भी दिए. उनका कहना है कि बिहार में महिला उद्यमियों के लिए एक अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए. छोटे–छोटे जिले में काम कर रही महिलाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए. सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझ कर इनके लिए कुछ करना चाहिए.

इसके बाद दूसरा नाम कल्पना कुमारी का है जो अपना बुटीक चलाती हैं. इनका भागलपुरी सिल्क से लेकर मधुबनी पेंटिंग इत्यादि का काम है. उन्होंने बताया कि हर बार हमें बजट से काफी सारी उम्मीदें होती हैं लेकिन वो कुछ हद तक ही पूरी हो पाती हैं. उनका भी कहना है कि मार्केटिंग ही सबसे ज्यादा मुश्किल काम है. सामान अच्छा होता है लेकिन लोगों तक सही से नहीं पहुंचने के कारण बिक नहीं पाता है. और अगर इसमें सरकार की तरफ से मदद मिल जाए तो हमें बहुत राहत मिलेगी.

इस क्रम में तीसरा नाम दरभंगा में पिछले 24 साल से अपना ब्यूटी सैलून/पार्लर चला रहीं अनुराधा लाला का है. घर के साथ–साथ ये बाहर का काम भी बखूबी संभालती हैं. उन्होंने बताया कि सारी जरूरत की चीजें उन्हें बाहर से मंगानी पड़ती हैं. सामान लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है. और ऊपर से इतना टैक्स भरना पड़ता है. अगर इस बार आने वाले बजट में प्रोडक्ट्स को टैक्स फ्री कर दिया जाए तो बहुत मदद हो जाएगी.

ऐसे ही कुछ और नामों में अनामिका सिंह, पूर्णिमा रॉय, मेनका सिंह और सुनीता प्रकाश हैं. सब अपने–अपने फील्ड में पैर जमा चुकी हैं. लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे वो आज भी जूझ रहीं है. सुनीता प्रकाश, जिनका टेक्सटाएल डिजाईनिंग का काम हैं, बताती हैं कि महिलाओं को अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से उन्हें बहुत परेशानी होती है. अनामिका सिंह, जो अपना हॉस्पीटल चलाती हैं, का कहना है कि सबसे ज्यादा परेशानी तो हर चीज पर लग रहे टैक्स से होती है. अगर चीजें टैक्स फ्री कर दी जाएं तो सबसे ज्यादा राहत की बात होगी. इस बारे में पूर्णिमा रॉय, जिनका फ्यूजन फिएस्ता बुटीक है, आगे कहती हैं कि उद्यमियों को तो मार्केट चाहिए. प्रोडक्ट को बनाने में बहुत कॉस्टिंग लग जाती है. अगर मार्केट नहीं मिला तो हमारा काम धीरे–धीरे खत्म हो जाएगा. इसके अलावा मेनका सिंह जो 1988 से अपना ब्यूटी पॉर्लर चला रही हैं उनका कहना है कि आने वाले बजट में घरेलू चीजों के दाम कम करने चाहिए. जो भी हर दिन की जरूरत की चीजें हैं उन के दामों में कटौती करनी चाहिए. अगर इन सब चीजों के दाम कम होंगे तो इनसे बचे पैसों को हम अपने काम में लगा सकते हैं और बढ़ोतरी हासिल कर सकते हैं. अगर घर का बजट गड़बड़ होता है तो सारा बजट गड़बड़ हो जाता है. रॉ मटेरियल के बढ़ते दाम से बड़े पैमाने पर काम कर रहे लोगो को इतना फर्क नहीं पड़ता जितना छोटे पैमाने पर काम कर रहे लोगों को पड़ता है, इसलिए रॉ मटेरियल्स के दाम में कटौती होनी चाहिए.

इन सारी महिलाओं का कहना है कि बजट की बातें सिर्फ पन्नों में ही रह जाती हैं. असल जिंदगी में इसका पालन शायद ही कभी होता है. हम इतने साल से काम कर रहे हैं. हमारी जरूरतें कभी भी पूरी नहीं हो पाती हैं. इस मसले पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और उनके लिए शीघ्र कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे उन्हें फायदा हो. और ये महिलाएं अपने–अपने काम में और तरक्की कर सकें.■

feedback@chauthiduniya.com

स्वामी शंकर देव प्रकरण

रामदेव को क्लीन चिट!

राजकुमार शर्मा

योग गुरु बाबा रामदेव एवं बालकृष्ण के गुरु स्वामी शंकर देव के अपहरण के मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल फाइनल रिपोर्ट अदालत ने मंजूर कर ली. राज्य के इस बहुचर्चित मामले में रामदेव को राहत दिए जाने को लेकर संत समाज के साथ–साथ जनसामान्य में तरह–तरह की चर्चाओं का बाज़ार गर्म है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की वह टिप्पणी अनायास याद आती है, जिसमें कहा गया था कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोते के समान है. संत समाज के प्रवक्ता एवं अखाड़ा परिषद के सचिव हठयोगी ने कहा कि सैंया भए कोतवाल, अब डर काहे का. उनका इशारा साफ़ है कि यह सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मर्जी से हो रहा है. हठयोगी कहते हैं कि सीबीआई आज भी केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली है. सीबीआई को लेकर जो आरोप पहले भाजपा कांग्रेस पर लगाती थी, वही आरोप आज स्वयं भाजपा पर लग रहे हैं.

दरअसल, यह घटना बताती है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधी आज भी अदालत और क़ानून से ऊपर हैं. यही नहीं, हठयोगी राज्य सरकार के मुखिया हरीश रावत द्वारा बाबा रामदेव पर की जा रही मेहरबानियों पर भी हैरान हैं. वह कहते हैं कि जिन रामदेव के विरुद्ध पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने लगभग आठ दर्जन मामले दर्ज कराए थे, उन्हीं रामदेव पर मौजूदा मुख्यमंत्री हरीश रावत की मेहरबानियां

कांग्रेस के दोहरे चरित्र का प्रमाण हैं. भारतीय संत समाज के अध्यक्ष प्रमोद कृष्णन ने कहा कि रामदेव के गुरु शंकर देव एवं शिष्य बालकृष्ण प्रकरण आज भी ज्वलंत है. इसके लिए संत समाज गंभीर है और आम जनता भी इसका हल चाहती है. प्रमोद कृष्णन ने कहा कि शंकर देव वर्ष 2007 से लापता हैं, लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने उनकी खोजबीन किए बगैर फाइनल रिपोर्ट लगा दी. पुलिस के इस रवैये से संत समाज स्तब्ध और आहत है. उन्होंने कहा कि इस मामले का पर्दाफाश अवश्य होना चाहिए. शंकर देव के एक अन्य शिष्य कर्मवीर ने कहा कि लापता होने से दो–तीन दिन पहले गुरु शंकर देव ने अपनी जान को ख़तरे का संकेत दिया था.

ग़ौरतलब है कि रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण ने 16 जून, 2007 को थाना कनखल में शंकर देव की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि स्वामी शंकर देव कृपालु बाग आश्रम से कहीं चले गए हैं. लंबी जांच के बावजूद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा. बाद में गुमशुदगी का मामला अपहरण में बदल दिया गया और जांच सीबीआई को सौंप दी गई. बताते हैं कि 80 वर्षीय शंकर देव 14 जुलाई, 2007 को कृपालु बाग आश्रम से नित्य की भांति सैर के लिए निकले थे. उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला. जिस दिन यह घटना घटी, उस दिन बाबा रामदेव विदेश दौरे पर थे, जबकि उनके सहयोगी बालकृष्ण भी आश्रम में नहीं थे. सीबीआई ने भी शंकर देव मामले में गहनता से पूछताछ और कई बिंदुओं पर जांच की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका. 10 दिसंबर, 2014 को सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट दाखिल होने के बाद अदालत ने आचार्य बालकृष्ण से आपत्ति दर्ज कराने के लिए कहा था, जिस पर उन्होंने ने बीती 12 जनवरी को अनापत्ति दर्ज करा दी. अदालत ने बालकृष्ण की अनापत्ति स्वीकार करते हुए यह मामला बंद करने का आदेश दे दिया.■

feedback@chauthiduniya.com

> आज पानी की कम उपलब्धता की वजह से खेती में उत्पादन सीमित है. हम आज भी गेहूं–धान लगाने को बढ़िया काम कह रहे हैं. क्या बढ़िया काम कर रहे हैं. हम न तो जमीन का सदुपयोग कर रहे हैं और न हम इस प्रकृति द्वारा दी गई हवा और धूप का प्रयोग ठीक से कर रहे हैं. मेरे हिसाब से गेहूं और धान लगाना कोई अक्लमंदी नहीं है. राजस्थान को देखिए यह राज्य एक तरफ यमुना की पानी के लिए लड़ता है और दूसरी तरफ गेहूं का उत्पादन करता है और राजस्थान से एक्सपोर्ट कर देता है. फूड कॉर्पोरेशन को दे देता है कि हमने 10 लाख टन गेहूं का उत्पादन कर के दे दिया. एक किलो गेहूं पैदा करने में तो 1800 लीटर पानी लगता है तो आप जोड़ लें कि कितना पानी हम एक्सपोर्ट करते हैं.

कृषि क्षेत्र के कायाकल्प की ज़रूरत है

मुकेश गुप्ता

देश में कृषि नीति के संबंध में जो राजनीतिक नेतृत्व की जरूरत थी या फिर किरदार होना चाहिए था वह तो नहीं है. ऐसा लगता है कि उनमें या तो समझ की कमी है या उतना उत्साह नहीं है. सरकार सिर्फ इतना करती है कि जो कुछ पहले से चलता चला आ रहा है, उसी में कुछ बढ़ा देने का प्रयास कर देते हैं. कभी फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ा दो, एमएसपी घटा दो या बढ़ा दो, नई क्रॉप एमएसपी में डाल दो, चलो थोड़ा सा ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वही पुराना तरीका अपनाया जा रहा है. दूसरा ये है कि सरकार का प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर दो. किसानों की प्रॉब्लम क्रेडिट की है तो क्रेडिट दे दो, एमएसपी की प्रॉब्लम है तो एक रुपया बढ़ा दो. इस तरह की बातें ही अभी तक हो रही हैं. मुख्य बात है कि कोई बड़े बदलाव की कोशिश नहीं हो रही है. इसका कारण यह है कि राजनीतिक नेतृत्व और अफसरशाही को कृषि ग्लैमरस नहीं लगती है. उससे मीडिया की हेडलाइन नहीं बनती. इसी वजह से एग्रीकल्चर को लेकर कोई उत्साह नहीं है. जैसे इंडस्ट्री के लिए सीआईआई है, फिक्की है, ये कुछ न कुछ करते हैं. नई पॉलिसी, नये तौर-तरीकों की बात करेंगे. उसमें इन्वेस्टमेंट भी है. तो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी उसमें कुछ न कुछ करते हैं. ये सब कृषि में नहीं है. कृषि क्षेत्र में महज टोकनिज्म है और यही कृषि का दुर्भाग्य है.

मोदी सरकार को अपने बजट में कृषि को प्राथमिकता देनी चाहिए. देश में कई नई योजनाओं की शुरुआत हुई लेकिन बीच रास्ते में ही खत्म हो गईं. मोदी सरकार को रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट यानि नदियों को जोड़ने की परियोजना को फिर से शुरू करना चाहिए. एक लाख करोड़ रुपये हर साल उस प्रोजेक्ट के लिए आवंटित कर देना चाहिए. पांच साल में हमारी खेती की दशा में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा. ये एक लाख करोड़ रुपये हम कहीं से भी लाएं. टैक्स से इकट्ठा करें या सेस से इकट्ठा करें, लोगों से लोन लें, बॉन्ड निकालें, कुछ भी करे सरकार, लेकिन हमें एक लाख करोड़ रुपये हर साल इस पर लगाना चाहिए. हम नहरें और नदियों को जोड़ने में सफल हो गए तो देश में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है, जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं.

आज पानी की उपलब्धता की वजह से खेती में उत्पादन सीमित है. हम आज भी गेहूं-धान लगाने को बढ़िया काम कह रहे हैं. क्या बढ़िया काम कर रहे हैं. हम न तो जमीन का सदुपयोग कर रहे हैं और न हम इस प्रकृति द्वारा दी गई हवा और धूप का प्रयोग ठीक से कर रहे हैं. मेरे हिसाब से गेहूं और धान लगाना कोई अक्लमंदी नहीं है. राजस्थान को देखिए यह राज्य एक तरफ यमुना की पानी के लिए लड़ता है और दूसरी तरफ गेहूं का उत्पादन करता है और राजस्थान से एक्सपोर्ट कर देता है. फूड कॉर्पोरेशन को दे देता है कि हमने 10 लाख टन गेहूं का उत्पादन कर के दे दिया. एक किलो गेहूं पैदा करने में तो 1800 लीटर पानी लगता है तो आप जोड़ लें कि कितना पानी हम एक्सपोर्ट करते हैं. दूसरे ये दोनों क्रॉप लीस्ट एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हैं. एक तो पानी की मुसीबत, दूसरी एम्प्लॉयमेंट. अगर आप मैन डेज बेसिस पर कैलकुलेट करें तो आपको पता चलेगा कि मुश्किल से एक एकड़ जमीन में 50-55 मैन डेज का वर्क क्रिएट होता है. उसी तरह अगर उसी जमीन और उसी जगह में उतने उपलब्ध पानी में अगर हम सब्जियों की खेती करें, अगर हो सकती हैं तो, वो 500 मैन डेज का एम्प्लॉएमेंट क्रिएट करेगी. यदि हम, और भी पानी कम है, जमीन के नीचे से पानी निकाल रहे हैं 300, 500, 800, 1000 फुट पर डार्क जोन डिक्लियर करते जा रहे हैं. वहां पर हम वहां गेहूं और चावल की खेती करना बंद कर दें और उसकी जगह हम फलों के पेड़ लगायें तो वहां पर हम 700-800 मैन डेज एम्लॉयमेंट जेनरेट करेंगे. प्रति एकड़ हम कितना एम्लायमेंट क्रिएट कर रहे हैं, प्रति एकड़ हम कितना पानी कितना उपयोग कर रहे हैं, ये बेसिस होना चाहिए. प्रति एकड़ हम कितना खाद्य उत्पादन कर रहे हैं. वो तो हमारी जरूरत 70 के दशक में थी. दुनिया सारी स्थिर नहीं है. पहले हम फिएट में चलते थे अब फोर्ड में चलने लगे हैं.

दूसरा हमारी जो वन भूमि है उनमें जंगल तो होना चाहिए. बंजर जमीन नहीं होनी चाहिए. अभी तो हम इसकी दुर्दशा कर रहे हैं. कानून बना दिया कि जंगल में कुछ नहीं होगा. परिणाम क्या हो रहा है, जो है वो तो सब खत्म होता जा रहा है, हरियाली के नाम पर हम जंगली बबूल लगा रहे हैं. न वो धरती के काम आ रहा है, न गाय भैंस के काम आ रहा है न इंसान के काम आ रहा है. हमारे पास प्रकृति की विरासत में मिली हुई विविधता है, ट्रॉपिकल कंट्री होने की वजह से हमें बहुत बड़ी मात्रा में विविध फूड डायरेक्टली और इंडायरेक्टली तरीके से उपलब्ध हैं. हमेशा से ही हम कृष्ण की कहानियां सुनते हैं, कि साहब गाय पालते थे और सब गाय पे जिंदा रहते थे, कृष्ण की कहानियों में कहीं नहीं आता है कि ग्वाले खेती करके पेट भरते थे. यानि कि मुख्य फूड दूध था. एनीमल प्रोडक्ट, उनका सोर्स ऑफ फूड क्या था- जंगल. कोई खेती करके गेहूं का भूसा तो स्टोर करता नहीं था. इसका जिक्र स्टोरी में तो नहीं है आता है कहीं. यदि आप इतिहास देखें तो हमनें अपने टोटल क्रॉपिंग पैटर्न को बर्बाद कर लिया और जंगल विभाग को हमने अलग कर दिया और उनकी जिम्मेदारी हो सकती है इंडायरेक्ट्ली प्रोडक्शन ऑफ फूड. यदि हम उनको टारगेट करें तो बहुत बड़ा रिसोर्स प्रोडक्टिव यूज में आ जाएगा. यदि इस बजट में कोई ट्रॉन्सफॉर्मेशन आ सकता है तो उसके लिए फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को एक टेबल पर लाया जाए. उनके कंबाइन्ड प्रोग्राम बनाए जायें. तीनों को एक टेबल पर लाया जाये और कहा जाये कि आप कमरे से तभी निकलोगे जब आपके पास एक मिलियन हेक्टेयर को हरा करके10 मिलियन या 100 मिलियन फॉडर प्रोडक्शन करने का प्लान हाथ में होगा. उतने फॉडर से इतना दूध और इतना मीट और जाने क्या-क्या पैदा होगा. यह फॉडर हमारे पेट भरने से नहीं न्यूट्रीशन की जरूरतों को पूरा करेगा. जो भी हम मिस कर रहे हैं.

मैं बड़े दिनों से ऑब्जर्व करता हूं और ये जमीन के अधिग्रहण और जमीन से संबंधित समस्या भी है. ये हमारी नहीं पूरी दुनिया की संस्कृति के उद्भव का मूल कारण भी रहा है. हम सब नदी या पानी के रिसोर्स पर बसे हैं. परिणाम यह है कि हमारे आज भी अधिकतर शहरों की बसावट अच्छे पानी के प्राकृतिक स्त्रोत पर निर्भर है, आप किसी भी शहर का नाम लेंगे वहां पर या तो कोई नदी होगी या कोई बड़ी झील या तालाब होगा. या जमीन में बहुत आसानी से उपलब्ध पानी होगा. अभी तकरीबन 100-150 सालों में कृषि छोड़ कर दूसरे इकोनॉमिक्स सेक्टर में जो तरक्की हुई है, उससे आप देखेंगे कि लोग शहरी किसान बन गए. उदाहरण के लिए किसी ने शहर में कपड़ों का शोरूम खोला और निवेश के लिए 10 बीघा जमीन खरीदी है, अब वह कोई पहाड़ी ज़मीन तो नहीं खरीदेगा, वो सबसे प्रोडक्टिव लैंड खरीदता है. प्रोडक्टिव लैंड ऐसे नॉन प्रोडक्टिव काम में डाइवर्ट हो गई है. आप यकीन नहीं करेंगे. ऐसी भी मिलियन हेक्टेयर लैंड है. और शहरी तो ऐसे ही छोड़ देते हैं. बंटाई के नियम ठीक नहीं हैं. वहां ताला बंद करके चौकीदार रखते हैं. उसी चौकीदार से कहते हैं कि उगा कुछ. वो उगाए तो ठीक न उगाए तो ठीक. उसका तो केवल इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है, अभी क्या कर सकते हैं.

> **1920 के बाद में 1970 तक 50 साल तक खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रिवाल्यूशवन जो हुआ वो हुआ डेवलपमेंट ऑफ केमिकल इन पुट्स, बोथ एज फर्टीलाइजर एंड पेस्टीसाइड, जो उस समय उचित समझा गया वो किया गया, लेकिन आज जो परिणाम है उसे देखकर ये विचार किए जाने की जरूरत है कि हमें इसका कोई कोई न कोई अलटरनेटिव तो ढूंढना पड़ेगा, केमिकल्स के दाम बढ़ते जायेंगे, खेती में आमदनी कम होती जाएगी, केमिकल पेस्टेसाइड वाले ज्यादा पैसे मांगेंगे,**

मेरा मानना है कि हम दो आब्जेक्टिव को लिंक कर सकते हैं. एक तो रोजगार और दूसरा हाई वैल्यू हाई रिस्क फूड प्रोडक्शन. हमारे यहां जमीन अच्छी है, पानी उपलब्ध है. सब सुविधायें हैं और हमारे यहां बेरोज़गारों की फौज है. हम कृषि के लिए आईटीआई खोल सकते हैं. युवाओं को बाजार से जुड़ी चीजों के उत्पादन की ट्रेनिंग दी जा सकती है. साथ ही अगर हम लैंड ऑनर की वनरेबिलीटी का सिस्टम क्रिएट कर दें. जो उसे ये सुरक्षा देता हो कि यदि मैंने कोई ऐसी लेबर इंगेज की जो वहां फूलों की, फलों की, सब्जियों की खेती कर सकती है, वो मेरी जमीन नहीं दाबेगा. और वहां जो उपज होगी उसका फेयर शेयर उसे मिलेगा. और उसमें चोरी नहीं होगी. कानून तो बना सकते हैं. सरकार को न तो पैसा देना पड़ेगा न बजट एलोकेशन करना पड़ेगा. लेकिन नियम में ऐसे प्रावधान करने पड़ेंगे जिससे ये संभव हो. जब हम महिलाओं के लिए इतने बड़े कानून बना सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि दूसरे की जमीन तुमने हड़पी तो तुम्हें बीस साल की सजा होगी. सोचेगा आदमी कि मुझे ऐसा नहीं करना है. कानून बना दें कि आपने इस जमीन पर होने वाली उपज में से चोरी की तो तुम्हें कम से कम पांच साल की सजा होगी. तो वह नहीं करेगा. ऐसे हम यदि कुछ न कुछ इनेबलिंग प्रोवीजन क्रिएट करें. और बजट में अलोकशन करें इस तरह के लोगों को ट्रेनिंग देने की. पांच, दस, बीस लाख लोगों को ट्रेनिंग दें. ऐसे दो बीघा में एक आदमी खप जाएगा. यदि ऐसी पांच, दस मिलियन हेक्टेयर जमीन है तो आप नंबर निकाल सकते हैं कि कितने लोग इस इंडस्ट्री में लग जायेंगे. फिर इसके बाद जो वैल्यू एडीशन होगा उसमें रोजगार मिलेगा. न तो बैंक के ऊपर प्रेशर आएगा. न सरकार को कोई लोन सब्सिडी देनी पडेगी. यहां ट्रांस्फॉर्मेशनल बदलाव करने की जरूरत है.

1920 के बाद में 1970 तक 50 साल तक खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रिवाल्यूशवन जो हुआ वो हुआ डेवलपमेंट ऑफ केमिकल इन पुट्स, बोथ एज फर्टीलाइजर एंड पेस्टीसाइड. जो उस समय उचित समझा गया वो किया गया. लेकिन आज जो परिणाम है उसे देखकर ये विचार किए जाने की जरूरत है कि हमें इसका कोई कोई न कोई अलटरनेटिव तो ढूंढना पड़ेगा. केमिकल्स के दाम बढ़ते जायेंगे. खेती में आमदनी कम होती जाएगी. केमिकल पेस्टेसाइड वाले ज्यादा पैसे मांगेंगे. तो सरकार कहेगी कि और सब्सिडी देते हैं और आवाज उठेगी. एमएलए और एमपी उससे ज्यादा अपने लेवल पर और उससे कुछ कर नहीं सकते हैं. उतना उनका एक्सपोजर भी नहीं है. उन्हें इस तरह समझने का मौका भी नहीं मिलता है. रीसेंटली ऑर्गेनिक एग्रीकल्टर के आने के बाद में एक बात स्टेब्लिश्ड हो गई कि बिना केमिकल के खेती तो होती है. और देश में कश्मीर में केशर से लेकर अंडमान में नारियल तक जैविक तरीके से हो रहा है. क्यों न देश में एक राट्रीय मुहिम चलाई जाये जो कहे कि देश में ये मुहिम चले कि हमारे टारगेट है कि कुल होने वाले वाले फर्टीलाइजर का हम दस प्रतिशत सब्सटीट्यूशन करेंगे. पहले तो ये फैसला होगा. उसके पीछे मेरिट होगी. इस पर चर्चा करें तो मेरिट समझ में आएगी, अब कैसे होगा, तो बॉयलॉजिकल है. कैसे फर्टीलिटी मैनेजमेंट के नए टूल डेवलप कर सकते हैं. जिसमें अधिक ऑर्गेनिक मैन्योर, उसका बेटर कन्वर्शन और उसका सॉइल में एप्लीकेशन हो तो हम शायद ये लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं. मोटे तौर पर ये नंबर फेवरेवल हैं. इसे एचीव करने के लिए. यानि, यदि मैं तय कर लूं कि मुझे 1 मिलियन हेक्टेयर के अंदर कोई भी केमिकल इनपुट नहीं डालना है, एज ए फर्टीलाइजर. अब पेड़ तो नहीं पहचानता है, कुछ लोग बोलते हैं कि साहब केमिकल नहीं तो खेती नहीं, ये तो मूर्खता भरी बात है कि पेड़ तो नहीं पहचानता है कि उसे नाइट्रोजन गोबर की खाद से आ रही है या केमिकल फर्टीलाइजर या यूरिया से आ रही है. उसे नाइट्रोजन मिला तो पेड़ की ग्रोथ होगी ही. तो हम ये प्लानिंग करें जो पहले मैंने फॉरेस्ट वाला बोला कि दोनों को लिंक करने से मिलियन्स ऑप हेक्टेयर लैंड, विच इज करेंटली अंडर स्ट्रेस ऑफ प्रोडक्टिवीटी कैन बी ब्रॉट टू ए बेटर मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक फिलॉसफी की बात है. बजट क्या करेगा? इसमें बजट कैन एलॉकेट सम मेजर इनिशिएटिव 25-25 लाख रुपये एक-एक केवीके को दे दिया.इस तरह का टोकनिज्म नहीं. सीधे 10 हजार हजार करोड़ का एलोकेशन इसलिए इसको सपोर्ट करने के लिए, किसानों को एक फॉलबैक मैकेनिज्म प्रोवाइड करने के लिए, इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए और लोकल लेवल के ऊपर इसकी प्रेक्टिसेज डेवलप करने के लिए. ऑर्गेनिक मैन्योर फॉर्मर लेवल पर भी बनाई जाए ऑर्गेनिक मैन्योर कमर्शियल लेवल पर भी बनाई जाए.इंटरप्रोन्योर को प्रमोट किया जाए. उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी कुछ समय तक, तो यह भी एक राष्ट्रीय लक्ष्य का काम हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशनल बदलाव लाएगा. पांच-दस सालों में बहुत बड़े पैमाने पर इसका आपको बज़ट में इंपैक्ट दिखाई देगा. यदि केमिकल फर्टीलाइजर की सब्सिडी सरकार अगर हम कहें एक डेढ़ लाख करोड़ रुपये साल की है, वो धीरे-धीरे कम होती दिखाई देगी. जमीनों का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा. और हम तो बहुत लकी हैं हमारे पास में तो बहुत सारे मिनरल्स हैं. रॉक फॉस्फेट हमारे देश का अपना है, जिप्सम हमारे देश अपना है, और भी दूसरे न्यूट्रेंट्स हैं. केवल सल्फर की मारा-मारी है. सल्फर हमें इंपोर्ट करना पड़ता है वो भी जिंक सल्फेट वगैरह कुछ हैं इनसे पूर्ति हो सकती है. अगर इंसानों ने अक्ल लगा के यूरिया और डीएपी का विकास किया तो विकास करके बॉयोलाजिकल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट भी बना लेंगे. कोई ये बोले कि यह संभव नहीं है तो ये अज्ञानता की वजह से या और किसी कारण की वजह से कहता होगा. तो ये भी एक ऐसा बदलाव बजट में ला सकता है.

(लेखक भारत में जैविक खेती की शुरुआत करने वाले कृषि वैज्ञानिक हैं. वे वर्तमान में मोरारका फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं और देश में सबसे बड़े जैविक कृषि फॉर्म को मैनेज कर रहे हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

भाजपा को कांग्रेस पार्टी के साथ बातचीत शुरू कर देनी चाहिए और कांग्रेस को भी एक जिम्मेदार पार्टी बननी चाहिए. बजाए एक बाधा उत्पन्न करने वाली पार्टी के. छोटे दल ऐसा कर सकते हैं. कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती. भाजपा केवल 5 साल के लिए चुनी गई है. कांग्रेस का उद्देश्य 5 साल के बाद सत्ता वापस पाने का होना चाहिए. उसे सिर्फ एक समस्याएं पैदा करने वाली पार्टी के तौर पर खुद को नहीं प्रदर्शित करना चाहिए और न ही खुद को ऐसा दिखाना चाहिए कि एक चुनाव हार कर वो आगे शासन करने का नैतिक अधिकार खो चुकी है.

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश किसान विरोधी है

पिछले हफ्ते विश्व कप में भारत–पाकिस्तान मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. हैरत की बात है कि पाकिस्तान कभी भी विश्व कप के मैचों में भारत के खिलाफ नहीं जीत पाया है. ऐसा क्यों होता है. इसे समझना बहुत कठिन है, लेकिन यह तय है कि मनोवैज्ञानिक दबाव में आने की वजह से ही टीम में अच्छे खिलाड़ी होने के बावजूद जीतने में वो सक्षम नहीं हो पाते. मैं इस बार मान रहा था कि कमजोर भारतीय गेंदबाजी की वजह से पाकिस्तान की जीत होगी, लेकिन फिर भी भारत 76 रन की एक मार्जिन के साथ बहुत आराम से जीत गया. यह भारत के लिए खुशी की बात है, लेकिन क्रिकेट के लिए हमें इस पहलू का अध्ययन करना चाहिए. बेशक विश्व कप के फाइनल में 5–6 हफ्तों का समय है. भारत ने एक अच्छी शुरुआत करके अपने मनोबल को ऊंचा कर लिया है. भारत को एक बार फिर से कप जीतने का प्रयास करना चाहिए.

राजनीतिक मोर्चे पर चिंता करने की बात यह है कि भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ किसान आंदोलन शुरू होने वाला है. ब्रिटिश शासन द्वारा पारित पुराना भूमि अधिग्रहण बिल आउट आफ डेट (गैर जरूरी) हो गया है. पश्चिम बंगाल में यह साबित हो चुका है. तत्कालीन सरकार ने वहां किसानों से दो फसली जमीन छीनने की कोशिश की. मेरे हिसाब से वामपंथ के 34 साल पुराने शासन के खात्मे की एक मुख्य वजह यही रही. सरकार के इस कदम को किसान विरोधी माना गया. यूपीए सरकार ने फिर इस बिल पर काम किया. स्थायी समितियां अन्य सभी संबंधित पक्षों से लंबी बहस, राय–मशविरा करने के बाद एक बिल ले कर आई. हालांकि यह बिल भी बहुत संतोषजनक नहीं था, लेकिन यह कम से कम कामचलाऊ था. कम से कम जमीन खोने की स्थिति में किसान को मुआवजे के रूप में एक बड़ी रकम मिलने का आश्वासन यह बिल दे रहा था. अब सत्ता में आने के बाद एनडीए सरकार कॉरपोरेट सेक्टर को खुश करने की कोशिश कर रही है. जहां होना यह चाहिए था कि कम्पनियां सीधे पैसा देकर किसानों से जमीन खरीदे, हो ये रहा है कि सरकार इस कानून के सहारे किसानों से जबरिया जमीन लेकर कॉरपोरेट को देने की कोशिश में लगी हुई है. सरकार का रवैया कॉरपोरेट्स के लिए भी एकसमान नहीं है. किसी एक का फेवर करती है तो दूसरे का नहीं करती है. इस सब में कुछ पारदर्शिता होनी चाहिए. अधिग्रहण के लिए 80 फीसदी सहमति वाले प्रावधान को हटाने से किसान नाराज है. एनडीए ने यूपीए वाले बिल से कई अन्य जरूरी प्रावधान को भी हटा दिया है.जाहिर है, इन सब से किसान स्वाभाविक रूप से उत्तेजित हो रहे हैं.

हालांकि यह बिल अध्यादेश के माध्यम से पारित किया गया है और इसे संसद के दोनों सदनों से पारित होना है और यह तब तक नहीं हो सकता, जबतक कि सभी पार्टियां इसका समर्थन न करें. कांग्रेस यहां कोई समझौता नहीं करना चाहेगी. संसद की अनदेखी कोई समाधान नहीं है, लेकिन इसे लेकर अति सक्रियता भी ठीक नहीं है. विपक्ष को केवल बाधा डालने का काम नहीं करना चाहिए और न ही सरकार को सब कुछ अध्यादेश के जरिए पास करवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. ये दोनों पहलू लोकतंत्र में गलत हैं. अमेरिका में हम देखते हैं कि एक बिल को पास करने के लिए सरकार को सीनेट में कम से कम 60 सदस्य की जरूरत होती है. शायद ही किसी अमेरीकी राष्ट्रपति को कोई बिल पास कराने के लिए इतना समर्थन होता है, लेकिन वे दोनों पार्टियों के सदस्यों का समर्थन लेकर, थोड़े बहुत संशोधन के साथ बिल पास करा लेते हैं. यही फार्मूला भारत में भी आजमाया जाना चाहिए.

भाजपा को कांग्रेस पार्टी के साथ बातचीत शुरू कर देनी चाहिए और कांग्रेस को भी एक जिम्मेदार पार्टी बननी चाहिए. बजाए एक बाधा उत्पन करने वाली पार्टी के. छोटे दल ऐसा कर सकते है. कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती. भाजपा केवल 5 साल के लिए चुनी गई है. कांग्रेस का उद्देश्य 5 साल के बाद सत्ता वापस पाने का होना चाहिए. उसे सिर्फ एक समस्याएं पैदा करने वाली पार्टी के तौर पर खुद को नहीं प्रदर्शित करना चाहिए और न ही खुद को ऐसा दिखाना चाहिए कि एक चुनाव हार कर वो आगे शासन करने का नैतिक अधिकार खो चुकी है. खतरा यह है कि कांग्रेस अभी यही धारणा पुष्ट कर रही है. एक जिम्मेदार तरीके से कांग्रेस यह कह सकती है कि हमने आपसे बात कर के यह बिल पारित किया था. अब आप बहुमत में हैं, कुछ मुद्दों पर हम सहमत हो सकते हैं, लेकिन जो मुद्दे किसानों के हित से जुड़े हैं, हम उन पर समझौता नहीं कर सकते.

और यह बिल कुछ ऐसे बड़े उपाय के साथ, जो किसानों की रक्षा कर सके, पारित किया जाना चाहिए. किसान आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, यह कैसे आगे जाएगा, हम नहीं जानते. अन्ना हजारे भी राजगोपाल के साथ दिल्ली जा रहे हैं. संसद शुरू होने के साथ ही तीन समूह दिल्ली में एक ही बिंदु पर आंदोलन कर रहे हैं. यह एक गंभीर मुद्दा बन सकता है और मामला अनियंत्रित हो सकता है. सरकार को अपना दिमाग लगाना चाहिए. इस मामले का संबंध किस पोर्टफोलियो से है, मुझे नहीं मालूम. वित्त मंत्री बजट में व्यस्त होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री या गृहमंत्री राजनाथ सिंह, जो खुद उत्तर प्रदेश से हैं और किसानों की समस्या से वाकिफ हैं, को अपना दिमाग इसमें लगाना चाहिए और सिर्फ कानून और व्यवस्था की समस्या मानने की जगह एक तर्कसंगत उचित समाधान ढूंढा जाना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

जेपी ने कहा था, फिर आना-2

सिर्फ़ सबको देने वाली शख्सियत

रणछोड़ बाबू के बाहर निकलने की आशा छोड़ कमरे में घुस जाता हूं. रणछोड़ बाबू बाहर निकल जाते हैं, तो जेपी कहते हैं, बहुत साफ़ दिमाग है प्लानिंग के बारे में रणछोड़ बाबू का. डॉक्टर रक्तचाप देखने लगता है. मैं कमरे में नज़र घुमाता हूं, तो जेपी के सिरहाने मोटे अक्षरों में लिखा मिलता है, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे. सिर के एक ओर गांधी जी व प्रभावती दीदी की तस्वीर है तथा बाईं दीवार पर जेपी और प्रभावती दीदी की. ठीक आंखों के सामने चीनी कला की दो खूबसूरत तस्वीरें हैं. जेपी के पलंग के दाईं तरफ़ भारी–भरकम डायलिसिस की मशीनें रखी हैं. सारे कमरे में एक अजीब तरह की खुशबू भरी है.

जेपी घूमकर कुछ कहना चाहते हैं कि मैं रोक कर बोल उठता हूं, मैं बात करने नहीं, केवल बैठने आया हूं. सच्चिदा बाबू उस दिन के अख़बार सुनाने लगते हैं. राजनीतिक समाचारों पर जेपी ठंडी सांसें भरते हैं, पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की राजनीतिक हत्याओं से संबंधित रिपोर्ट के समाचार से परेशान हो जाते हैं. दिल्ली की ख़बरों पर सिर्फ़ एक टिप्पणी की कि मैं तो जनता से ताकत लेता था, आज भी यदि जनता से मिल पाऊं तो... वाक्य अधूरा रह जाता है, लेकिन अर्थ स्पष्ट कर देता है. जेपी ऊपर देखने लगते हैं. शायद उन्हें याद आ गया होगा कि जनता से वादे तो उन्होंने ही किए थे. मैं टीप जड़ता हूं कि जेपी, आपने जिनकी जमानत दी थी, उन्होंने बेल एक्जम्प्ट कर दी है. जेपी मुस्करा उठते हैं, व्यंग्य भरी मुस्कान.

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं. नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

अचानक कहते हैं बाहर चलने के लिए. मुझे साथ लेकर टहलने लगते हैं. अपनी कमजोरी और बीमारी को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं. केवल 25 गज के चार चक्कर और जेपी थक जाते हैं. उनका कमरा, साथ में लगा बाथरूम, पीछे की छत तथा बरामदा, बस अब यही है उनका संसार. जेपी यहां से निकलना नहीं चाहते.

अचानक कहते हैं बाहर चलने के लिए. मुझे साथ लेकर टहलने लगते हैं. अपनी कमजोरी और बीमारी को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं. केवल 25 गज के चार चक्कर और जेपी थक जाते हैं. उनका कमरा, साथ में लगा बाथरूम, पीछे की छत तथा बरामदा, बस अब यही है उनका संसार. जेपी यहां से निकलना नहीं चाहते. सच्चिदा बाबू बताते हैं कि अब भी यदि जेपी जनता से मिल सकें, तो यह बिल्कुल ठीक हो सकते हैं. मैं मन ही मन हंस पड़ता हूं कि जेपी से उनका कार्यकर्ता आकर आज भी मिल नहीं सकता, वहीं संजय गांधी से मिलने के लिए जेपी एक घंटे तक बैठाए जा सकते हैं.

अगले दिन डायलिसिस है. बिल्कुल सुबह जेपी के पास पहुंचता हूं. जेपी अचानक बोधगया में संघर्ष वाहिनी के लड़कों पर हुए हमले की बात पूछ उठते हैं. यह जानकर कि सारे देश में आस्था का संकट खड़ा हो रहा है, जेपी गुमसुम हो जाते हैं. मैं पूछता हूं कि आपको क्या लगता है कि क्या होगा? जेपी डबडबाई आंखों से बोल उठते हैं, देखो क्या होता है. धीरे–धीरे मेरा साहस चुकने लगता है तथा अचानक उठकर उन्हें प्रणाम करता हूं. जेपी आशीर्वाद देते हुए रुक–रुककर बोलते हैं, फिर आना.

नीचे उतरते हुए सच्चिदानंद से टकराहट हो जाती है. उनके मन में अलग गुस्सा है. वह भी उपयुक्त समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वह उन सारी घटनाओं से परदा हटा सकें, जिन्होंने जयप्रकाश को एकांतवास के लिए मजबूर कर दिया है. दूसरे सचिव अब्राहम का कहना है कि उनकी डायरी में बहुत कुछ बंद है, लेकिन वह उनके साथ ही चला जाएगा.

जयप्रकाश को इतिहास अवश्य इस रूप में याद करेगा कि इस आदमी ने केवल दिया ही दिया है, किसी से लिया कुछ भी नहीं–न सत्ता, न सहानुभूति और न संवेदना. ■

(14 अक्टूबर, 1979)

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

शेखर गुप्ता ने प्रभाष जोशी को कलंकित किया

ये भ्रष्ट पत्रकारिता की चरम सीमा है. शेखर गुप्ता ये कह रहे हैं कि पत्रकारों की उपस्थिति में, जिसमें वो स्वयं थे वहां पर, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने यह पैसा लिया. उन्होंने अपने गवाही के तौर पर लिखा कि वहां पर इस साल पद्म पुरस्कार पाये हुए एक पत्रकार भी उपस्थित थे. इस साल तीन पत्रकारों को पद्मपुरस्कार मिला है, जिनमें श्री रजत शर्मा, श्री राम बहादुर राय और स्वपन दास गुप्ता शामिल हैं. मैंने सबसे पहले रजत शर्मा जी से फोन पर पूछा कि क्या आप 1988 में इलाहाबाद में थे और क्या आपके सामने विश्वनाथ प्रताप सिंह को साढ़े सात लाख रुपये या आठ लाख रुपये दिए गए थे और क्या प्रभाष जोशी ने ये रुपये दिए थे?

पत्रकारिता के नए सिद्धांत गढ़ने वाले और कोई नहीं, पत्रकारिता के सिरमौर माने जाने वाले बड़े पत्रकारों में से ही एक हैं. बे–सिर पैर की, जो साबित न हो सके, ऐसी खबरें और ऐसी चीजों का उद्घाटन, जिनसे मृत व्यक्तियों का संबंध हो और जो अपनी सफाई देने न आ सकें, ऐसी परिपाटी शुरू करने वाले पत्रकार श्री शेखर गुप्ता हैं. शेखर गुप्ता भारतीय पत्रकारिता में अहम स्थान रखते हैं और उनका मानना है कि उन्होंने बहुत सारे रहस्योद्घाटन किए हैं. उनके अच्छे कामों को सलाम करना चाहिए, लेकिन उनके उन कामों को, जो अच्छे नहीं है, बल्कि पत्रकारिता के नाम पर धब्बा माने जा सकते हैं, ऐसे कामों की आलोचना भी की जानी चाहिए.

मुझसे टेलीविजन के एक बड़े संपादक ने कहा कि पत्रकारों के खिलाफ हमें कोई स्टोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैसे ही पत्रकार लोगों के निशाने पर रहते हैं. इसलिए मैं सिद्धांततः पत्रकारों के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट करने के खिलाफ हूं. मैं उनका चेहरा देखता रह गया. वे पत्रकारिता से ज्यादा मित्रता को महत्व देते हैं. अगर यही काम कोई नया पत्रकार करे तो इन बड़े लोगों के मुंह से आसानी से निकल जाता है कि इसे पत्रकारिता की एबीसीडी नहीं पता और ये पत्रकारिता में जबरदस्ती तलवारबाजी कर रहा है. पर यही काम अगर शेखर गुप्ता करें तो उसके ऊपर लोगों की जुबान भी बंद हो जाती है और कलम भी.

मैं शेखर गुप्ता की बड़ी इज्जत करता था. उनकी पत्रकारिता का प्रशंसक भी था. जिस समय वो बड़े पत्रकार माने जाते थे, उस समय मैं उनका दीवाना भी था. दरअसल, मैं उन्हें रविवार के संपादक सुरेंद्र प्रताप सिंह के दोस्त की नज़र से देखता था. और मेरा मानना था कि सुरेंद्र प्रताप सिंह का रिश्ता किसी भी ओछे व्यक्ति से नहीं होगा. मैंने उन्हें कोलकाता में सुरेंद्र प्रताप सिंह के साथ एक बहुत छोटे से नुक्कड़ जैसे होटल में बातें करते घंटो देखा है. उस बातचीत में शेखर गुप्ता ही ज्यादा बोलते थे, सुरेंद्र प्रताप सिंह केवल श्रोता की मुद्रा में रहते थे. मैं ऐसी कई बैठकों में खामोश विद्यार्थी की तरह बैठा रहता था. शेखर गुप्ता ने पत्रकारिता में नेतृत्व संभाला और उनकी रिपोर्ट्स को पढ़कर ऐसा लगता था कि शेखर गुप्ता सही लिख रहे हैं और अचानक मेरा साबका शेखर गुप्ता की पत्रकारिता के उस चेहरे से पड़ा, जिस चेहरे ने मेरे जैसे श्रद्धा करने वाले व्यक्ति को तोड़ दिया.

तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह को लेकर शेखर गुप्ता की रिपोर्ट के कुछ हिस्से मेरे सामने घटित हुए. उन घटनाओं में शेखर गुप्ता स्वयं शामिल थे, लेकिन शेखर गुप्ता ने जब उन्हें रिपोर्ट किया तो कुछ चीजों को बिल्कुल उड़ा दिया और कुछ चीजों को पूर्णतः गलत दर्शाया. जब मैंने शेखर गुप्ता के इस कर्म की आलोचना अपने अखबार में की तो शेखर गुप्ता खामोश रहे. इसके दो ही कारण हो सकते हैं. या तो शेखर गुप्ता मेरे जैसे साधारण पत्रकार की बात का उत्तर देना अपनी शान के खिलाफ समझते रहे हों या फिर उनके पास उत्तर रहे ही न हों. हालांकि उनके अखबार ने कई बार मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की, तब हमने उनके नेतृत्व में चलने वाले इंडियन एक्सप्रेस अखबार की पूरी पत्रकारिता के ऊपर सवाल उठाये. ये सवाल पत्रकार मित्रों के बीच तो चर्चा का विषय बने, लेकिन शेखर गुप्ता के बहरे कानों में और धुंधली आंखों में इनकी आवाज और इनकी चमक नहीं पहुंची.

अब फिर शेखर गुप्ता ने एक नया कमाल किया है. उन्होंने उन दो मरे हुए व्यक्तियों के बारे में लिखा है, जिन्हें आम तौर पर हिंदुस्तान में पाक–साफ माना जाता है. हिंदी पत्रकारिता जगत के बड़े नामों में रहे प्रभाष जोशी को उन्होंने चौधरी देवी लाल का पैसे बांटने वाला दलाल साबित किया और विश्वनाथ प्रताप सिंह के ऊपर, जिन्हें हिंदुस्तान में आज तक किसी ने एक बूंद दाग का दोषी नहीं माना, चुनाव में बेशर्मी के साथ रुपये लेने वाला बताया. शेखर गुप्ता की अपनी रिपोर्ट में कॉन्ट्राडिक्शन ही कॉन्ट्राडिक्शन (विरोधाभास) है, क्योंकि 27 साल तक शेखर गुप्ता ने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन अब 27 साल बाद उन्हें उनकी एक रिपोर्ट्स डायरी मिली, जिसमें उन्हें ये घटना लिखी दिखाई दी. हमनें उनकी 6 पेज की इंडिया टुडे की जून 88 की रिपोर्ट देखी है, जिसमें उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में कुछ दूसरा ही लिखा है और आज वो उन्हें साढ़े सात लाख रुपये लेने वाला बता रहे हैं और देने वाले व्यक्ति का नाम प्रभाष जोशी बता रहे हैं. मैं उन दिनों चौथी दुनिया की तरफ से रिपोर्ट करने के लिए लगातार एक महीने इलाहाबाद में था. मैंने प्रभाष जोशी को इलाहाबाद में नहीं देखा. जनसत्ता के तत्कालीन संवाददाता हेमंत शर्मा 25 दिनों तक इलाहाबाद चुनावों को कवर करने के लिए इलाहाबाद में थे. उन्होंने प्रभाष जोशी को इलाहाबाद में नहीं देखा. विश्वनाथ प्रताप सिंह की पत्नी श्रीमती सीता देवी आज जीवित हैं, उन्होंने अपने घर में प्रभाष जोशी को नहीं देखा, और जितने भी लोग मुझे याद आ सकते थे, मैंने सबसे पता किया. किसी ने प्रभाष जोशी को इलाहाबाद में उस चुनाव में किसी ने नहीं देखा, लेकिन शेखर गुप्ता ने अपने सामने प्रभाष जोशी को साढ़े सात लाख रुपये लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह के घर ऐश महल में देखा और कई पत्रकारों की उपस्थिति में उन्हें पैसा देते हुए भी दिखा दिया.

ये भ्रष्ट पत्रकारिता की चरम सीमा है. शेखर गुप्ता ये कह रहे हैं कि पत्रकारों की उपस्थिति में, जिसमें वो स्वयं थे वहां पर, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने यह पैसा लिया. उन्होंने अपने गवाही के तौर पर लिखा कि वहां पर इस साल पद्म पुरस्कार पाये हुए एक पत्रकार भी उपस्थित थे. इस साल तीन पत्रकारों को पद्मपुरस्कार मिला है, जिनमें श्री रजत शर्मा, श्री राम बहादुर राय और स्वपन दास गुप्ता शामिल हैं. मैंने सबसे पहले रजत शर्मा जी से फोन पर पूछा कि क्या आप 1988 में इलाहाबाद में थे और क्या आपके सामने विश्वनाथ प्रताप सिंह को साढ़े सात लाख रुपये या आठ लाख रुपये दिए गए थे और क्या प्रभाष जोशी ने ये रुपये दिए थे? रजत शर्मा ने साफ कहा कि मैं उस समय तक वीपी सिंह से मिला ही नहीं था. मैंने स्वपनदास गुप्ता से पूछा, उन्होंने कहा रबिश, ये रिपोर्ट बकवास है. मैं इलाहाबाद चुनावों में गया ही नहीं था. तीसरे सज्जन हिंदी पत्रकारिता का बड़ा नाम, तत्कालीन नवभारत टाइम्स के विशेष संवाददाता राम बहादुर राय ने कहा कि पारिवारिक परिस्थितियों के कारण और अपने संस्थान के रमेश चंद्रा द्वारा संपादक राजेंद्र माथुर को दिए गए आदेश के अनुसार इलाहाबाद नहीं गया. मेरा जाना वहां प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि उन दिनों राजीव गांधी बनाम विश्वनाथ प्रताप सिंह चल रहा था और मुझे माना जाता था कि मैं सही रिपोर्ट करता हूं तो मैं कहीं वी पी सिंह के पक्ष में रिपोर्ट न कर दूं, इसलिए मुझे इलाहाबाद जाने से रोक दिया गया.

तब कौन पद्म पुरस्कार वाला व्यक्ति वहां उपस्थित था, जब वीपी सिंह को पैसे दिए गए और पैसे प्रभाष जोशी ने दिए. शेखर गुप्ता भ्रष्ट पत्रकारों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ माने जायेंगे, अगर शेखर गुप्ता अब भी उन पत्रकारों का नाम घोषित नहीं करते, जो उनके साथ इस घटना के गवाह थे. अगर शेखर गुप्ता इंडिया टुडे में ही लिखकर सात दिनों के भीतर नाम नहीं खोलते तो माना जाएगा कि शेखर गुप्ता न केवल भ्रष्ट पत्रकार हैं, बल्कि षड्यंत्रकारी पत्रकार भी हैं, जो कुछ लोगों के लिए ओछी पत्रकारिता करते हैं. शेखर गुप्ता को अगर इंडिया टुडे अब भी अपने यहां लिखने देता है तो मानना चाहिए कि इंडिया टुडे की पत्रकारिता भी इस देश में भ्रम फैलाने वाली, झूठ फैलाने वाली पत्रकारिता है.

एक वक्त इंडिया टुडे, संडे के मुकाबले की पत्रिका थी. एक तरफ संडे था, एक तरफ इंडिया टुडे थी और लोग दोनों ही पत्रिकाओं को बहुत गंभीरता से पढ़ते थे. संडे बंद हो गया, लेकिन इंडिया टुडे चल रही है. संडे का संपादन एम जे अकबर करते थे और इंडिया टुडे का संपादन श्री अरुण पुरी करते थे. अरुण पुरी ने अपना एक बड़ा बिजनेस एंपायर बनाया और जिसमें उन्होंने अच्छे–अच्छे पत्रकारों को मौका दिया. उन लोगों ने अरुणपुरी की आशाओं को पूरा भी किया, लेकिन वहीं पर अभी जिस तरह की घटना इंडिया टुडे के जरिये देश के सामने आई है, उसने पत्रकारों का सिर, ईमानदार पत्रकारों का सिर शर्म से झुका दिया है.

क्या मृत व्यक्तियों के बारे में लिखना शेखर गुप्ता का शगल बन गया है? उनकी ज्यादातर रिपोर्ट का टेल पीस या पुनश्चः मृत व्यक्तियों से जुड़ा होता है, जो अपनी सफाई देने नहीं आ सकते. और कम से कम ये घटना बताती है, जिसमें प्रभाष जोशी और वीपी सिंह शामिल हैं, कि शेखर गुप्ता पत्रकारिता में झूठ, मिथ्या और अपराध का सम्मिश्रण कर रहे हैं.

इस घटना ने मेरे जैसे साधारण पत्रकार को हिला दिया है. मैं शेखर गुप्ता से कहना चाहता हूं कि पत्रकारिता के लिए जान हथेली पर रखनी पड़ती है, आंखों में आंखे डालकर सत्य से सामना करना होता है और तब लिखना होता है. मुझे शेखर गुप्ता जैसे पत्रकार के पतन के ऊपर दुःख है. सबसे ज्यादा दुःख इस बात का है कि सुरेंद्र प्रताप सिंह जैसे लोगों की आत्मा शेखर गुप्ता जैसे लोगों की रिपोर्ट देखकर, यह सोच कर कहीं न कहीं परेशान हो रही होगी कि शेखर गुप्ता उनके कभी दोस्त थे.

भरी कड़ाही दूध में एक चुटकी नमक डाल कर उस पूरे दूध को फाड़ने जैसा है, पर इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है. शेखर गुप्ता न कभी इसे समझे, न कभी इसे समझेंगे. पर मुझे इस बात का गर्व है कि शेखर गुप्ता अपनी चालाकी में, अपने झूठ में, अपनी ही रिपोर्ट का असत्य वर्णन कर गए कि प्रभाष जोशी ने पत्रकारों की उपस्थिति में विश्वनाथ प्रताप सिंह को साढ़े सात लाख रुपये दिए और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी पत्रकारों की उपस्थिति में वो पैसे रख लिए. उनमें से कोई माई का लाल पत्रकार ऐसा नहीं था, जिसके अगुआ शेखर गुप्ता माने जा सकते हैं, जिसने इसको रिपोर्ट किया हो और ये वो दौर था, जब राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ हल्का सा धब्बा तलाश रहे थे. ये सारे पत्रकार विश्वनाथ प्रताप सिंह के वेतनभोगी नहीं थे. उन दिनों शेखर गुप्ता इंडिया टुडे के रिपोर्टर थे.

मैं बहुत दुःख के साथ ये शब्द लिख रहा हूं और मैं शेखर गुप्ता से आग्रह करता हूं कि उन पत्रकारों के नाम इंडिया टुडे के उसी कॉलम में खोलें, जिसमें उन्होंने ये मिथ्या भाषण किया है. अगर वो नाम खोलते हैं और एक गवाह उनके समर्थन में गवाही देने खड़ा होता है, क्योंकि पद्म पुरस्कार पाये इन तीनों पत्रकारों ने तो साफ मना कर दिया, तो मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं कितनी भी आशा करूं, शेखर गुप्ता का झूठ, झूठ रहेगा और नए पत्रकारों को, जो शेखर गुप्ता में कहीं एक बड़े पत्रकार की छवि देखते हैं, गुमराह करने में शेखर गुप्ता का व्यक्तित्व बड़ा काम करेगा, शायद मेरी क्षमा मांगने की इच्छा पूरी न हो पाए. ■

editor@chauthiduniya.com

अब अपने वादे पूरे कीजिए...

मेघनाद देसाई

जब एक नया रोमन सम्राट अपने विजय रथ पर सवार होकर रोम की गलियों से निकल रहा था, तो वहां खड़े लोग उसका स्वागत कर रहे थे. तभी सम्राट के पीछे खड़े एक शख्स ने उसके कान में कहा कि यह समय हमेशा नहीं रहेगा. किसी लोकतंत्र में यह बात आम जनता कहती है. दिल्ली के मतदाताओं ने एक चौंकाने वाला संदेश दिया है. सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को छोड़कर आज तक कोई भी राजनीतिक दल 95 फ़ीसद सीटें हासिल नहीं कर सका और न किसी राज्य में पूर्व में सत्ता में रहे किसी राजनीतिक दल के 90 फ़ीसद उम्मीदवारों की जमानत ज़ब्त हुई. यदि आम आदमी पार्टी ने खुद को पुनर्जीवित किया है और कांग्रेस ने आत्मविनाश (जिसमें बेशक राहुल गांधी का कुसूर नहीं है) किया है, तो भाजपा इस मायने में भाग्यशाली है कि उसे देश के चुनावी चक्र में बहुत जल्द एक बड़ी चेतावनी मिल गई है.

67 के मुक़ाबले तीन के आंकड़े को कम करके नहीं आंका जा सकता. पहली बात अरविंद केजरीवाल को यह याद रखनी चाहिए कि वह इस कामयाबी को हलके में नहीं ले सकते. इस बार उन्हें दिल्ली की सड़कों पर धरना देकर ट्रैफिक जाम करने के बजाय अच्छा शासन देना है. उन्हें एक दूसरा मौक़ा मिला है, जो किसी और को विरले ही मिलता है. उन्हें साबित करना है कि वह एक सक्षम प्रशासक हैं. हालांकि, यह कामयाबी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सत्ता पर कब्जा करने का लालच पैदा कर सकती है, जैसा कि पिछली बार हुआ था. आम आदमी पार्टी इसलिए जीती, क्योंकि यह दिल्ली की पार्टी थी. यह दिल्ली के इतिहास में पहली पार्टी थी, जिसे राष्ट्रीय पार्टियों ने बहुत छोटी चुनौती समझा. जब शीला दीक्षित बहुत अधिक कामयाब हो गईं और वंशवाद पर ख़तरा मंडराने लगा, तो कांग्रेस ने उनके पर कतर दिए. वहीं भाजपा यह फ़ैसला नहीं कर पाई कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी के रहते एक मुख्यमंत्री की ज़रूरत है या नहीं? केवल आप ही ऐसी पार्टी थी, जिसने एमसीडी की तरह जनता को परेशान करने के बजाय ज़मीनी स्तर पर दिल्ली के हितों की बात की.

केजरीवाल को अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करके दिल्ली को रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनाने की कोशिश करनी चाहिए. यहां भीड़भाड़ बढ़ गई है, हर जगह अवैध रूप से खड़ी गाड़ियां नज़र आती हैं, प्रदूषण की हालत बीजिंग से भी बदतर है. कचरा इकट्ठा करने और उसे ठिकाने लगाने के लिए कोई खास सुविधा मौजूद नहीं है. बिजली के बिल के अतिरिक्त भी दिल्ली में करने के लिए बहुत कुछ है. झुग्गी–झोंपड़ियों को नियमित करने और ग़रीबों के लिए सस्ता पेयजल मुहैय्या कराने जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है. ग़रीब आदमी को पीने का पानी खरीदना पड़ता है, जबकि मध्य वर्ग को सस्ता मिलता है. महिलाओं की सुरक्षा पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है. जहां तक भाजपा का सवाल है, तो उसे कांग्रेस की तरह व्यवहार करना छोड़ देना चाहिए. शीर्ष नेतृत्व के बचाव में सफाई नहीं देनी चाहिए. अगर भाजपा जीत गई होती, तो सारा श्रेय मोदी और अमित शाह के हिस्से में गया होता. उन्हें अब सामने आकर हार की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, जो एक नेता की पहचान होती है. विपरीत परिस्थितियां आदमी को बहुत कुछ सिखाती हैं.

2002 के बाद मोदी को पहली चुनावी हार का सामना करना पड़ा है. उन्हें पूछना चाहिए कि ग़लती कहां हुई? क्या पार्टी मोदी मैजिक पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर हो गई थी? दिल्ली में जो नारे लग रहे थे, उसके केंद्र में केवल मोदी थे. जिनमें न कोई वादा था और न कोई योजना. केवल दिल्ली में स्थिरता के लिए मोदी को वोट दें. बाक़ी सब खुद हो जाएगा, क्योंकि हम केंद्र में सत्ता में हैं. यह संदेश कि भाजपा जब तक सत्ता में नहीं आएगी, तब तक दिल्ली को किसी अच्छी योजना की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, प्रधानमंत्री के संघीय सहयोग के विजन का मज़ाक उड़ाता है. भाजपा ने मई 2014 के बाद होने वाले चुनावों का आकलन नहीं किया. पार्टी को महाराष्ट्र में बहुमत नहीं मिला और वह जम्मू–कश्मीर में भी सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन सकी. भाजपा संघ परिवार को अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ ज़हर उगलने से नहीं रोक सकी और न अपने सांसदों एवं मंत्रियों को अनुशासित करके भड़काऊ भाषण देने से रोक सकी. केवल एक व्यक्ति का करिश्मा पार्टी को हमेशा जीत नहीं दिला सकता.

अभी भारतीय जनता पार्टी को चुनावी वादे भी पूरे करने हैं. शेयर बाज़ार का संवेदी सूचकांक ही एक ऐसी जगह है, जहां अच्छे दिन आ गए हैं. बाकी सारा देश अच्छे दिनों का इंतज़ार कर रहा है. मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत की तरह एक नारा है. सवाल यह है कि उक्त नारे हक़ीकत में कब और कितनी जल्द परिवर्तित होंगे. दिल्ली के नतीजों ने विपक्ष को खुश कर दिया है. राज्यसभा की कार्यवाही अब और अधिक बाधित होगी. जो अध्यादेश लाए गए हैं, अब उन्हें आसानी से पारित नहीं कराया जा सकता है. फिलहाल भाजपा को राज्यसभा में जल्द बहुमत हासिल करने की आशा छोड़ देनी चाहिए. अब आवश्यकता यह है कि सबका विकास (जिस मुद्दे पर मोदी जीतकर आए थे) के मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाने के लिए सरकार अपने रवैये में नरमी लाए, क्योंकि सबका साथ में विपक्ष को भी शामिल करना होगा. ■

नुकसानदायक है दर्द निवारक दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल

चौथी दुनिया ब्यूरो

दर्द निवारक दवाओं का प्रयोग कभी न कभी सभी करते हैं. आजकल बिना डॉक्टर की सलाह के ही पेनकिलर्स लेने का प्रचलन बढ़ गया है. भाग–दौड़ की ज़िंदगी में सिर, घुटना, कमर, पीठ दर्द होना आम बात हो गयी है. इसी कारण दर्द निवारक दवाओं की बिक्री भी बहुत बढ़ गयी है. असल में ये दर्द कोई रोग नहीं हैं, बल्कि रोग के लक्षण हो सकते हैं. अनुभवी चिकित्सक दर्द के कारणों का पता लगा कर उस रोग का इलाज करते हैं, जबकि कुछ कथित डॉक्टर सीधे दर्द निवारक दवाएं दे देते हैं. इससे रोगी को तुरंत आराम तो मिल जाता है, लेकिन धीरे–धीरे वह इन दवाओं का अभ्यस्त हो जाता है.

पेनकिलर्स या दर्द निवारक दवा वे दवाएं हैं, जिनका इस्तेमाल दर्द से राहत पाने में किया जाता है. यह दो तरह से काम करती हैं. पहला ब्रेन की ओर जाने वाले दर्द के सिग्नल को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे रोगी को दर्द का अहसास नहीं हो पाता और दूसरा ब्रेन में सिग्नल के इंटरप्रिटेशन सिस्टम में छेड़छाड़ कर देती हैं और रोगी को लगता है कि उसे दर्द से राहत मिल गई. दर्द निवारक दवाएं दो प्रकार की होती हैं–नशीली (नारकोटिक्स) और गैर नशीली (नॉन नारकोटिक्स). नशीली दर्द निवारक तेज़ असरकारक होते हैं. इनकी लत लगने की आशंका के साथ इनके हानिकारक प्रभाव भी होते हैं. इसलिए इन्हें चिकित्सक की पर्ची से ही प्राप्त किया जा सकता है.

ग़ैर नशीली दवाओं में एस्पिरीन, क्रोसीन, पेरासिटामॉल, इबु–प्रोफेन, नीमुलेसाइड प्रमुख हैं, जिनका बिना डॉक्टर की सलाह या पर्ची के बहुत प्रयोग होता है. कुछ तीव्र रसायन वाली दर्द निवारक दवाएं जैसे डायक्लोविन प्लस के अधिक इस्तेमाल से लिवर ख़राब होने का ख़तरा बढ़ जाता है. इस हरी पन्नी वाली गोली का विज्ञापन टी.वी. पर दिखाया जाने लगा था, जिसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की आपत्ति के बाद बंद किया गया, लेकिन तब तक इसका काफी प्रचार हो चुका था. इस गोली की मांग इतनी बढ़ गई कि यह आज किराने की दुकानों पर भी उपलब्ध है. नियमानुसार यह दर्द निवारक गोली चिकित्सक की पर्ची पर ही मिलनी चाहिए और किराने की दुकानों पर इसे बेचा जाना दंडनीय अपराध है, लेकिन यह सरेआम बिक रहा है और औषधि नियंत्रक विभाग चुप है. साराडॉन और डिस्प्रिन जैसी दवाइयों के भी विज्ञापन बहुत दिखाए जाते हैं. बिना जाने विज्ञापन देख कर ये दवाइयां ले रहे लोग यह नहीं जानते कि इनके नियमित सेवन से शरीर पर कितना बुरा असर पड़ता है. पेनकिलर्स के आकर्षक विज्ञापन आज भी बिना रोक–टोक के दिखाए जा रहे हैं, जिसे सच मान कर सामान्य आदमी बिना इसके दुष्प्रभाव जाने इन दवाओं का सेवन कर रहा है.

इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज के एक अध्ययन के अनुसार, लगभग 317 भारतीय खुद से दवा लेते हैं. बड़े स्तर पर ओवर द काउंटर यानी ओटीसी दवाएं मौजूद हैं. लोगों को यह रास्ता अधिक आसान और सस्ता लगता है. पेरासिटामॉल जैसी दवा विभिन्न नामों से केमिस्ट की दुकान पर बगैर डॉक्टर की पर्ची के मिल जाती है और लोग बिना सोचे–समझे इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके लीवर को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है.

सर दर्द, हलके–फुल्के बदन दर्द, यहां तक की दांत में दर्द होने पर भी लोग बिना डॉक्टर की सलाह के पेनकिलर्स खा लेते हैं, ये सोचकर कि दर्द ठीक हो जाएगा. कुछ समय के लिए इससे आराम भी मिल जाता है, लेकिन अगर ऐसी दवाओं को रोज ही लेने की आदत पड़ जाए तो न केवल यह शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, बल्कि इससे होने वाले साइड इफेक्ट्स से जान का खतरा भी हो सकता है. क्रोसिन, कॉम्बिफ्लैम, डिस्प्रिन या ब्रूफिन आमतौर पर सबसे लापरवाही से खा ली जाती हैं. कुछ पेनकिलर्स ऐसे भी हैं, जिनको अगर बिना उचित सलाह के अपनी मर्ज़ी से खाया जाए तो उनपर निर्भरता बहुत अधिक बढ़ जाती है. यानी इनकी लत लग जाती है, जिससे और कई बीमारियां हो सकती हैं.

साधारण से दर्द को ठीक करने की कोशिश में लोग बिना डॉक्टर की सलाह के अनाप–शनाप दवाएं खाने लगे हैं, जिससे के एडिक्शन की खतरनाक बीमारी हो सकती है. पेनकिलर्स दर्द में तुरंत राहत पहुंचाती हैं. यही वजह है कि इंसान जरा–सी दिक्कत होते ही उनका इस्तेमाल करने लगता है और धीरे–धीरे उसे इनकी आदत पड़ जाती है. लंबे समय तक इस्तेमाल करने से दिमाग व शरीर इन दवाओं पर निर्भर करने लगते हैं. इस स्थिति को एडिक्शन

यानी लत कहते हैं. एक बार यदि व्यक्ति नियमित रूप से पेनकिलर्स लेना शुरू कर दे तो फिर उसका शरीर दवा का आदी हो जाता है और उसे लिए बगैर चैन नहीं मिलता. यदि कभी इन दवाओं को लोग बंद भी करना चाहें और अचानक बंद कर दें तो इनके विदड्रॉल सिम्पटम के कारण अनेक समस्याएं उठ खड़ी होती हैं. जैसे–हाथ पैरों का कांपना, बैचैनी, गुस्सा, डायरिया, छींकें, अनिद्रा, नाक से पानी बहना आदि. अगर रोगी को पेनकिलर का एडिक्शन हो गया है तो उसे मनोचिकित्सक से इलाज करवाने की ज़रूरत होती है . इसमें रोगी को नशामुक्त होने की तरह से ही कुछ समय इलाज करवाना पड़ता है और कुछ समय में रोगी ठीक हो जाता है. कुछ रोगियों को नशा मुक्ति के इलाज़ के साथ–साथ काउंसिलिंग की भी ज़रूरत होती है. आमतौर पर इस पूरी प्रक्रिया में 4–6 माह लगते हैं. दर्द कम करने के लिए ली जाने वाली कोई भी दवा सिर्फ उतने समय तक ही ली जानी चाहिए, जब तक डॉक्टर ने कहा हो. एक बार दर्द खत्म होने के बाद दवा लेना बंद कर देने में ही भलाई है. दर्द निवारक दवाइयां शौकिया तौर पर बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए.

साइडइफेक्ट्स

पेन किलर्स के ज़्यादा प्रयोग से सीने में जलन, पेट दर्द, खट्टी डकारें और उलटी आने की समस्याएं होने लगती हैं. इसके बाद धीरे–धीरे पेट में सूजन आ जाती है और उसमें घाव बनने लगते हैं. कुछ पेनकिलर्स में मौजूद एसिटामिनोफेन के इस्तेमाल से लिवर डैमिज होने का खतरा काफी ज्यादा होता है. ज्यादा पेनकिलर्स खाने से किडनी भी खराब हो सकती है. पेनकिलर्स लगातार लेते रहने से किडनी और लिवर में जहर बन सकता है, जिससे पेट में ब्लीडिंग भी हो सकती है. दर्द निवारक दवाओं के अधिक सेवन से अब लोगों में अल्सर के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं. पेनकिलर्स हाइपर एसिडिटी का कारण भी बनते हैं. इसके अलावा सुस्ती, मुंह सूखना, अचानक ब्लड प्रेशर कम होना और कब्ज जैसी शिकायतें भी हो सकती हैं. कई बार चरम परिस्थिति में कन्फ्यूजन और भ्रम की स्थिति, बेहोशी, धीमी हार्ट रेट, तेज हार्ट रेट, मांसपेशियों में जकड़न, यूट्रस में दिक्कत और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की स्थिति भी आ सकती है.

सावधानी बरतें

किसी तरह का दर्द होने पर डॉक्टर की पहले की दी हुई दवा न लें. इस प्रवृत्ति के कारण दवाओं का साइड इफेक्ट् बढ़ जाता है. अधिकांश पेनकिलर्स को खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है. इसे खाली पेट न खाएं. पेनकिलर्स और शराब दोनों से एसिडिटी बनती है, इसलिए दोनों को अगर एक साथ लिया जाय तो एसिडिटी बढ़ सकती है. शराब और पेनकिलर्स को एक साथ लेने से हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है. अगर किसी बीमारी के कारण आप पेनकिलर्स का नियमित सेवन करते हैं तो शरीर में पानी की कमी न होने दें. कम पानी पीने से किडनी से विषाक्त पदार्थ नहीं निकलेंगे और किडनी खराब हो सकती है.

सामान्य तौर पर एक बार में एक से अधिक पेनकिलर नहीं लेनी चाहिए. दर्द कितना भी तेज हो या कैसा भी हो, बिना अपने डॉक्टर की सलाह के पेनकिलर की मात्रा न बढ़ाएं. याद रखें ये केमिकल्स हैं, जिसे बिना डॉक्टरी सलाह के अधिक मात्रा में लेने से आपके शरीर को जानलेवा नुकसान भी हो सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

हिटलर को मात दे रही थीं बोरेल

अरुण तिवारी

एंड्री बोरेल का जन्म पेरिस के नजदीक लाउवेंसिनेस में 18 नवंबर, 1919 को एक साधारण परिवार में हुआ था. वे बचपन से ही काफी तेजतर्रार थीं और स्कूली शिक्षा के अलावा पर्वतारोहरण में भी काफी दिलचस्पी लिया करती थीं. उन्होंने 14 साल की कम उम्र में स्कूल छोड़कर बेकरी शॉप में नौकरी कर ली.

जब दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो 19 वर्षीय बोरेल नर्स बनने की शिक्षा लेने के लिए मेडिटेरेनियन पोर्ट सिटी चली गईं. अपनी ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने विश्व युद्ध में जख्मी सैनिकों का इलाज करने में डॉक्टरों की मदद करना शुरू किया. इस दौरान वे सैनिकों से अपने अच्छे व्यवहार और उनका अच्छे से ख्याल रखने के कारण उन सैनिकों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई थीं. जब 1940 में जर्मनी के हाथों फ्रांस की हार हो गई तो मार्शल पीटेन को देश की कमान दे दी गई तो बोरेल ने उस समय फ्रांस में उस गुट को ज्वाइन किया, जो जर्मनी का विरोध कर रहा था. दरअसल, उन्हें अपने देश की हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी. फ्रेंच रेजिस्टेंस के साथ मिलकर उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों का साथ देना शुरू कर दिया. उन्होंने स्पेन की सीमा के पास अपना ठिकाना बनाकर जर्मनी के खिलाफ अपनी गतिविधियां शुरू कर दीं.

साल 1941 में बोरेल के विद्रोही ग्रुप की जानकारी नाजी सरकार को मिल गई. नाजियों को इस बात की पूरी जानकारी मिल गई कि किन जगहों से उनकी सरकार के खिलाफ विरोधी मुहिम चलाई जा रही है. नाजी सैनिकों ने बोरेल के ठिकाने के आसपास अपनी गतिविधियां बढ़ा

दीं. पकड़े जाने की भनक लगते ही बोरेल वहां से गोपनीय रूप से भाग निकलीं. वे फ्रांस से छिपते–छिपाते पुर्तगाल पहुंची. वहां पर उन्होंने फ्री फ्रेंच प्रोपगेंडा नामक संस्था के साथ काम करना शुरू किया, जो फ्रांस को नाजियों के हाथों से मुक्त कराने के लिए काम कर रही थी. इस संस्था के साथ उन्होंने कुछ समय तक काम किया. 1942

साल 1941 में बोरेल के विद्रोही ग्रुप की जानकारी नाजी सरकार को मिल गई. नाजियों को इस बात की पूरी जानकारी मिल गई कि किन जगहों से उनकी सरकार के खिलाफ विरोधी मुहिम चलाई जा रही है. नाजी सैनिकों ने बोरेल के ठिकाने के आसपास अपनी गतिविधियां बढ़ा दीं. पकड़े जाने की भनक लगते ही बोरेल वहां से गोपनीय रूप से भाग निकलीं. वे फ्रांस से छिपते–छिपाते पुर्तगाल पहुंची. वहां पर उन्होंने फ्री फ्रेंच प्रोपगेंडा नामक संस्था के साथ काम करना शुरू किया, जो फ्रांस को नाजियों के हाथों से मुक्त कराने के लिए काम कर रही थी.

में वे लंदन चली गईं. यहीं पर उन्होंने स्पेशल ऑपरेशन एक्जिक्यूटिव के साथ प्रशिक्षण हासिल किया और फ्रांस की आजादी के लिए एक बार फिर से पूरे उत्साह के साथ काम करना शुरू किया.

24 सितंबर, 1942 को बोरेल पहली महिला बनीं, जिन्हें नाजी अधिकृत फ्रांस में मित्र राष्ट्रों की ओर से जासूसी के लिए उतारा गया. वहां पर सहयोगियों द्वारा उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया. बोरेल ने पेरिस में कूरियर नेटवर्क के जरिए जानकारियां पहुंचानी शुरू कर दीं. मित्र राष्ट्र बोरेल के जरिए नाजी सेनाओं को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे. बोरेल पेरिस की गली–गली से वाकिफ थीं. उन्होंने संगठन और खुद के नेटवर्क के जरिए खुफिया जानकारियां जुटाकर लंदन भेज रही थीं, जिसके जरिए नाजी सेनाओं को मात खानी पड़ रही थी. स्पेशल ऑपरेश ग्रुप के लिए काम करते हुए वे हथियारों को अपने सैनिकों तक सही तरीके से पहुंचाने में भी मदद कर रही थीं. उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्होंने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का फ्रांस में सेकंड इन कमांड बना दिया गया.

बोरेल के कारनामों से मिलती मात ने हिटलर को बौखला दिया था. जर्मनी से ये स्पष्ट आदेश दे दिए गए कि किसी भी कीमत पर बोरेल की गिरफ्तारी की जानी चाहिए. नाजी सेनाओं ने बोरेल के नेटवर्क को तोड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी और और बोरेल गिरफ्तार कर ली गईं. उन्हें वहां से नाजी कैंप ले जाया गया. काफी प्रताड़ना दी गई, जिससे वे नाजियों के सामने वो राज उगल दें, जो उन्होंने मित्र राष्ट्रों तक पहुंचाए थे, लेकिन 24 वर्षीय बोरेल ने कोई भी राज नहीं खोला. 6 जुलाई, 1944 को बोरेल व उनके साथियों को जहरीले इंजेक्शन के जरिए मौत की नींद सुला दिया गया.

आखिरकार, एक जांबाज महिला की मौत हो गई. एक ऐसी महिला, जो उस हिटलर के साथ डटकर मुकाबला कर रही थी, जिससे पूरी दुनिया घबराती थी.

feedback@chauthiduniya.com

आईएसआईएस का अंत

अमेरिकी राष्ट्रपति को अनुमति की दरकार

आईएसआईएस एक शक्तिशाली आतंकवादी संगठन है. इसको कुचलने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को विशेष अधिकार की आवश्यकता है, जिसे अमेरिका अमेरिकी कांग्रेस के सहयोग से हासिल करना चाहता है, ताकि आईएसआईएस पर सख्त कार्रवाई कर वह दुनिया को संदेश दे सके कि आतंकवाद के ख़िलाफ़ युद्ध में पूरा अमेरिका एक है.

वसीम अहमद

आईएसआईएस पर हमले के लिए व्हाइट हाइस ने अमेरिकी कांग्रेस को मसौदा भेज दिया है. अगर इस मसौदे को डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों की अनुशंसा प्राप्त हो जाएगी तो राष्ट्रपति ओबामा को तीन वर्ष के लिए आईएसआईएस के विरुद्ध दुनिया के किसी भी क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अधिकार मिल जाएगा. दरअसल, अमेरिकी संविधान के अनुसार, प्रशासन को किसी भी दूसरे देश में युद्ध शुरू करने की अनुमति केवल कांग्रेस ही दे सकती है. इस प्रकार की अनुमति पहली बार राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को मिली थी. उन्हें यह अनुमति 2001 में अमेरिका पर अलक़ायदा की ओर से हमला करने के बाद 2002 में दी गई थी. इस हमले में 3000 लोगों की जानें गई थीं. प्रतिक्रिया के रूप में अमेरिकी कांग्रेस ने बुश को यह अधिकार दिया था कि वह अगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई करके आतंकवादी संगठन अलक़ायदा का अंत कर दें. इस अधिकार का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति बुश ने अगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई की और अलक़ायदा का खात्मा कर दिया.

तत्कालीन राष्ट्रपति बुश को दिए गए इसी अधिकार को वर्तमान राष्ट्रपति ओबामा ने अपने लिए प्रयोग किया और पिछले वर्ष सितंबर में सहयोगियों के साथ मिलकर आईएसआईएस के ख़िलाफ़ सैन्य कार्रवाई शुरू की थी. हालांकि उनकी इस कार्रवाई पर सवाल भी उठते रहे कि दूसरे देश में सैन्य कार्रवाई का अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा को नहीं है, जबकि ओबामा प्रशासन ने यह औचित्य अपना रखा था कि जॉर्ज बुश के दौर में ही अमेरिकी राष्ट्रपति को दूसरे देशों में आतंकवादियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की अनुमति मिल चुकी है और ओबामा प्रशासन इसी अनुमति का प्रयोग कर रहा है.

ओबामा प्रशासन पिछले वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति को मिली अनुमति का फ़ायदा उठाते हुए आईएसआईएस के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दिया था. इस कार्रवाई में हल्के और मध्यम हथियारों का प्रयोग किया गया. अमेरिका इस जंग में ज़मीन पर उतरकर नहीं लड़ रहा था. वह हवाई हमले करके आईएसआईएस के ठिकानों को निशाना बनाता था, जबकि कुर्दिश सेना बशमर्गा ज़मीन पर आईएसआईएस का मुक़ाबला करती थी. आईएसआईएस को कमज़ोर करने के लिए अब तक अमेरिकी नेतृत्व में लगभग दो हज़ार से अधिक हवाई हमले किए गए, लेकिन अब अमेरिका को यह महसूस होने लगा है कि आईएसआईएस किसी साधारण शक्ति का नाम नहीं है. इसको हल्के या मध्यम हथियार से कम समय में कुचला नहीं जा सकता है. इसको कुचलने के लिए एक लंबे युद्ध की आवश्यकता है और इस युद्ध में अमेरिका को कड़ी रणनीति अपनानी होगी. इस लंबी जंग में अमेरिका को अपनी सेनाएं ज़मीन पर उतारनी पड़ सकती हैं और उसे उस समय तक आईएसआईएस से लड़ना होगा, जब तक कि उसका ख़ात्मा नहीं हो जाता. ज़ाहिर है यह एक बड़ी और जटिल समस्या है. अगर अमेरिकी सेना ज़मीन पर उतरती है और पूर्ण रूप से जंग में शामिल हो जाती है और जंग का सिलसिला लंबा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अमेरिकी कांग्रेस की ओर से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ेगा. इसलिए इन्होंने लंबी जंग शुरू करने से पहले कांग्रेस से विशेषाधिकार मिलने की स्वीकृति के लिए अपील कर दी है. कांग्रेस से अधिकार मिलने के बाद ओबामा प्रशासन अधिक विश्वास के साथ आईएसआईएस के लिए अपने सहयोगियों के साथ इसके विरुद्ध हवाई हमले जारी रख सकता है. यहां तक कि आईएसआईएस के ख़िलाफ़ ज़मीनी और समुंद्री जंग करने का अधिकार मिल जाएगा. व्हाइट हाइस ने कांग्रेस से अपील करते हुए स्पष्ट किया है कि आईएसआईएस अलक़ायदा से अधिक ख़तरनाक हो चुका है और अगर उसका ख़ात्मा नहीं किया गया तो अमेरिकी धरती पर भी ख़तरे का कारण बन सकता है. कांग्रेस के नाम राष्ट्रपति ओबामा के पत्र में ख़बरदार किया गया है कि तथाकथित इस्लामिक स्टेट ईराक, सीरिया और विस्तृत मध्यपूर्व की जनता और उनकी स्थिरता के अलावा अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी ख़तरा है. इस क्षेत्र में अमेरिकी नागरिक और प्रतिष्ठान भी सुरक्षित नहीं हैं. राष्ट्रपति ओबामा ने कांग्रेस से समर्थन की अपील करते हुए अमेरिकी नागरिकों की आईएसआईएस के हाथों विशेष उल्लेख किया और बताया कि इस आतंकवादी संगठन के ख़िलाफ़ जंग लड़ना क्यों ज़रूरी है. राष्ट्रपति ओबामा ने मसौदे में यह स्पष्ट किया है कि हम ईराक और अगानिस्तान में लंबे युद्ध जैसा रास्ता आईएसआईएस के ख़िलाफ़ नहीं चाहते हैं, लेकिन अल्पावधि के लिए युद्ध की अनुमति मिलनी चाहिए, ताकि इस सशक्त आतंकवादी संगठन का ख़ात्मा किया जा सके. अमेरिकी प्रशासन का यह एक अच्छा क़दम है और दुनिया से आतंकवाद को ख़त्म करना एक गंभीर समस्या है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अमेरिका जो काम अब करने जा रहा है अगर वह पहले ही कर लिया होता तो आईएसआईएस को फलने-फूलने का मौक़ा नहीं मिला होता और निर्दोष लोगों की जानें नहीं जातीं.

इसको समझने के लिए हमें अमेरिका की वर्तमान स्थिति का जायज़ा लेना होगा. पहली बात तो यह कि अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अनुमान नहीं था कि आईएसआईएस इतना शक्तिशाली है. वह यह समझते थे कि हल्के और मध्यम हथियारों के प्रयोग से ही उसका ख़ात्मा किया जा सकता है और न ही अमेरिकी प्रशासन को यह आभास था कि यह लड़ाई इतनी लंबी हो सकती है. दूसरा कारण यह है कि इस समय अमेरिका का ध्यान यूक्रेन की ओर है. वह यूक्रेन में लोकतंत्र की बहाली के लिए प्रयासरत है. अगर वहां राजनयिक स्तर पर कोई हल नहीं निकलता है तो ऐसी स्थिति में यूक्रेन को रूसी वर्चस्व से आज़ाद कराना अमेरिका की प्राथमिकता में शामिल होगा. अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी भारत यात्रा के दौरान इस ओर इशारा भी कर चुके हैं कि अगर यूक्रेन में कोई हल नहीं निकलता है तो दुनिया को यह जान लेना चाहिए कि यूक्रेन की सेना को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना बना दी जाएगी. यानी अमेरिका यूक्रेन को रूस के वर्चस्व से आज़ाद कराने के लिए अपनी ताक़त का प्रयोग कर सकता है. ऐसे में अगर वह इराक, सीरिया और आईएसआईएस के ख़िलाफ़ लंबी जंग में फंस जाता है तो अमेरिकी शक्ति द्विपक्षीय मोर्चे में बंट जाएगी. यही कारण है कि ओबामा अमेरिका को आईएसआईएस के ख़िलाफ़ किसी भी लंबी जंग में व्यस्त होने से बचाना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से बशमर्गा की सेना आईएसआईएस का मुक़ाबला नहीं कर सकी. नतीजे में आईएसआईएस का दायरा बढ़ता चला गया. न केवल ईराक व सीरिया, बल्कि लीबिया तक उसने अपनी पकड़ मज़बूत बना ली और ईसाइयों की हत्याओं का दौर चला. ऐसे में अगर आईएसआईएस के विरुद्ध युद्ध छिड़ती है तो इस जंग का दायरा लीबिया तक फैल सकता है. इसके अलावा आईएसआईएस के प्रभाव यूरोप के 22 देशों तक पहुंच चुके हैं. दूसरी ओर पाकिस्तान और अगानिस्तान में भी इसकी जड़ें मज़बूत हैं. अगाानिस्तान में अमेरिकी सेनाओं के सपोर्ट मिशन के कमांडर जनरल जोन कैंप बेल इस बात का संकेत दे चुके हैं कि आईएसआईएस की ओर से पाकिस्तान और अगानिस्तान में भर्तियां हो रही हैं. इसके बढ़ते क़दमों से दुनिया समेत अमेरिका का अपना हित भी खतरे में नज़र आने लगा है, जैसा कि राष्ट्रपति ओबामा ने कांग्रेस को भेजे गए मसौदे में उल्लेख किया है. लिहाज़ा, अब अमेरिका के लिए एक ही रास्ता रह जाता है कि वह आईएसआईएस को ख़त्म करने के लिए पूर्ण रूप से संलिप्त हो. यह स्थिति अमेरिकी कांग्रेस को भी महसूस हो रही है. इसीलिए इस मसौदे को पेंटागन से मंज़ूरी के संकेत मिलने लगे हैं और आईएसआईएस के ख़िलाफ़ ज़मीनी जंग के लिए 20 हज़ार सेना तैयार करने की बात कही जा रही है. इस प्रकार देखा जाए तो अब अमेरिका ने आईएसआईएस को ख़त्म करने के लिए कमर कस ली है और आईएसआईएस की ज़मीन तंग होना शुरू हो चुकी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

विदेश मंत्री कौन

पीएमओ या सुषमा स्वराज

मोदी सरकार की विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज, लेकिन एक विदेश मंत्री के तौर पर न तो उनके काम बोल रहे हैं और न ही मीडिया उनको तवज्जो दे रही है. कहा तो यहां तक जा रहा है कि विदेश मंत्रालय को साइलेंट कर सारे नीतिगत फैसले पीएमओ ले रहा है और पीएमओ के फैसले की जानकारी विदेश मंत्रालय को पहुंचाई तक नहीं जाती. ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब पीएमओ ही विदेश मंत्रालय का काम देख रहा है तो सुषमा विदेश मंत्री के तौर पर क्या कर रही हैं...

राजीव रंजन

पी वी नरसिम्हा राव, प्रणब मुखर्जी, यशवंत सिंह सहित अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कुछ ऐसे नाम हैं, जिन्होंने विदेश मंत्री के तौर पर भारत से अंतर्राष्ट्रीय संबंध को एक नये मुकाम तक पहुंचाया. ये मंत्री अपने मंत्रालय का काम बिना किसी रोकटोक के अंजाम देते थे, लेकिन मोदी सरकार की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है. सुषमा विदेश दौरे तो जरूर कर रही हैं, लेकिन अन्य देशों के साथ भारत को कहां तक मुकाम तय करना है, किस समय कौन निर्णय लेना है, इसका निर्णय कोई और ही कर रहा है. भले ही सुषमा स्वराज भारत सरकार में विदेश मंत्री हैं, लेकिन हाल के दिनों में सुषमा को कोई बडा फैसला लेते नहीं देखा गया और न ही मीडिया ने उन्हें कभी उचित कवरेज दिया. कहा तो यहां तक जाता है कि विदेश नीति संबंधी सारे निर्णय पीएमओ लेता है. सूत्रों का यह भी कहना है कि पिछले 6 महीने में विदेश मंत्रालय ने राजदूत और हाई कमिश्नर की नियुक्तियों पर जितनी सिफारिशें भेजीं, उनको पीएमओ ने कबूल ही नहीं किया. पूर्व डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी अडवाइजर नेहचल संधु को हटाने का मसला हो या विदेश सचिव सुजाता सिंह की बर्खास्तगी के बाद उनकी जगह अमेरिका में भारतीय राजदूत सुब्रमण्यम जयशंकर की नियुक्ति का मसला हो, सारे फैसलों पर हरी झंडी मिली तो पीएमओ के इशारे पर. बताया जाता है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सुजाता सिंह को हटाने के पक्ष में नहीं थीं. सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और सुषमा स्वराज में सुजाता सिंह पर तनातनी की स्थिति थी. हालांकि मामला ज्यादा लंबा न खिंचे, इसलिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर बताया कि वह जयशंकर की नियुक्ति पर हुए फैसले में पूरी तरह से शामिल थीं. कहा तो यहां तक जाता है कि इस फैसले की जानकारी आधिकारिक तौर पर विदेश मंत्रालय को नहीं दी गई थी. मोदी सरकार द्वारा सुषमा स्वराज की जासूसी की भी मीडिया में खबरें सुनने को मिलीं.

सवाल यह उठता है कि एक विदेश मंत्री के तौर पर आखिर सुषमा स्वराज क्या कर रही हैं. यह सवाल इसलिए भी खडा हो रहा है, क्योंकि विदेश मंत्रालय से संबंधित छोटे नीतिगत फैसलों की भी जानकारी सुषमा या उनके मंत्रालय को नहीं दी जाती. सच्चाई तो यह है कि मोदी विदेश नीति पर शुरू से ही काफी संजीदा हैं. जिस तरह से अपने शपथ ग्रहण समारोह में अपने पडोसी देशों को उन्होंने बुलाया और प्रमुख देशों की यात्रा की, उससे यह साफ है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने विदेश नीति के विजन को अमलीजामा पहनाने की ठान चुके हैं. वास्तव में देखा जाए तो मोदी सरकार अपनी विदेश नीति को लेकर प्रो-एक्टिव होना चाहती है, क्योंकि वह यूपीए सरकार की ढुलमुल विदेश नीति को हरगिज नहीं अपनाना चाहती. यही कारण है कि मोदी अपने सरकार की विदेश नीति को मुख्य रूप से चार कसौटियों पर कस कर चल रहे हैं.

पहला, अमेरिका से संबंधों को मजबूत बनाना, जापान से रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करना, पड़ोसी चीन से संवाद में सीमा से जुड़े मसलों के साथ-साथ व्यापारिक संबंधों पर खास फोकस देना और साउथ एशिया के पड़ोसी मुल्कों से फिर से रिश्तों में नई जान फूंकना.

सुषमा के मंत्रालय को साइलेंट करना या फैसला लेने के अधिकारों से वंचित करना यह बताता है कि मोदी सरकार को सुषमा या उनके अधिकारियों के फैसले पर विश्वास नहीं है. मोदी सरकार का यह फैसला अनायास नहीं है, क्योंकि पूर्व के विदेश मंत्रियों के कार्यों पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि उन्होंने अपने हूनर और कार्यों से खुद को प्रूफ किया और उनके मंत्रालय का कामकाज सरकार के सिर चढकर बोला. प्रणब मुखर्जी जब विदेश मंत्री थे तो अमेरिकी सरकार के साथ असैनिक परमाणु समझौते पर भारत-अमेरिका के सफलता-पूर्वक हस्ताक्षर और परमाणु अप्रसार सन्धि पर दस्तखत नहीं होने के बावजूद असैन्य परमाणु व्यापार में भाग लेने के लिए परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के साथ हुए हस्ताक्षर जैसे कार्य किए. पी वी नरसिम्हा राव की विदेश मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 1981 में गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में उनकी भूमिका के लिए बहुत प्रशंसा की गई थी. श्री राव विशेष गुट निरपेक्ष मिशन के भी नेता रहे, जिसने फिलीस्तीनी मुक्ति आन्दोलन को सुलझाने के लिए नवंबर 1983 में पश्चिम एशियाई देशों का दौरा किया. अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने विदेश मंत्री रहते भारत-पाकिस्तान संबंधों को सुधारने का भरसक प्रयास किया. वाजपेयी के करीबी लोगों का कहना है कि वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास 70 के दशक में मोरारजी देसाई की सरकार में बतौर विदेश मंत्री रहते हुए ही कर दिए थे. इस तरह से हम देखें तो अपने पूर्व के विदेशमंत्रियों की तुलना में सुषमा स्वराज के कार्य कहीं नहीं ठहर पाते. इसके पीछे उनकी खुद ही नीतियां ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर वे खुद को प्रूफ कर पातीं तो मोदी सरकार उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए जरूर आने को कहती. ■

feedback@chauthiduniya.com

''शांत हो जाओ मैं समझ गया हूँ .ईश्वर तुम्हे मुक्ति प्रदान करें !'' गुरुदेव के इतना कहते ही बुलेट शांत हो गया और अपने स्थान पर जाकर बैठ गया .वहां उपस्थित प्रभात सहित उसके परिवारीजन यह देखकर चकित रह गए क्योंकि बुलेट को शांत करना वे सभी जानते थे कि बहुत मुश्किल होता है.थोड़ी देर बाद जब गुरुदेव ने अपना निर्धारित आसन ग्रहण कर लिया तब गंभीर व् अमृततुल्य वाणी में वे कोमल स्वर में बोले – ''आप सभी चकित हैं कि आपका प्रिय जीव मुझसे क्या कह रहा था ?

साई बाबा से जुड़ी कुछ कहानिया

चौथी दुनिया ब्यूरो

साई बाबा की चमत्कारिक कहानियों के पीछे जीवन से जुड़ी कोई न कोई शिक्षा या मर्म छिपा है. साई बाबा सशरीर भले ही धरती पर नहीं हैं लेकिन सच्चे भक्तों को हमेशा यह एहसास होता है कि साई बाबा उनके साथ हैं. साई बाबा से जुड़ी कुछ कहानियां जिनमें जीवन से जुड़े संदेश छिपे हैं.

भोजन में सभी प्राणियों का हिस्सा: शिरडी के लोग प्रारंभ में साई बाबा को पागल समझते थे लेकिन धीरे–धीरे उनकी शक्ति और गुणों को जानने के बाद भक्तों की संख्या बढ़ती गई. साई बाबा शिरडी के केवल पांच परिवारों से रोज दिन में दो बार भिक्षा मांगते थे.

वे टीन के बर्तन में तरल पदार्थ और कंधे पर टंगे हुए कपड़े की झोली में रोटी और ठोस पदार्थ इकट्ठा किया करते थे. सभी सामग्रियों को वे द्वारिका माई लाकर मिट्टी के बड़े बर्तन में मिलाकर रख देते थे. कुत्ते, बिल्लियां, चिड़िया आदि नि:संकोच आकर उस खाने का कुछ अंश खा लेते थे, बची हुए भिक्षा को साई बाबा भक्तों के साथ मिल बांट कर खाते थे.

कुत्ते का नहीं साई का अनादर: एक बार साई के एक भक्त ने साई बाबा को भोजन के लिए घर पर बुलाया. निश्चित समय से पूर्व ही साई बाबा कुत्ते का रूप धारण करके भक्त के घर पहुंच गए. साई के भक्तों ने अनजाने में चूल्हे में जलती हुई लकड़ी से कुत्ते को मारकर भगा दिया. जब साई बाबा नहीं आए तो उनका भक्त उनके घर पर जा पहुंचा. साई बाबा मुस्कुराये और कहा, मैं तो तुम्हारे घर भोजन के लिए आया था लेकिन तुमने जलती हुई लकड़ी से मारकर मुझे भगा दिया. साई भक्त अपनी भूल पर पछताने लगा और बाबा से माफी मांगी. साई बाबा ने स्नेह पूर्वक उसकी भूल को क्षमा कर दिया.

उदी की महिमा से संतान सुख: लक्ष्मी नामक एक स्त्री संतान सुख के लिए तड़प रही थी. एक दिन साई बाबा के पास वह अपनी विनती लेकर पहुंची. साईं ने उसे उदी यानी भभूत दिया और कहा आधा तुम खा लेना और आधा अपने पति को दे देना लक्ष्मी ने ऐसा ही किया. निश्चित समय पर लक्ष्मी गर्भवती हुई. साई के इस चमत्कार से वह साई की भक्त बन गई और वह जहां भी जाती साई बाबा के गुण गाती. साई के किसी विरोधी ने लक्ष्मी के गर्भ को नष्ट करने के लिए धोखे से गर्भ नष्ट करने की दवाई दे दी. इससे लक्ष्मी को पेट में दर्द एवं रक्तस्राव होने लगा. लक्ष्मी साई के पास पहुंचकर साई से विनती करने लगी. साई बाबा ने लक्ष्मी को उदी खाने के लिए दिया. उदी खाते ही लक्ष्मी का रक्तस्राव रुक गया और लक्ष्मी को सही समय पर संतान सुख प्राप्त हुआ.

साई के जीवन में गुरु का महत्व

साई बाबा के जीवन में उनके गुरु का क्या स्थान था, इसे उनके गुरु की निशानियों को देखकर बखूबी समझा जा सकता है. साई ने अपने गुरु की निशानियों को संभालकर रखा था. बाबा के गुरु की खड़ाऊं, उनकी चिलम और माला को उन्होंने बाबा के समाधि लेने के बाद भी संभाल कर रखा गया है.

साई की दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता. साई की दर पर जाने के बाद भक्तों की कोई मुराद कभी अधूरी नहीं रहती और बाबा के ये चमत्कार दिखाते हैं. उनका बटुआ: समाधि लेने के पहले भी बाबा इसी बटुए में हाथ डालकर अपने भक्तों को सोने–चांदी के सिक्के देकर उनके दुखों को दूर किया करते थे. साई बाबा की इस अनमोल धरोहर को आज भी संभाल कर रखा गया है.

शिरडी के साई बाबा की शरण से आजतक कोई झोली खाली नहीं लौटी. क्या अमीर, क्या गरीब, हर कोई साई की दर से हंसी खुशी ही लौटा है. साई का नाम सुनते ही बाबा के चमत्कार आंखों के सामने घूमने लगते हैं. कपड़े के उस बटुए के चमत्कार की कहानियां आज भी शिरडी के हर भक्त की जुबां पर हैं. इस बटुए की माया को आजतक कोई नहीं समझ पाया कि कैसे कोई फकीर अपनी शरण में आने वाले भक्तों को इस बटुए से सोने और चांदी के सिक्के निकालकर देते थे और वह बटुआ कभी खाली नहीं होता था.

कपड़े के इस चमत्कारी बटुए को साई बाबा ने उस वक्त उनके सबसे करीबी सेवक तात्या पाटिल और बायजा मां को साल 1918 में समाधि लेने से पहले सिक्कों के साथ दान कर दिया था. आज भी वे सिक्के इस बटुए के साथ सही सलामत हैं.

पाटिल परिवार ने जब से इस बटुए का रख रखाव शुरू किया तब से उनके परिवार पर लक्ष्मी की विशेष कृपा रही है.

समाधि लेने से पहले साई बाबा हर रोज इसी बटुए से सैंकड़ों सिक्के अपने भक्तों को दान किया करते थे, और तो और उस समय अंग्रेज शासकों ने साई बाबा के इस चमत्कार की जांच के आदेश भी दिए थे, लेकिन वह चमत्कार आज भी एक पहेली बना हुआ है. आज भी साई बाबा की शक्ति का ही कमाल है कि हर भक्त उनके दरबार से अपनी खाली झोली भरकर ले जाता है.

हफ्ते के सात दिनों में गुरुवार का दिन बाबा के नाम पर है. शिरडी में आज भी हर गुरुवार को साई की पालकी निकलती है, जिसके दर्शन करने लिए हजारों भक्तों की भीड़ लगती है. कहते हैं जिसने भी बाबा की इन निशानियों के दर्शन कर लिए उन्हें साक्षात साई के दर्शनों का सौभाग्य मिलता है.

शिरडी के साई बाबा हर गुरुवार को अपने भक्तों की समस्त तकलीफों को अपने साथ ले जाते हैं और बदले में मन की मुरादों से भक्तों की झोलीभर देते हैं. ये सिलसिला तब से चला आ रहा है, जब शिरडी में साई बाबा सबको दर्शन दिया करते थे.

द्वारका माई से चावड़ी तक आज भी हर गुरुवार को पालकी में साई खुद विराजते हैं. साई पहले साक्षात दर्शन देकर भक्तों के दु:ख दर्द दूर करते थे और अब साई का वही चमत्कार उनकी छड़ी और खड़ाऊं करते हैं.

साई के इस दिव्य रूप के दर्शन के लिए हर गुरुवार को उनके दरबार में लाखों श्रद्धालु जुटते हैं. सामधि लेने से पहले बाबा अपनी लाठी से छूकर भक्तों की सारी तकलीफें दूर किया करते थे और जब भक्तों के दु:ख से बाबा खुद निढ़ाल हो जाते तो अपनी चिलम जला लेते थे.

आज भी साई की पालकी जब चावड़ी पहुंच जाती है तो उनको चिलम चढ़ाई जाती है. ये चिलम सिर्फ श्रद्धा और आस्था का चढ़ावा ही नहीं है बल्कि साई के चमत्कारों से भी जुड़ी हुई है. साई की पालकी की इन खास रस्मों के दर्शन करने की मनाही किसी को नहीं है.■

feedback@chauthiduniya.com

साई के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दु:ख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

पाकिस्तान के खिलाफ जीत विश्वकप जीतने के बराबर

भारतीय टीम पिछले दो महीने से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थी. टीम इंडिया इस दौरान एक भी मैच नहीं जीत सकी. विश्व कप से पहले अभ्यास मैच में भी उसे ऑस्ट्रेलिया ने मात दी. भारतीय टीम को पहली सफलता अफगानिस्तान के खिलाफ अभ्यास मैच में मिली. इसके बाद विश्वकप के सबसे चर्चित भारत बनाम पाकिस्तान के मुक़ाबले पर सबकी नजरें टिक गईं. दोनों टीमों के लिए विश्वकप का आगाज इस बड़े मुकाबले से हुआ. भारतीय टीम ने आशानुरूप प्रदर्शन करते हुए. पाकिस्तान को एक बार फिर विश्वकप में मात दी और विश्वकप में पाकिस्तान के खिलाफ अजेय बनी रही. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया से हार कर टीम इंडिया ने लोगों को निराश कर दिया था. लेकिन इस जीत ने लोगों में एक नया उत्साह भर दिया है, मानो टीम इंडिया ने एक बार फिर विश्वकप जीत लिया हो. लोगों केजहन में एक बार फिर टीम इंडिया के विश्वविजेता बनने की आशायें प्रबल हो गई हैं.

– कार्तिकेय शुक्ला, *कानपुर*

सौर ऊर्जा को सरकार वरीयता दे.

अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा का दौरा भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा. इस दौरे के बाद भारत–अमेरिका संबंधों के एक नई ऊंचाई पर पहुंचने की बातें की जा रही हैं, लेकिन चौथी दुनिया में छपे आलेख में यह बताया गया कि जिस परमाणु समझौते को इस ओबामा के दौरे के दौरान अमली जामा पहनाया गया, उसमें अमेरिका फायदे में रहा. सरकार को अमेरिकी कंपनियों को जिम्मेदारी के अलग नहीं करना चाहिए था. सरकार की पहली जिम्मेदारी देश के लोगों का हित के लिए काम करना होती है. सरकार जिस तरह ऊर्जा के नए विकल्पों की तलाश कर रही है और परमाणु ऊर्जा के विकल्पों के रूप में परमाणु ऊर्जा को स्वीकार कर रही है. उसे उनकी जगह ऐसे विकल्पों को वरीयता देनी चाहिए जिनसे लोगों को होने वाला नुक्सान कम से कम या कहें नगणय हो. सरकार को सौर ऊर्जा को पहले विकल्प के रूप में चुनना चाहिए. जिससे देश कम निवेश से ज्यादा फायदा उठा सके.

– आमिर चौधरी , *ग्रेडर नोएडा*

मैकाले की शिक्षा नीति से अलग हो नई शिक्षा नीति

अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरूआत की थी. इस वजह से धीर–धीरे भारत की पारंपरिक शिक्षा पद्धति का अवसान हो गया. इसके नई शिक्षा के साथ सांस्कृतिक मूल्यों का हास होता गया. आजादी के 66 साल बाद भी हम अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति को ढो रहे हैं. हमने अपनी मौलिक शिक्षा पद्धति को पुनर्स्थापित करने की कोशिश नहीं की है. अब जब मोदी सरकार नई शिक्षा पद्धति लेकर आ रही तो उसे वर्तमान शिक्षा और पारंपरिक शिक्षा के बीच बेहतर संतुलन बनाना होगा. ताकि देश वैज्ञानिक विकास के साथ–साथ आपनी सांस्कृतिक विरासत को संजो कर रख सके और उसके विकास के लिए भी आगे भी बढ़ सके.

– विजय सिंह , *मैनपुरी (उ.प्र.)*

चुनाव और पैसा

राजनेता चुनाव में पैसा इसलिए खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें जनप्रतिनिधि बनना है. वे विधान सभा, लोकसभा या स्थानीय निकायों में जनप्रतिनिधि बनकर जनता की सेवा करने की बात करते हैं. बिना जनप्रतिनिधि बने ये कोई जनता की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि सेवा करना उनकी आदत में नहीं है, उन्हें आम जनता के प्रश्न पर आंदोलन करते नही देखा गया. उन्हें मज़दूर और किसानों की बात सिर्फ और सिर्फ चुनाव के दौरान ही करते देखा गया. ऐसे कितने ही प्रत्याशी हैं, जो निजी स्वार्थ के लिए, अपने काले धंधों को छुपाने के लिए और सरकारी अधिकारियों पर धौंस जमाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, एक बार चुनाव लड़ने के बाद नेता होने का लेबल इनके नाम के साथ जुड़ जाता है, जीतें या हारें, लेकिन फिर वो गैर क़ानूनी धंधे धड़ल्ले से कर सकते हैं, क्योंकि प्रशासन इनसे ख़ौफ़ खाएगा. तमाम नाजायज़ काम करने की उन्हें छूट मिल जाएगी, यह है देश में चुनाव लड़ने की मानसिकता. तमाम घाघ किस्म के लोग राजनीति को कितना भ्रष्ट और गंदा करेंगे, इसका अंदाजा नहीं लगया जा सकता है.

–राम मणि शर्मा, दिल्ली

नोटा को शक्तिशाली बनाया जाए

जब किसी क्षेत्र से किसी जन प्रतिनिधि को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाता है उसका मतलब यह प्रकट होता है कि उस व्यक्ति या उस पार्टी का कोई विरोध वहां नहीं है जबकि यथार्थ में स्थिति यह होती है कि यह चुनावी प्रबंधन का कमाल होता है. देखा गया है कि ऐसे निर्विरोध निर्वाचन हमेशा ही सत्तारूढ राजनीतिक दल के पक्ष में ही होते हैं. भय या लालच के सहारे अगर किसी को सत्तारूढ दल के प्रत्याशी के खिलाफ उम्मीदवार बनने से रोक दिया जाता है तो नोटा के वोट उस ज्यादती के संकेत दे सकते हैं. नोटा लोकतंत्र के प्रति सचेत और सक्रिय मतदाताओं को एक नया रास्ता दिखाते हैं. इसलिए मोदी सरकार को लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए नोटा को और शक्तिशाली बनाना चाहिए.

–वीरेन्द्र जैन, भोपाल

कहानी

पाप-पुण्य की कसौटी-एक लघु कथा

प्रभात के घर आज गुरुदेव आने वाले थे. गुरुदेव का सम्मान प्रभात का पूरा परिवार करता है. गुरुदेव ने ज्यों ही उनके मुख्य द्वार पर अपने चरण कमल रखे तभी वहीं पास में बैठा प्रभात का पालतू कुत्ता बुलेट उन पर जोर जोर से भौंकने लगा. गुरुदेव के उज्जवल मस्तक पर क्षण भर को कुछ लकीरें उभरीं और फिर होंठों पर मुस्कान. गुरुदेव ने स्नेह से बुलेट के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा– शांत हो जाओ मैं समझ गया हूं. ईश्वर तुम्हें मुक्ति प्रदान करें! गुरुदेव के इतना कहते ही बुलेट शांत हो गया और अपने स्थान पर जाकर बैठ गया. वहां उपस्थित प्रभात सहित उसके परिवारीजन यह देखकर चकित रह गए क्योंकि बुलेट को शांत करना बहुत मुश्किल होता है वे सभी जानते थे. लेकिन थोड़ी देर बाद जब गुरुदेव ने अपना निर्धारित आसन ग्रहण कर लिया तब गंभीर व अमृततुल्य वाणी में वे कोमल स्वर में बोले– आप सभी चकित हैं कि आपका प्रिय जीव मुझसे क्या कह रहा था? प्रभात ये जो श्वान योनि में है पिछले जन्म में ये एक सर्राफ था और तुम इससे उधार लेने वाले गरीब किसान. जब तुम उधार लौटाने इसकी गद्दी पर गर्मी में जाते तो ये तुम्हें बाहर धूप में इंतजार करवाता और खुद शीतल कमरे में बैठता इसीलिए आज ये तुम्हारे द्वार पर सर्दी–गर्मी के थपेड़े खाता है. पर तुम दयालु हो इसका ध्यान रखते हो... इसे खाने को देते हो ...सर्दी गर्मी में इसे लू–ठंड के थपेड़ों से बचाने का प्रयास करते हो क्योंकि कहीं न कहीं तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में पिछले जन्म में इससे लिए गए उधार का बोझ बना हुआ है. आज मेरे यहां प्रवेश करते ही ये जीव मुझसे कहने लगा–मुझे इस नारकीय जीवन से मुक्ति दिलवाइए! मैंने स्नेह से इसके मस्तक पर हाथ फेरा तो निज पाप कर्मों की अग्नि से तपती इसकी आत्मा को ठंडक पड़ी. और यह शांत भाव से बैठ गया. हम सभी के लिए यह एक उदाहरण है कि हमें अपना हर कर्म पाप–पुण्य की कसौटी पर कसकर ही करना चाहिए अन्यथा विधाता आपको दंडित अवश्य करेंगें! जय भोलेनाथ की !! गुरुदेव के यह कहते ही सब उनके चरणों में नतमस्तक हो गए.■

– शिखा कौशिक नूतन

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

> लंबू ने धीरे से सिगरेट का आखिरी कश खींचा और बचा हुआ फिल्टर दूर फेंक दिया, जो नहाकर निकले एक आदमी के कंधे के बगल से होता हुआ गिरा. कंधे पर गमछा रखे उस आदमी ने क्रोध से तीनों की ओर देखा और आगे बढ़ गया.मज़ा आ रहा है गुरु, चश्मे वाले ने किलकारी मारी और खड़ा होकर अंगड़ाई लेने लगा. उसके भीतर पिनक जाग गई थी. हां, माल वाकई तगड़ा था, मोटा भी उठ खड़ा हुआ.क्या हुआ? बइठो थोड़ी देर, लंबू ने कहा.

सलमान की कुंठा, नेमाडे पर निशाना

अनंत विजय

सलमान रश्दी, विश्व प्रसिद्ध लेखक. अपने लेखन, व्यक्तित्व और बयानों से विवादों में बने रहने वाले. ये वही सलमान रश्दी हैं, जिनकी किताब सैटेनिक वर्सेस के खिलाफ 14 फरवरी, 1989 को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खोमैनी ने मौत का फतवा जारी किया था, जिसके बाद वे वर्षों तक निर्वासन में रहे. इसके पहले 1984 में सलमान रश्दी ने ज़ॉर्ज ऑरवेल की अवधारणा को निगेट करते हुए विवादित लेख लिखा था. ऑरवेल लेखकों के राजनीति से अलग रहने की वकालत करते थे, लेकिन सलमान ने इस अवधारणा को खारिज करते हुए कहा था कि लेखन को राजनीति से मिलकर चलना होगा. हालांकि सलमान ने उस वक्त भी लेखन और राजनीति के मेल को घटिया करार दिया था, लेकिन उसको जरूरी भी बताया था. इस पर भी उन दिनों काफी विवाद हुआ था. इसी वक्त लगभग सलमान ने अमेरिकी उपन्यासकार मैरियन विगिन्स से शादी की, जो खासी विवादास्पद रही. उस दौर के अमेरिका के अखबार इस विवाद से रंगे रहते थे. अब ताजा विवाद उनके एक ट्वीट को लेकर पैदा हो गया है. उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा–ग्रम्पी ओल्ड बास्टर्ड, जस्ट टेक योर प्राइज एंड से थैंक यू नाइसली. आई डाउट यू हैव इवन रेड द वर्क यू अटैक. ये विस्फोटक ट्वीट उन्होंने किया था इस बार के ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता मराठी के वरिष्ठ लेखक भालचंद नेमाडे के बारे में. दरअसल, नेमाडे ने एक कार्यक्रम में सलमान रश्दी की किताब मिडनाइट चिल्ड्रन को औसत साहित्यिक कृति करार दिया था. नेमाडे ने कहा था कि सलमान रश्दी और वी एस नायपॉल पश्चिम के हाथों खेल रहे हैं. अपने उस बयान में नेमाडे ने अंग्रेजी के खिलाफ बहुत कुछ कहा था और उनके अपने तर्क थे. सलमान रश्दी को नेमाडे की बातें नागवार गुजरीं और उन्होंने भाषिक मर्यादा को ताक पर रखते हुए गाली–गलौच की भाषा में ट्वीट किया. सलमान रश्दी को शायद पता हो कि नेमाडे अंग्रेजी के ही शिक्षक रहे हैं और लंदन के मशहूर स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में शिक्षक रह चुके हैं तो सलमान रश्दी का ये संदेह बेकार है कि उन्होंने बगैर पढ़े उनके साहित्य को औसत कह दिया. भालचंद नेमाडे ने यह भी बताया था कि क्यों सलमान और नायपाल की रचनाएं पश्चिम के इशारे पर लिखी जा रही हैं. उनके अपने तर्क हैं, रश्दी को बजाए गाली–गलौच की भाषा इस्तेमाल करने के तर्कों के आधार पर नेमाडे की प्रस्थापना को काटना चाहिए था.

अब अगर सलमान रश्दी के लेखन की बात की जाए तो बहुत हद तक नेमाडे सही भी कह रहे हैं. पिछले दिनों उनकी किताब जोसेफ एंटन अ मेमोऑर प्रकाशित हुई थी. साढे छह सौ पन्नों के इस ग्रंथ में बोरियत की हद तक विस्तार दिया है. इसको खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन बेहद ऊबाऊ तो कहा ही जा सकता है. चंद दिलचस्प अंशों को छोड़कर, जहां वे अपने निर्वासन के दिनों का वर्णन करते हैं. पलायन इस संस्मरणात्मक किताब की सेंट्रल थीम है, लेकिन वे पाठकों को पलायन से नहीं रोक पाते हैं. इसी वजह से इस किताब को लेकर कहीं कोई उत्साह नहीं दिखा. निर्वासन के दौरान ही लिखा उनका उपन्यास द मूर'स लास्ट साय भी कोई खास प्रभाव पैदा नहीं कर पाया था और लंदन और अमेरिका के अखबारों में उसकी विध्वंसात्मक समीक्षाएं प्रकाशित हुई थी. नेमाडे ने पश्चिम के हाथों खेलने का जो आरोप लगाया है, वह कोई नया आरोप नहीं है तो इससे अब क्यों तिलमिला रहे हैं, यह समझ से परे है. रही बात वीएस नायपाल की तो उनको नोबेल पुरस्कार अवश्य मिला है, लेकिन उनके बाद के लेखन में खास किस्म का ह्रास देखने को मिलता है, जो रचनात्मक चमक मिस्टिक मैसअर, सफरेज ऑफ अलवीरा या मायगुल स्ट्रीट में दिखाई देती है, वो एन एरिया ऑफ डार्कनेस, इंडिया अ वूंडेड सिविलाइजेशन या इंडिया अ मिलियन म्यूटिनी नाऊ तक आते–आते निस्तेज होने लगती है. उम्र बढ़ने के साथ–साथ नायपाल के लेखन में एक ठहराव सा आ गया और विचारों में जड़ता भी. इस्लामिक जगत के जीवन का उन्होंने बहुत ही विवादास्पद चित्र खींचा है. बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने को जिस तरह से उन्होंने परोक्ष रूप से सही ठहराया, वह भी लेखकों के सामने है. गांधी के बारे में वे लिखते हैं कि उनमें किसी तरह की पूर्णता थी ही नहीं, उनका व्यक्तित्व यहां–वहां से उठाए टुकड़ों से निर्मित हुआ था. बिनावो के बारे मे लिखते हैं कि वे एक मूर्ख शख्सियत थे, जिन्होंने पचास के दशक में गांधी की नकल करने की कोशिश की. नीरद सी चौधरी को वे शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से बौना करार दे चुके हैं. तभी तो विलियम डेलरिम्पल ने लिखा है कि एक लेखक के रूप में नायपाल का अंत हो चुका है, जितना ज्यादा वे अपने अनुभवों के बारे में लिखते हैं, उनकी कलम उतनी ही नपुंसक होती जाती है.

दरअसल, अगर हम देखें तो सलमान रश्दी की नेमाडे को लेकर जो भड़ास है, वह भारतीय लेखकों का वैश्विक परिदृश्य पर बढ़ते दबदबे की परिणति है. पिछले लगभग एक दशक से जिस तरह से भारतीय लेखकों ने अंग्रेजी साहित्य में अपनी धमक कायम की, उससे सलमान और नायपाल के अलावा कुछ अंग्रेजी लेखक घबराए हुए हैं. उनकी पूछ और लोकप्रियता दोनों कम होने लगी है. जिस तरह से एशियाई लेखकों को पुलित्जर और बुकर मिलने लगे, उस पर अंग्रेजी लेखक एलेक्स ब्राउन ने कहा भी था कि हमें डर लगने लगा है. चंद वर्षों पहले तक भारत के बारे में अंग्रेजी लेखक संपेरों के देश से लेकर कुछ भी कह जाते थे, लेकिन बच जाते थे. अब उनको जवाब मिलने लगा है. ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, जब हॉवर्ड के प्रोफेसर और इतिहासकार नायल फर्ग्यूसन की किताब–सिविलाइजेशन, दे वेस्ट एंड द रेस्ट छपी थी तो पंकज मिश्रा ने लंदन रिव्यू ऑफ बुक्स में उसकी विध्वंसात्मक समीझा लिखी थी. पंकज ने साफ–साफ लेखक से पूछा था कि क्या महात्मा गांधी के बिना पिछली सदी की सभ्यता का मूल्यांकन संभव है. क्या चीन की उत्पादन क्षमता और भारत के टैक्नोक्रैट के योगदान को नजरअंदाज किया जा सकता है. तिलमिलाए नायल ने पत्रिका को लिखे अपने पत्र में कहा था कि पंकज मिश्रा ने उनके लेखन की तुलना अमेरिकी नस्लवादी सिद्धांतकार लॉथ्रॉप स्टोडार्ड की किताब द राइजिंग टाइड ऑफ कलर अगेंस्ट व्हाइट सुप्रीमेसी से की है. उन्होंन मिश्रा को कोर्ट आदि जाने की धमकी भी दी थी. लंदन रिव्यू ऑफ बुक्स में कई अंकों तक ये विवाद चला था, लेकिन पंकज मिश्रा डटे रहे थे और एलआरबी ने भी पंकज का ही समर्थन किया था. इस तरह के वाकयों से साफ है कि पश्चिम में रह रहे लेखकों को यह गंवारा नहीं है कि उनके अलावा कोई और लेखक सामने आए या उनके लेखन पर कोई सवाल उठाए

अगर हम विस्तार से वैश्विक अंग्रेजी साहित्य के परिवेश को देखें तो सलमान रश्दी के फ्रस्टेशन की वजह साफ हो जाती है. सलमान भारत आते–जाते रहते हैं, यहीं पैदा भी हुए हैं, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्रतिष्ठा का भी ज्ञान होगा. उन्हें चोट इस बात से पहुंची होगी कि इतने सम्मानित पुरस्कार से नवाजा गया लेखक उनके लेखन को औसत मानता है. इसी परेशानी में वे मर्यादा भूल गए और ट्वीट पर अपनी कुंठा को उड़ेल दिया. सलमान रश्दी ने अपने लेखन के नहीं पढ़े जाने की बात की है, उसमें मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाहूंगा कि क्या सलमान ने नेमाडे के साहित्य को पढ़ा है. अगर नहीं, तो पढ़ लें उन्हें एहसास हो जाएगा कि नेमाडे कितना सही कह रहे थे. आग्रह सिर्फ इतना है कि इस तरह की भाषा से उनकी छवि दरकती ही है, मजबूत नहीं होती. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

कहानी

लोकल

विमल चंद्र पांडेय

लंबू की अब दोस्त का कमरा खोजने की इच्छा मर गई थी और वह बाहर निकल कर वहां की सड़कों पर घूमने लगा. घूमता–घूमता वह थोड़ा आगे निकल गया. जब थक गया, तो सड़क के किनारे बैठ गया. अभी वह अपनी थकान मिटाकर आगे के क़दम के बारे में सोच पाता, तब तक एक गश्त लगाते पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया और थोड़ी दूर पर खड़ी पुलिस जीप के पास ले गया.

वहां उसने कुछ कहने की कोशिश की थी, लेकिन उसके हुलिये और चेहरे पर मार के निशानों ने पुलिस का मन भी चंचल कर दिया था. उसे दो–चार झापड़ और मारे गए और पूछा गया कि वह वहां क्यों बैठा है.

बताओ, कोई कहीं बैठे, तो भला इस बात का क्या जवाब दे सकता है कि वहां क्यों बैठा है, उसने दु:खी मन से दोनों की ओर देखते हुए कहा. फिर थोड़ी दूरी पर बैठे एक अधेड़ की ओर मुंह करके पूछा, जहां देहाती औरतों का एक झुंड नहाकर गुज़र रहा था, का हो चच्चा, इहां काहें बदे बइठल हउवा?

अधेड़ ने उसकी ओर हिकारत से देखा और बोला,...बदे बइठल हई.

वे तीनों समझ गए कि वह लोकल है और हंसने लगे.

लंबू ने आगे कहानी को समाप्त करते हुए बताया कि उस पूरी रात वह उस क्षेत्र में घूमता रहा और सुबह होते ही दोस्त के कमरे पर जाकर अपना बैग लेकर निकल आया.

वहां के लोग अपने आपको दुनिया का राजा समझते हैं. बाहरी आदमी की कोई इज्जत ही नहीं. हमारे सामने ही एक और आदमी को पकड़ा, जो दारू पीये था और बाइक से जा रहा था. वह मराठी में कुछ बोला, तो उसे सब आराम से जाने दिए. बाहरी लोगों के लिए वहां के लोगों के मन में कोई भावना नहीं. बेकार है. मसीन हैं सब उहां, कोई आदमी नहीं. लंबू कहानी के उपसंहार के बाद चुप हो गया और इंतज़ार करने लगा कि सिगरेट का आखिरी कश उसे दिया जाए. मोटे ने उसकी दृष्टि भांप कर हाथ उसकी तरफ़ बढ़ा दिया.

लंबू ने धीरे से सिगरेट का आखिरी कश खींचा और बचा हुआ फिल्टर दूर फेंक दिया, जो नहाकर निकले एक आदमी के कंधे के बगल से होता हुआ गिरा. कंधे पर गमछा रखे उस आदमी ने क्रोध से तीनों की ओर देखा और आगे बढ़ गया.

मज़ा आ रहा है गुरु, चश्मे वाले ने किलकारी मारी और खड़ा होकर अंगड़ाई लेने लगा. उसके भीतर पिनक जाग गई थी.

हां, माल वाकई तगड़ा था, मोटा भी उठ खड़ा हुआ.

क्या हुआ? बइठो थोड़ी देर, लंबू ने कहा.

चलोगे तो नसा भिनेगा, भिनेगा तो मजा आएगा, मोटे ने सलाह दी, तो लंबू भी उठ खड़ा हुआ. कर्नाटक से लौट आएंगे, उसने कहा.

ठीक है गुरु, चलो तो. दोनों ने रज़ामंदी दे दी.

वे दोनों घाट के ही रास्ते कर्नाटक स्टेट भवन की तरफ़ चलने लगे. मोटे ने काफ़ी देर से हाथ में ली हुई पन्नी ज़ोर से घुमाकर गंगा जी में फेंक दी.

क्या था बे?

मूर्ति था कई ठो भगवान का, टूट गया था.

जल पुलिस वालों की उद्घोषणा सुनाई दे रही थी, जो घाट के स्थायी भिखारी हैं, वे ही कृपया घाट पर रहें. बाहरी भिखारी घाट पर प्रवेश न करें. ध्यान से सुनें, बाहरी भिखारी घाट पर प्रवेश न करें.

दोनों ने ध्यान से सुना और लंबू की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, गोया घाट की सारी बातें उसे पता हैं.

अरे नहान वाले दिन बहुत बाहरी भिखारी आ जाते हैं, लंबू ने उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की.

तो?

अरे तो क्या, ऊ सब पइसा थोड़े देंगे. पुरनकन सब पइसा देते हैं, जब बइठने देती है जल पुलिस इनको सीढ़ी पे भीख मांगने.

इस जवाब से दोनों संतुष्ट हो गए और आगे की ओर बढ़ चले. सामने से दक्षिण भारतीय श्रद्धालुओं का एक दल आ रहा था, जिसमें कुछ महिलाओं ने सिर मुंडा रखा था.

औरतन काहे सब कपार छिलवा लेती हैं वहां की? मोटे ने झल्लाहट में पूछा. चश्मे वाला कुछ कहना चाहता था, लेकिन तब तक उसके मोबाइल पर फिर से मिस्डकॉल आ गई. लंबे वाले लड़के ने मोटे की ओर देखा, ई सब बहुत बिजंड भक्त होते हैं. पूरा इंडिया घूमते हैं नंगे पैर भक्ति के चक्कर में. यहां घाट पर सबसे ज़्यादा गंदगी साइथ इंडियनवे फइलाते हैं, तीसरे ने समूह को घूरते हुए कहा.

चश्मे वाला थोड़ा पीछे रह गया था और अपनी बात ख़त्म कर रहा था, एयरसेल आल इंडिया रोमिंग फ्री करने वाला है, तुम एयरसेल ले लेना और हम तुम कहीं रहें, बात कर सकेंगे.

उसने फोन की दूसरी तरफ़ वाले को खुशखबरी दी और तेज़ क़दमों से दोनों के पास आ गया. तभी दक्षिण भारतीयों के समूह में से एक आदमी ने अपने हाथ में पकड़ा फ्रूटी का पैकट खाली होने पर बगल में फेंक दिया, जहां पहले से काफी कूड़ा–करकट बिखरा हुआ था. चश्मे वाला कुछ कहने ही वाला था कि लंबू फुर्ती से श्रद्धालुओं के उस समूह के पास पहुंच गया.

इधर क्यों फेंका कचरा?

व्हाट? उस आदमी ने समझ न पाने की स्थिति में पूछा.

व्हाई इम्पटी पैकेट थ्रो हियर? दिस नॉट डस्टबीन. दिस गंगा मइया.

ओके, उस आदमी ने कहा और आगे बढ़ने लगा. लंबू को बुरा लगा. तब तक बाकी दोनों भी पास आ गए थे.

देख रहे हो? एक तो गंदगी फइलाते हैं और ऊपर से बोल रहे हैं, तो सुन भी नहीं रहा, लंबू ने आगे बढ़ते उस आदमी का हाथ पकड़ लिया था. वह आदमी शरीर से तगड़ा था. उसने अपना हाथ झटका, तो लंबू नीचे गिर पड़ा. उसके बाद का सब काफ़ी तेज़ी से हुआ. लंबू उठा और उसने उस आदमी को पीछे से एक लात मारी. आदमी अचानक हुए हमले से संभल नहीं पाया और गिर गया. उसके गिरते ही लंबू उसके ऊपर चढ़ गया और उसे पीटने लगा. मोटा भी आकर उसका साथ देने लगा. चश्मे वाले ने चश्मा जेब में रख लिया और उन दोनों के साथ उस आदमी पर पिल पड़ा.

उस आदमी के परिवार के लोग डर गए थे और शोर मचा रहे थे. जब तक घाट पर इधर–उधर से लोग दौड़कर आते, तब तक आदमी को वे तीनों मिलकर काफ़ी मार चुके थे. घाट के लोगों ने आदमी को तीनों की पकड़ से छुड़ाया और झगड़े की वजह पूछी. लंबू ने अपने कोण से घटना बयान की और बाकी दोनों ने उसके पक्ष में गवाही दी. कुछ बुज़ुर्ग लोगों ने श्रद्धालुओं को आगे जाने को कहा और लड़कों को डांटा. लगभग सभी लोगों का कहना था कि लोकल लड़के आजकल बहुत बदमाश हो गए हैं, लेकिन कुछेक लोगों का कहना था कि लड़कों ने ठीक किया है. बाहरी लोग आकर गंगा जी को बहुत दूषित कर रहे हैं.

वे तीनों सामान्य होकर फिर से कर्नाटक स्टेट भवन की ओर बढ़ चले थे. उनकी भंगिमाओं से अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि उनके साथ अभी कोई दुर्घटना हुई है. अचानक लंबू ने पीछे पलट कर पूछा, कौन बता रहा था कि एयरसेल ऑल इंडिया रोमिंग फ्री कर रहा है?

अख़बार में निकला था, मोटे ने जवाब दिया. ■

समाप्त

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

कंप्यूटर वायरस क्या है?

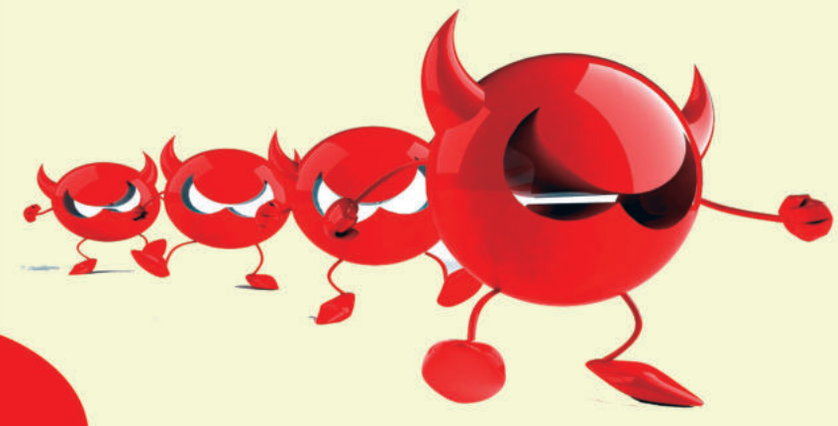

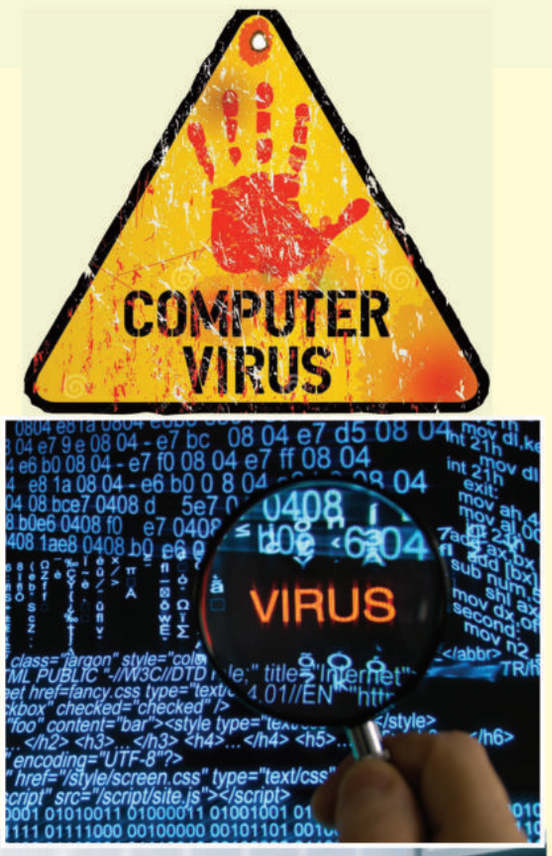

आज के इस तकनीकि दौर में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और टैब का इस्तेमाल आम बात है. लेकिन इनका उपयोग करने वालों सभी उपयोगकर्ताओ को वायरस का डर और इससे जुडी कुछ भ्रम का डर बना रहता है.

श्याम सुन्दर प्रसाद

कंप्यूटर वायरस का फुल फॉर्म वाइटल इनफार्मेशन रिसोर्सेज अंडर सिज़े (Vital Information Resources Under Seize) होता है. वायरस भी कंप्यूटर प्रोग्राम या कहें सॉफ्टवेयर होता है. यहां हम ये जानेंगे कि आखिर सॉफ्टवेयर होता क्या है? सॉफ्टवेयर एक या एक से अधिक कंप्यूटर प्रोग्राम का संग्रह होता है जिसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिये किसी विशेष कार्य को करने के लिए तैयार किया जाता है. अब सवाल उठता है कि प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम एक या एक से अधिक निर्देशों का संग्रह होता है, अब बात आती है कि निर्देश क्या होता है? निर्देश कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में (प्रोग्रामिंग लैंग्वेज) कंप्यूटर के कार्य करने के लिए दी गई सूचना होती है.

कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है जिसे मुख्य रूप से दूसरे प्रोग्राम के कार्य में अवरोध डालने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है. यह उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना उसके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है, सबसे खास बात यह है कि उपयोगकर्ता को इसका पता भी नहीं चलता है. विभिन्न प्रकार के मालवेयर (malware) और एडवेयर(adware) प्रोग्राम के संदर्भ में भी ***वायरस*** शब्द का उपयोग सामान्य तौर पर होता है, हालांकि ऐसा कभी–कभी भूल से भी होता है.

मूल वायरस मुख्य प्रोग्राम के कोड(प्रोग्रामिंग) में बदलाव कर सकता है, या कोड स्वयं अपने आप को न समाप्त होने वाले लूप में परिवर्तित कर सकता है. जैसा कि एक बदल सकने वाले वायरस में होता है. वायरस नाम सयोंगवश लोगों को बीमार करने वाले वायरस से मिलता है. लोगों को लगता है कि कंप्यूटर वायरस भी कंप्यूटर में आकर उसे बीमार कर देते हैं, या कहें उसकी सामान्य कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न करते हैं. यह बात कुछ हद तक तो ठीक है लेकिन वायरस का प्रमुख उददेश्य केवल कम्प्यूटर मेमोरी में एकत्रित आंकड़ों व संपर्क में आने वाले सभी प्रोग्रामों को अपने संक्रमण से प्रभावित करना होता है.

कम्प्यूटर वायरस कुछ निर्देशों का एक कम्प्यूटर प्रोग्राम मात्र होता है जो अत्यन्त सूक्षम किन्तु शक्तिशाली होता है. यह कम्प्यूटर को अपने तरीके से निर्देशित कर सकता है. ये वायरस प्रोग्राम किसी भी सामान्य कम्प्यूटर प्रोग्राम के साथ जुड़ जाते हैं और उनके माध्यम से कम्प्यूटरों में प्रवेश कर अपने उददेश्य अर्थात डाटा और प्रोग्राम को नष्ट करने या उसे संक्रमित करने के उद्देश्य को पूरा करते हैं. ये अपने संपर्क में आने वाले सभी प्रोग्रामों की प्रोग्रामिंग को प्रभावित कर देते हैं अथवा उसमें बदलाव कर देते हैं. वायरस से प्रभावित कोई भी कम्प्यूटर प्रोग्राम अपनी सामान्य कार्य शैली में कार्य नहीं कर पाता है. इसके काम करने में तरह तरह की रुकावटें आती हैं ये रुकावटें वायरस के प्रकार और उसकी कार्यप्रणाली पर निर्भर करती है. प्रत्येक वायरस प्रोग्राम कुछ कंप्यूटर निर्देशों का एक समूह होता है जिसमें उसके अस्तित्व को बनाएं रखने का तरीका, संक्रमण फैलाने का तरीका तथा हानि का प्रकार डिफाइन होता है. सभी कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम मुख्यतः असेंबली भाषा या किसी उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए जाते हैं.

जिस तरह बीमारी का वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैला है ठीक उसी तरह एक कंप्यूटर किसी भी माध्यम से दूसरे कंप्यूटर के संपर्क में आने से फैलता है. माध्यम कई हो सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट, पोर्टेबल डिवाइस (फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, और मोबाइल में उपयोग होने वाले डेटा कार्ड). इन्हीं के माध्यम से वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है. कभी–कभी कंप्यूटर वॉम(Worm) और ट्रोजन हॉर्स (trojan Horse) के लिए भी भ्रमपूर्वक वायरस शब्द का उपयोग किया जाता है. एक वॉम एक से दूसरे कंप्यूटर में खुद–ब–खुद फैल सकता है, इसे स्थानांतरित होने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है. ट्रोजन होर्स एक ऐसा प्रोग्राम है सामान्य तौर पर नुक्सानदायक नहीं होता है लेकिन यह कंप्यूटर सिस्टम के आंकडों, उसकी कार्यप्रणाली या कार्य को संपन्न करने के दौरान नेटवर्किंग को नुक़सान पहुंचा सकता है. सामान्य तौर पर, एक वॉम कंप्यूटर हार्डवेयर–सॉफ्टवेयर को नुक़सान नहीं पहुंचाता है, जबकि सिद्धांतिक रूप में एक ट्रोजन, कार्य के दौरान किसी तरह का नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं होता है. लेकिन जैसे ही संक्रमित कोड चलता है, ट्रोजन होर्स कंम्पयूटर में प्रवेश कर जाता है. यही कारण है कि लोगों के लिए वायरस और अन्य मालवेयर खोजना बहुत ही कठिन होता है, इसीलिए उन्हें इसके लिए स्पाईवेयर प्रोग्राम और पंजीकरण प्रक्रिया का उपयोग करना पड़ता है.

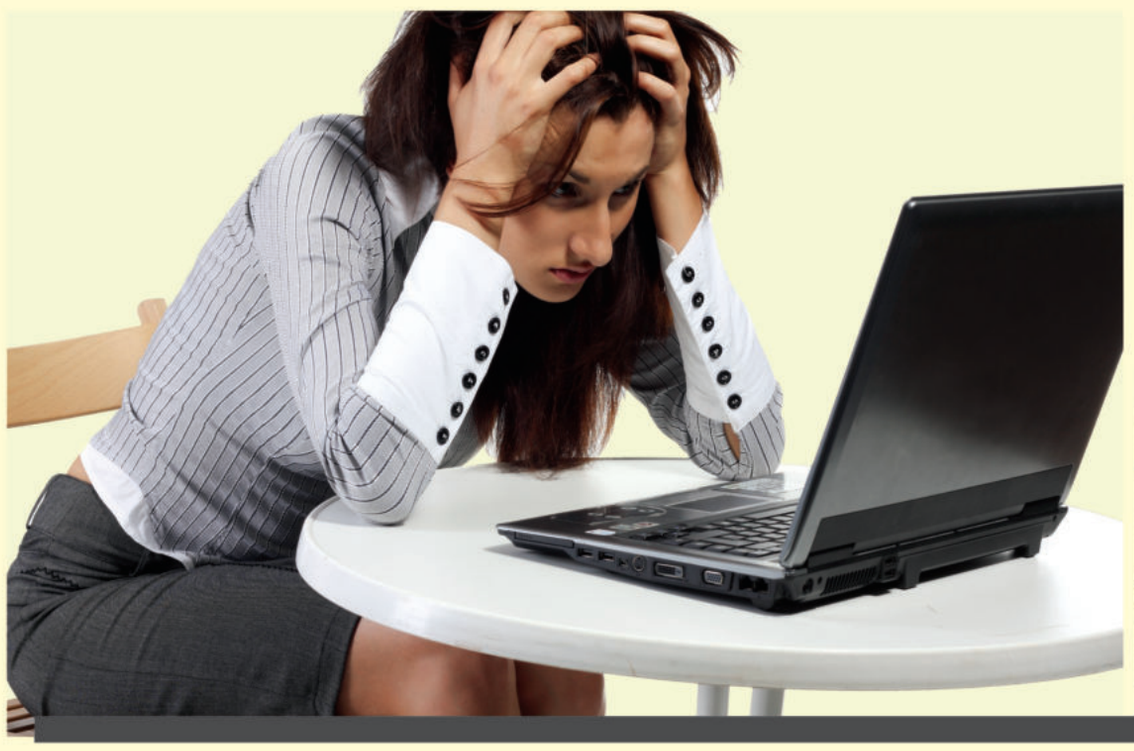

कम्प्यूटर वायरस कुछ निर्देशों का एक कम्प्यूटर प्रोग्राम मात्र होता है जो अत्यन्त सूक्षम किन्तु शक्तिशाली होता है. यह कम्प्यूटर को अपने तरीके से निर्देशित कर सकता है. ये वायरस प्रोग्राम किसी भी सामान्य कम्प्यूटर प्रोग्राम के साथ जुड़ जाते हैं और उनके माध्यम से कम्प्यूटरों में प्रवेश कर अपने उददेश्य अर्थात डाटा और प्रोग्राम को नष्ट करने या उसे संक्रमित करने के उद्देश्य को पूरा करते हैं. ये अपने संपर्क में आने वाले सभी प्रोग्रामों की प्रोग्रामिंग को प्रभावित कर देते हैं अथवा उसमें बदलाव कर देते हैं.

वायरस स्वयं को न खोज पाने के लिए और कंम्प्यूटर कार्यक्रमों को बर्बाद करने के लिए ही बनाए जाते हैं, ये काम मुख्य रूप से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट लोग ही करते हैं.विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ वायरस को वायरस फाइलों को हटाने या हार्ड डिस्क reformatting का ही इंतज़ार रहता है क्योंकि इन्हें इसी कार्य के लिए ही बनाया जाता है. कुछ मालवेयर डिस्ट्रक्टिव प्रोग्रामों, डेटा–डिक्शनरी को डिलीट करने या हार्ड डिस्क को पुनः फ़ॉर्मेट करने के दौरान कंप्यूटर को क्षति पहुंचाने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं. आमतौर पर मालवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर उपयोगकर्ता के लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं. वे आमतौर पर वैलिड(वैध) कार्यक्रमों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली कम्प्यूटर मेमोरी को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं. इसके परिणाम स्वरूप ये कंप्यूटर अचानक से अनियमित व्यवहार करने लगता है जैसे कि माउस का कर्सर अपने आप गति करने लगे या कंप्यूटर अचानक से हैंग हो जाये. इसके अलावा बहुत से मालवेयर बग (bug) से ग्रस्त होते हैं, और ये बग सिस्टम को नुक़सान पंहुचा सकते हैं या डाटा लॉस (data loss) का कारण हो सकते हैं. कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं, जो उपयोगकर्ता के सामने अपने आप अवतरित हो जाते हैं और अचानक से डाउनलोड हो जाते हैं, इस तरह के प्रोग्रामों की वजह से कंप्यूटर की स्पीड बहुत कम हो जाती है लेकिन इन्हें ढूंढ़ना और इसका समाधान करना बहुत कठिन होता है. ये वायरस कंप्यूटर उपयोगकर्ता के लिए लगातार समस्या पैदा करते हैं, सिस्टम पर ज्यादा दबाव पड़ने से यह क्रैश हो सकता है. इसके अलावा सहेजी गईं कई फाइल्स वायरस बग से ग्रस्त हो सकती हैं. इस वजह से डेटा की हानि हो सकती है.

वायरस के प्रकार

फाइल फैक्टर वायरस : ये वायरस कंप्यूटर में फाइल के एड्रेस को बदल देते हैं.

ट्रोजन हॉर्स : एक ट्रोजन बड़ी गुपचुप तरीके से आप के कंप्यूटर सिस्टम को संक्रमित कर देगा जो एक जान बूझ कर आपको परेशान करने के लिए बनाया गया प्रोग्राम है. ट्रोजन अन्य क्रम में सबसे ऊपर की श्रेणी में आता है. यूजर की जानकारी के बिना एक सिस्टम में सेव हो जाता है. ट्रोजन को आपके सिस्टम में हैकिंग या कहें आपके सिस्टम की जानकारी चुराने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. यह साइबर वॉर का एक प्रमुख हथियार है जिसका दुनिया भर के हैकर इस्तेमाल करते हैं. ट्रोजन भी कई प्रकार के होते हैं, इनमें से कुछ निम्न हैं–

1. रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन ट्रोजन
2. डाटा स्टीलिंग ट्रोजन
3. सेक्योरिटी डिसेबल ट्रोजन
4. कंट्रोल चेंजर ट्रोजन

कुछ प्रसिद्ध ट्रोजन :
Beast (बीस्ट)
Back orifice (बैक ओरीफाइस)
Pro Rat (प्रो–रैट)
Girl Friend (गर्ल फ्रेंड)

बूट सेक्टर वायरस : ये एक ऐसा वायरस है जो कि बूटिंग के समय में कंप्यूटर के द्वारा पढ़ा जाता है कि सिस्टम बूट फ़ाइलों को ही देख़ता है. ये आम तौर पर फ्लॉपी डिस्क के जरिये ही फैलता हैं. ये ऐसा वायरस है जो कि सिस्टम BIOS पर असर डालता है , जिसकी वजह से कंप्यूटर के हार्डवेयर काम करना छोड़ने लगते है.

Macro Virus (मैक्रो वायरस): मैक्रो वायरस सेल्फ एक्जीक्यूट करने के लिए तैयार किए जाते हैं. ये एक मैक्रो प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करने वाले वायरस होते हैं. वे ऐसे एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल के रूप में दस्तावेजों को संक्रमित कर देते हैं और आम तौर पर इसी तरह के अन्य दस्तावेजों में मूल टेक्स को अपनी लैंग्वेज में परिवर्तित कर देते हैं.

Worms (वॉम्स) : इस तरह की प्रोग्रामिंग वॉम क्रिएट कर देती है और खुद की प्रतियों के डिस्ट्रीब्यूशन(वितरण) कर देता है. उदाहरण के लिए एक सीडी से दूसरी सीडी, एक ई–मेल से दूसरे ई–मेल का उपयोग कर अपने आपको फैलाता है. यह एक संक्रमित ई – मेल पर क्लिक करने पर कंप्यूटर में आ जाता है.

Memory Resident Virus (मेमोरी रेजिडेंट वायरस) : मेमोरी रेजिडेंट वायरस कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी जिसे रीड ऑनली मेमोरी (रैम) कहते हैं में रहते हैं. जब एक प्रोग्राम कंप्यूटर पर चलता है तो ये भी उसी के साथ चलते हैं और शुरुआत में ही प्रोग्राम को बंद कर देता है.

Rootkit Virus (रूटकिट वायरस): रूटकिट वायरस किसी कंप्यूटर प्रणाली का नियंत्रण हासिल करने के लिए बनाया जाता है. जो कि एक undetectable (जिसे खोजा न जा सके) वायरस है. रूटकिट वायरस लायनेक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम से आता है. ये वायरस आमतौर पर ट्रोजन द्वारा भी स्थापित होता हैं. ■

smart7973@gmail.com

सबसे मंहगे युवराज

देल्ही डेयरडेविल्स ने 16 करोड़ में खरीदा

आईपीएल के आठवें सीज़न के लिए खिलाड़ियों की बोली में देल्ही डेयरडेविल्स ने 16 करोड़ रुपये में खरीदा. देल्ही डेयरडेविल्स ने श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज़ को 7.50 करोड़ में, अमित मिश्रा को 3.50 करोड़ रुपये में, श्रेयस अय्यर को 2.60 करोड़ रुपये में और ज़हीर खान को चार करोड़ रुपए में अपने नाम किया. इसपर भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज़ और आईपीएल में कोलकाता नाइटराइडर्स के सहायक कोच विजय दहिया कहते हैं कि दरअसल देल्ही की टीम को एक चेहरे की तलाश थी. उन्होंने कहा, पिछले कुछ समय से टीम खेल ज़रूर रही थी लेकिन उनके पास कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं था जिसके इर्द-गिर्द टीम रह सके. ऐसे में भारतीय चेहरा होना बेहद ज़रूरी है. इसलिए उन्होंने इतने अधिक पैसे के साथ युवराज पर अपना दांव खेला है. पिछले सीजन भी युवराज सबसे मंहगे खिलाड़ी थे, उन्हें बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स ने 14 करोड़ रुपये में खरीदा था.■

बिना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले बना करोड़पति

आईपीएल 8 की नीलामी कई मामलों में चौंकाने वाली रही. एक ओर जहां वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में नहीं शामिल किए गए युवराज सिंह सबसे महंगे खिलाड़ी रहे, वहीं कई ऐसे युवा चेहरों को भी मौका मिला जिनका क्रिकेटर करियर बेहद छोटा है. ऐसे ही एक खिलाड़ी हैं के सी करियप्पा. करियप्पा पर शाहरुख खान

की टीम कोलकाता नाइटराइडर्स ने दांव लगाया और उन्हें 2.4 करोड़ में खरीदा. किसी नए खिलाड़ी के लिए ये बड़ी बोली मानी जा रही है. उन्हें जैक कैलिस की खोज कहा जा रहा है. गौरतलब है कि द.अफ्रीका के कैलिस केकेआर की ओर से आईपील के 7 सीजन खेल चुके हैं. बिना फर्स्ट क्लास मैच खेले करियप्पा ना सिर्फ अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं, बल्कि उन्हें आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में खेलने का मौका भी मिल गया है. करियप्पा कर्नाटक प्रीमियर लीग (केपीएल) खेल चुके हैं. इसमें उन्होंने 6 मैचों में 11 विकेट लिए. 12 के औसत के साथ साथ उनका बेस्ट 19 रन देकर 4 विकेट रहा. केपीएल में करियप्पा बीजापुर बुल्स की ओर से खेले थे. वो स्पिनर हैं. हालांकि, वो अंडर 19 टीम में कर्नाटक की ओर से सीमित ओवर के मैच खेल चुके हैं. साथ ही कर्नाटक रणजी टीम में रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर शामिल हो चुके हैं.■

भारत में बास्केटबॉल को हिट बनाएगा एनबीए

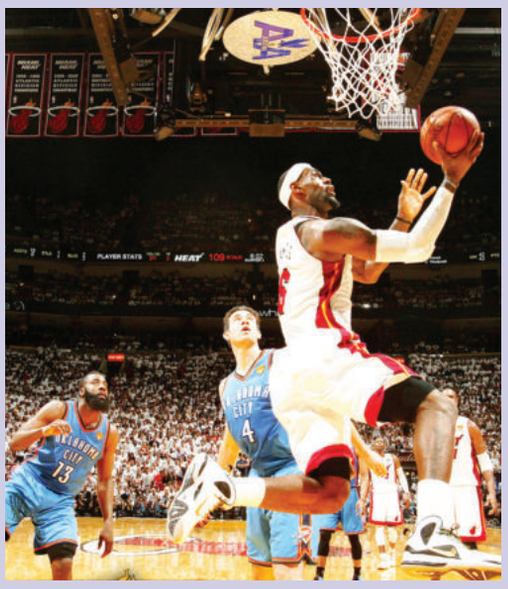

भारत में बास्केटबॉल उभरता हुआ खेल है लेकिन अमेरिका के राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ (एनबीए) ने इसे भारत में क्रिकेट के बाद दूसरा सबसे अधिक दबदबे वाला खेल बनाने की योजना बनाई है. दुनिया भर में एनबीए काफी लोकप्रिय है और भारत भी इससे अछूता नहीं है. भारत में युवाओं के बीच यह काफी पसंद किया जाता है और एनबीए इन्हीं युवाओं को अपना लक्ष्य बना रहा है. एनबीए इंडिया के प्रबंध निदेशक यानिक कोलासो ने एनबीए ऑल स्टार वीकेंड के बाद कहा, भारत में हम कभी क्रिकेट को चुनौती नहीं दे सकते और हमने कभी ऐसी योजना नहीं बनाई. भारत क्रिकेट का दीवाना देश है और हमें यह पता है. लेकिन, हमारा लक्ष्य भारत में बास्केटबॉल को दूसरा सबसे दबदबे वाला खेल बनाना है. उन्होंने कहा, भारत के युवा नियमित खेल के अलावा अन्य खेलों में भी मौके तलाश रहे हैं और हमारा लक्ष्य यही है.■

रियो ओलंपिक के बाद संन्यास : महेश्वरी

कॉमनवेल्थ गेम्स के पूर्व कांस्य पदक विजेता ट्रिपल जंप एथलीट रंजीत महेश्वरी ने कहा है कि वह 2016 रियो ओलंपिक के बाद खेल को अलविदा कह देंगे. रंजीत ने 35वें नैशनल गेम्स की ट्रिपल जंप स्पर्धा में 16.66 मीटर के नये रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है. जीत के बाद उन्होंने कहा, मैं रियो ओलंपिक के बाद संन्यास ले लूंगा,

क्योंकि मैं परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहता हूं. केरल के इस स्टार एथलीट का करियर उतार चढ़ाव भरा रहा है. उन्होंने 2007 में एशियाई चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन 2008 बीजिंग ओलंपिक के बाद वह डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए. इसके बाद उन्हें तीन महीने का निलंबन झेला गया. इसके असर का सामना उन्हें साल 2013 में तब करना पड़ा जब उन्हें दिया गया अर्जुन पुरस्कार वापस ले लिया गया.■

विश्वकप

भतीजे पर भारी चाचा

ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड की संयुक्त मेजबानी में हो रहे विश्व कप में आयरलैंड के कोच फ़िल सिमंस बेहद खुश हैं. वजह यह है कि उनकी टीम को हल्के में ले रहे क्रिकेट विश्वज्ञों को उन्होंने पहले ही मुक़ाबले में झटका दे दिया है, जब उसने दो बार की विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज़ को मात दी. दिलचस्प यह है कि इस मैच में वेस्टइंडीज़ की तरफ़ से फ़िल सिमंस के भतीजे लैंडल सिमंस भी खेल रहे थे और मैच में एक बार उन्होंने अपने चाचा को परेशानी में डाल दिया था. आयरलैंड ने क्रिस गेल और डेवेन ब्रावो समेत वेस्टइंडीज़ के पांच चोटी के बल्लेबाज़ों को 87 के योग पर पैवेलियन लौटा दिया था. सिमंस मन ही मन बहुत खुश थे जिस टीम को उन्होंने कोचिंग दी है, वह शानदार प्रदर्शन कर रही है. तभी उनके भतीजे लैंडल क्रीज़ पर उतरे और आयरलैंड के गेंदबाज़ों पर कहर बरपा दिया. उन्होंने 102 रनों की धमाकेदार पारी खेली.■

एक पारी में चार बैट्समैन बने गोल्डन डक

वर्ल्ड कप 2015 का छठा मैच न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड के बीच खेला गया. इस मुक़ाबले में स्कॉटलैंड के चार खिलाड़ी गोल्डन डक हुए. यानी वे पहली ही गेंद पर अपना विकेट खो बैठे. वर्ल्ड कप इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी टीम के चार खिलाड़ी गोल्डन डक हुए. इन खिलाड़ियों के नाम हैं – कैलम मैक्लयोड, हामिश गार्डिनर, प्रोस्टन मोमसेन और इयान वार्डलॉ. क्रिकेट में इससे पहले ऐसा वाक्या सिर्फ दो बार ही हुआ है. पहली बार 19 मार्च, 1999 को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच हुए मुकाबले में श्रीलंका के चार खिलाड़ी गोल्डन डक हुए. दूसरी बार, 20 जून, 2003 को इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान के चार बैट्समैन गोल्डन डक हुए. वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने तीन विकेट से स्कॉटलैंड को हरा दिया. मैच की शुरुआत से ही न्यूजीलैंड की टीम स्कॉटलैंड पर हावी हो गई. स्कॉटलैंड के चार खिलाड़ी महज 12 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए और पूरी टीम 142 के स्कोर पर आउट हो गई.■

रोनाल्डो की नई प्रेमिका

पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इरिना शायक के साथ ब्रेकअप हो गया है. मीडिया सूत्रों की मानें तो वह पुर्तगाल की 26 साल की खूबसूरत टीवी प्रेजेंटर लुसिया विलेलोन उनकी नई प्रेमिका हैं. उल्लेखनीय है कि रोनाल्डो और सुपरमॉडल इरिना 2010 से रिलेशनशिप में थे और उम्मीद लगाई जा रही थी कि यह जोड़ी जल्द ही विवाह बंधन में बंध जाएगी. इस बात को तब और तूल मिल गया, जब स्पोर्ट्स प्रेजेंटर ने रोनाल्डो के साथ वैलन डी ऑर ट्रॉफी के साथ वाली तस्वीर सोशल साइट पर पोस्ट कर दी. फोटो पर 25 हजार लाइक्स और 3 हजार से अधिक कमेंट्स आए हैं. अधिकतर लोगों ने इस नए लव कपल को बधाई दी है. जहां रोनाल्डो अपनी नई प्रेमिका को लेकर चर्चा में हैं, वहीं पूर्व गर्लफ्रेंड इरिना शायक ने एक स्पोर्ट्स पत्रिका के लिए हॉट फोटोशूट करवाया है. इरिना शायक ने 2014 में हॉलीवुड के लिए डेब्यू किया था. रूस की सुपरमॉडल इरिना के को-स्टार द रॉक इवेन जॉनसन थे. यह फिल्म सुपरहिट रही थी.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

रिजेक्ट हुई थीं आशा पारेख

साल 1959 से 1973 तक बॉलीवुड की टॉप हिरोइनों में शुमार रहीं आशा पारेख कभी हिरोइन के रूप में रिजेक्ट भी कर दी गई थीं, इस बात पर शायद कोई यकीन नहीं करेगा. पर, उनके बॉलीवुड करियर की शुरुआत में ऐसा ही हुआ था. 2 अक्टूबर, 1942 को मुंबई में जन्मीं आशा के पिता मिडिल क्लास गुजराती जैन परिवार के थे और उनकी मां एक मुस्लिम परिवार से थीं. उनकी मां ने ही उन्हें बचपन में ही क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग दिलानी शुरू कर दी थी. एक बार एक स्टेज शो के दौरान डायरेक्टर बिमल राय ने उन्हें देखा और 1954 में बेबी आशा के नाम से अपनी फिल्म बाप बेटी में बतौर बाल कलाकार ले लिया. पर, वह फिल्म अधिक नहीं चली और कुछ अन्य फिल्मों में भी बाल कलाकार के रूप में काम करने के बाद वह फिर से अपनी पढ़ाई में लग गईं. इसके बाद 1959 में उन्होंने फिर से बॉलीवुड में अपने लिए काम की तलाश शुरू कर दी. विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई के लिए उनका नाम फाइनल भी कर लिया गया, पर फिल्म निर्माता विजय भट्ट जब आशा जी से मिले तो उन्हें लगा कि इनमें स्टार मटेरियल नहीं है. भट्ट ने उनकी जगह अमीता को फिल्म में हिरोइन चुन लिया. उसी दौर में वह प्रोड्यूसर सुबोध मुखर्जी के संपर्क में भी थीं. मुखर्जी और फिल्म लेखक डायरेक्टर नासिर हुसैन ने आशा जी को अपनी फिल्म दिल दे के देखो में शम्मी कपूर के ऑपोजिट हिरोइन चुन लिया. शम्मी आशा पारेख से 10 साल बड़े थे. यह फिल्म 1959 में सुपर हिट रही और बॉलीवुड को आशा पारेख के रूप में एक चमकता सितारा मिल गया, जो अगले कई सालों तक दर्शकों के दिलों पर राज करता रहा. आशा पारेख ने कभी शादी नहीं की. उनका कहना था कि उनका रुख अनअप्रोचेबल था, शायद इसी वजह से किसी युवक ने उन्हें प्रपोज नहीं किया. वैसे 60 के दशक में यह अफवाह जरूर उड़ी थी कि उनके और नासिर हुसैन के बीच कुछ रोमांटिक लिंक है. पर, हुसैन के शादीशुदा थे,यदि दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता था भी तो वह कभी आगे नहीं बढ़ सका. हां, एक बार आशा पारेख ने कहा जरूर था कि उनकी एक युवक के साथ लंबे समय तक दोस्ती रही थी. उन्होंने इसके अलावा और इस रिश्ते के बारें में कु छ और नहीं बताया, पर यह जरूर कहा कि जब तक वह रिश्ता चला था बहुत अच्छा था.■

अब दीपिका भी गाएंगी गाना

इस फिल्म में होंगे उनके एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर. दीपिका से जुड़े करीबी सूत्र के अनुसार वह इन दिनों गाने की प्रैक्टिस भी कर रही हैं. यानी इस फिल्म में दीपिका के फैन्स को डबल खुशी मिलने की पूरी संभावना है.

लग रहा है बॉलीवुड के गायकों को बहुत जल्द अपने लिए दूसरे काम की तलाश शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ऐक्टर्स सिर्फ ऐक्टिंग तक ही सीमित नहीं रह गए हैं. प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर के बाद एक्टर-सिंगर की लिस्ट में एक नया नाम जुड़ने वाला है, वह नाम है दीपिका पादुकोण का. खबर है कि दीपिका को उनकी आगामी फिल्म तमाशा के लिए गाना गाने का ऑफर दिया गया है. इस फिल्म को इम्तियाज अली बना रहे हैं. यह जानकारी भी मिली है कि पहले तो दीपिका इस ऑफर पर हैरान रह गईं, पर फिर वह खुशी से इसके लिए राजी हो गईं. इस फिल्म में उनके अपोजिट उनके एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर होंगे. दीपिका से जुड़े करीबी सूत्रों के अनुसार वह इन दिनों गाने की प्रैक्टिस भी कर रही हैं. यानी इस फिल्म में दीपिका के फैन्स को डबल धमाका देखने को मिलेगा. फिल्म को साल के अंत तक रिलीज किए जाने का कार्यक्रम भी बनाया जा रहा है.■

न्यूज़ मसाला

बदलापुर से सेंसर का बदला

अभिनेता वरुण धवन की आने वाली फ़िल्म बदलापुर पर संसरबोर्ड की कैंची चल गई है. हालांकि, यह कैंची सिर्फ़ ऑडियो पर यानी डायलॉग पर चली है. फ़िल्म का वह सीन जस का तस है. केवल एक शब्द को बदलकर कुछ और कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि बदलापुर के हिंसक सीन को ज्यों का त्यों ही रखा गया है. सेंसर बोर्ड को फ़िल्म में प्रयोग किए गए एक शब्द पर आपत्ति थी. फ़िल्म में इस शब्द का प्रयोग दो से तीन दफ़े हुआ है. सूत्र के मुताबिक़ फ़***' को बदलकर हेल' कर दिया गया है और फ़****ग' को म्यूट कर दिया गया है. फ़िल्म के निर्देशक सेंसर की कैंची से संतुष्ट हैं. उनका मानना है कि किरदार की मानसिक स्थिति के अनुसार ही डायलॉग होते हैं. इस फ़िल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक किलर हैं, हुमा कुरैशी एक वैश्या के किरदार में हैं.■

मल्लिका की हॉरर

के.सी. बोकाडिया के निर्माण व निर्देशन में बनी डर्टी पॉलिटिक्स को लेकर मल्लिका शेरावत काफी प्रचार कर चुकी थीं. फिल्म की रिलीज डेट भी आगे बढ़ रही है. अब यह फिल्म मार्च में रिलीज होगी. उधर देरी होती देख मल्लिका ने एक और फिल्म साइन की है. ये एक हॉरर-थ्रिलर है. हालांकि इसी तरह की उनकी इंटरनेशनल फिल्म हिस्स बहुत बुरी बनी थी. खैर, इसके अलावा मल्लिका के.सी. बोकाड़िया की ही फिल्म फूल बने अंगारे के मॉडर्न रीमेक में भी काम कर रही हैं. मल्लिका अमेरिकी नेटवर्क सीबीएस के शो हवाई फाइव-0 के अन्य एपिसोड भी शूट करेंगी. इसी चैनल के लिए अब प्रियंका चोपड़ा काम करने वाली हैं.■

व्यस्त अनुष्का को विराट की चिंता

अनुष्का शर्मा बेशक इन दिनों काफी बिजी हैं, लेकिन वह एक साथ दो-दो काम भी आसानी से कर लेती हैं. अपनी आने वाली फिल्म एनएच10 को प्रमोट करने के साथ ही वह वर्ल्ड कप मैच में विराट के परफॉर्मेंस पर भी नज़र रख रही हैं. दरअसल, अनुष्का अपनी अपकमिंग मूवी एनएच10' के प्रमोशन में बिजी थीं, उनके लिए यह बड़ा इवेंट था, लेकिन ठीक उसी दिन इंडिया-पाक का मैच भी था तो अनुष्का काम के साथ-साथ मैच भी देख रही थीं कि विराट कैसा खेल रहे हैं. जाहिर है उनके शतकीय परफॉर्मेंस से वह बेहद खुश थीं. गौरतलब है कि अनुष्का पहले ही दुआ कर चुकी हैं कि इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीत जाए. वहीं, एनएच10 अनुष्का के लिए बहुत ही खास फिल्म है. वह इसके जरिए बॉलिवुड में बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू करने जा रही हैं. इसका ट्रेलर खूब पसंद किया जा रहा है. इस फिल्म को बेहतर बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है. यही वजह है कि अनुष्का अब इसकी प्रमोशनल इवेंट्स को भी अच्छी तरह प्लान कर रही हैं. हाल ही में अनुष्का की आमिर खान के साथ पीके में नज़र आई थी. इसमें अनुष्का की परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया गया था.■

फर्जी न्यूड सेल्फी को करें इग्नोर: राधिका

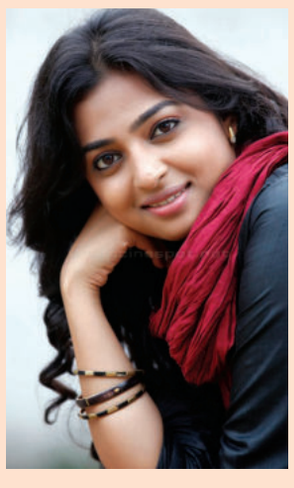

शोर इन द सिटी फिल्म में अभिनय कर चुकीं अभिनेत्री राधिका आप्टे सोशल नेटवर्किंग साइट्स और वॉट्सऐप पर अपनी फर्जी न्यूड तस्वीरें वायरल होने से हैरान हैं. वह कहती हैं कि ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज करना ही बेहतर है. ये विवादित तस्वीरें न्यूड सेल्फी हैं. राधिका ने कहा, पारखी नज़र वाला कोई भी व्यक्ति समझ जाएगा कि वह मैं नहीं हूं. राधिका इस बात से सहमत हैं कि इस तरह की घटनाएं सिलेब्रिटी होने के खामियाजे के तौर पर घटती हैं. उन्होंने बताया कि हमें यह सीखना होगा कि इससे प्रभावित न हों. महिलाओं को इस तरह देखने की दूषित मानसिकता और सनसनीखेज पत्रकारिता इस तरह की खबरों को बढ़ावा देती है. एक कलाकार स्वयं को फोटोशॉप और मॉर्फिंग (तस्वीर का रूप-रंग बदलने) से कैसे बचा सकता है? राधिका ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इसे नजरअंदाज करने के अलावा और कुछ किया जा सकता है या किया जाना चाहिए. कुछ और करना अपने समय की बर्बादी है.■

आलिया से इश्क लड़ाएंगे सुशांत

जल्द ही ये दोनों स्टार्स अपने कमिटमेंट्स को पूरा कर दिनेश विजन की फिल्म राब्ता की शूटिंग करेंगे.

ऐक्ट्रेस आलिया भट्ट और सुशांत सिंह राजपूत जल्द ही सिल्वर स्क्रीन पर रोमांस करते नजर आएंगे. सुशांत इन दिनों महेंद्र सिंह धोनी की के जीवन पर बन रही बॉयोपिक फिल्म एमएस धोनी की शूटिंग कर रहे हैं. वहीं आलिया, शाहिद कपूर के साथ फिल्म शानदार के प्रमोशन में बिजी हैं, जल्द ही ये दोनों स्टार्स अपने कमिटमेंट्स को पूरा कर दिनेश विजन की फिल्म राब्ता की शूटिंग करेंगे. डायरेक्टर दिनेश विजन पिछले काफी दिनों से सैफ अली खान और परिणीति चोपड़ा को साथ लेकर फिल्म बनाना चाहते थे. लेकिन बात नहीं बनीं. अब वह मैडॉक फिल्म्स के साथ मिलकर फिल्म का प्रोडक्शन करेंगे. सैफ-परिणीति की जगह उन्होंने सुशांत-आलिया को कास्ट करने का मन बना लिया है. फिल्म राब्ता की स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है और जुलाई में इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी. फिल्म से जुड़े सूत्र की मानें तो यह फिल्म होमी अदजानिया और दिनेश विजन मिलकर डायरेक्ट करेंगे. फिल्म 2016 में रिलीज होगी.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

02 मार्च -08 मार्च 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

बाजी पलट दी नीतीश ने

भाजपा के लिए परेशानी और चिंता के सबब भी कम नहीं हैं. वह यह नहीं समझ पा रही है कि मांझी का क्या किया जाए? इसका कारण है कि मांझी-काल, राजनीति और प्रशासन के संदर्भ में, बेहतर बिहार की किसी भी स्तर पर कोई उम्मीद नहीं जगाता. यह सूबे में कुशासन और कुव्यवस्था का प्रतीक बन गया . राज्य में 2005 के नवम्बर के बाद कानून का राज कायम हुआ था. वह दौर मांझी के मुख्मंत्रित्व काल में इतिहास की बात हो जैसा हो गया और पिछले साल हालात निरन्तर बिगड़ते चले गए. इस मोर्चे पर पिछला एक साल तो निराशा का काल रहा है.

चौथी दुनिया ब्यूरो

बिहार की सत्ता राजनीति का मौजूदा संकट भाजपा की राजनीति को विस्तार का अवसर तो दे रहा है, पर यह परेशानी के नए सबब भी पैदा कर रहा है. एक महादलित नेता को समर्थन देकर भाजपा बिहार के उन सामाजिक समूहों में पैठ बनाने की सार्थक कोशिश कर रही है जिसे मंडल की राजनीति के दौर में भी वोट से अधिक कुछ नहीं माना गया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने महादलित वोट की घेराबंदी मजबूत बनाने के ख्याल से जीतनराम मांझी को सीएम बनाया था लेकिन नीतीश-मांझी विवाद के सहारे इसका लाभ भाजपा लेने की जुगत में लग गई. हिन्दी पट्टी के अन्य राज्यों की तरह यहां भी कुछ चुनाव पहले तक भाजपा का सामाजिक आधार बड़ा ही सीमित था. एनडीए के दौर में इसका विस्तार सूबे की कुछ मध्यवर्ती जातियों में हुआ. पर, अतिपिछड़ी जातियों और दलित-महादलितों में यह अब तक अपनी उल्लेखनीय पैठ नहीं बना सकी थी. इन सामाजिक समूहों में पैठ बनाने के लिए पिछले कई वर्षों से भाजपा नेतृत्व परेशान रहा है. मांझी बनाम नीतीश विवाद ने इसे इन सामाजिक समूहों में अपना आधार तैयार करने का बेहतर अवसर दिया.

जीतनराम मांझी गत वर्ष मई के अंतिम दिनों में मुख्यमंत्री बने थे और दो-ढाई महीने बाद ही पार्टी सुप्रीमो और अपने मेंटर नीतीश कुमार के साथ उनका मतभेद आरंभ हो गया. उन दिनों कुछ समय तक तो भाजपा बहुत कुछ समझ नहीं सकी और रिमोट नियंत्रित मांझी सरकार को निशाने पर लेती रही, पर कुछ हफ्तों बाद उसने मांझी को बख़्श दिया. निशाने पर नीतीश कुमार को ले लिया गया. अब भाजपा के लिए नीतीश से राजनीतिक बदला लेने की मांझी ढाल बन चुके थे. यह अघोषित रिश्ता विधानसभा में साथ देने तक पहुंच गया. हालांकि इसका कोई बहुत मतलब नहीं निकला और नीतीश कुमार एक बार फिर राज्य का मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो गए. जो बाजी उनके हाथों से निकलती दिख रही थी, वो उन्होंने जीत ली.

आज के बिहार का एक सच यह भी है कि यहां विभिन्न सामाजिक समूहों की मतदान की निष्ठाएं भी लगभग तय हैं. अगड़े समाज का बहुमत वोटर भाजपा के साथ है तो पिछड़ों के वोट पर, उनके कुछ सामाजिक समूहों को छोड़कर, मंडल राजनीति के नायकों का गहरा प्रभाव है. पिछले विधान सभा चुनावों में दलित-महादलित का बहुमत वोट निश्चित तौर पर नीतीश कुमार और उनके एनडीए को मिला था, पर गत संसदीय चुनाव में वैसा हुआ नहीं. दलित-महादलित वोट पर नीतीश कुमार का एकाधिकार रहा नहीं-वोट बिखर गया. संसदीय चुनावों के बाद दलित-महादलित वोट किसी राजनीतिक गोल से प्रायः बाहर ही रहा. जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस वोट बैंक का झुकाव उनकी तरफ देखा गया था. अब अगले विधानसभा चुनाव में यह देखने

जीतनराम मांझी गत वर्ष मई के अंतिम दिनों में मुख्यमंत्री बने थे और दो-ढाई महीने बाद ही पार्टी सुप्रीमो और अपने मेंटर नीतीश कुमार के साथ उनका मतभेद आरंभ हो गया. उन दिनों कुछ समय तक तो भाजपा बहुत कुछ समझ नहीं सकी और रिमोट नियंत्रित मांझी सरकार को निशाने पर लेती रही, पर कुछ हफ्तों बाद उसने मांझी को बख़्श दिया. निशाने पर नीतीश कुमार को ले लिया गया. अब भाजपा के लिए नीतीश से राजनीतिक बदला लेने की मांझी ढाल बन चुके थे. यह अघोषित रिश्ता विधानसभा में साथ देने तक पहुंच गया. हालांकि इसका कोई बहुत मतलब नहीं निकला और नीतीश कुमार एक बार फिर राज्य का मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो गए. जो बाजी उनके हाथों से निकलती दिख रही थी, वो उन्होंने जीत ली.

वाली बाती होगी कि यह वोटर समूह किसको वोट देते हैं. विधान सभा चुनाव आते-आते राजनीतिक चक्र कैसे घूमेगा, कहना थोड़ा कठिन जरूर है. पर राजनीतिक संकट के दौर में भाजपा जीतनराम मांझी के साथ चट्टान की तरह अटूट खड़ी थी, तो मांझी भी उसके साथ ही होंगे-यह मानने में कोई परेशानी नहीं है.

भाजपा चाहती है, नीतीश कुमार आज से बीस साल पहले के दौर में वापस लौट जाएं. भाजपा की यह चाहत पूरी होगी, ऐसा कहना कठिन है. लोगों ने यह भी देखा है कि एक साल पहले नीतीश- गत संसदीय चुनाव- तक किस कटुता से लालू-राबड़ी राज पर व्यंग्य के तीर चला रहे थे. पर, चुनाव के बाद बिहार के राजनीतिक समीकरण में बदलाव आया और भाजपा-विरोधी राजनीति में नीतीश कुमार और लालू यादव आपस में मिले और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने में एक बार फिर कामयाब हुए. हालां

बतौर मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने क्या अच्छा-बुरा किया, बिहार को अपने किन निर्णयों से बिहार को विनाश की गर्त में पहुंचा दिया, जदयू के जनाधार पर आघात पहुंचाया, इसका ब्योरा सभी के पास है. इस राजनीतिक लड़ाई के दौरान बिहार के लोगों को बताया गया कि सूबे में नीचे से लेकर ऊपर तक सरकारी कार्यालयों में बिचौलियों का राज है और वही सारा कुछ चलाते हैं. यह भी सामने आया कि सरकारी निर्माण कार्यों में कमीशन-खोरी पर रोक की कोशिश ने मांझी सरकार को संकट में डाल दिया, कमीशन पाने वाले तत्व सरकार के खिलाफ गोलबंद हो गए. जीतनराम मांझी 20 मई 14 को मुख्यमंत्री बने थे और दो-ढाई महीनों तक राज्य सरकार के सारे कामकाज वह नीतीश कुमार से परामर्श लेकर ही करते रहे. नीतीश को उनसे यह उम्मीद भी थी कि वे शासन अच्छी तरह चलाएंगे लेकिन मांझी ने ज्यादा दिन नहीं लिए जब वे उल्टे सीधे बयान देने लगे और नीतीश कुमार की छवि को धूमिल करने का प्रयास भी करने लगे. इसकी शुरुआत पथनिर्माण विभाग के दो सौ इंजीनियरों के तबादले को लेकर हुई थी. यह मतभेद बढ़ता चला गया. औद्योगिक तौर पर पिछड़े बिहार में राजनेताओं व नौकरशाहों के लिए तबादला कितना बड़ा उद्योग है, यह बताने की जरूरत नहीं है.

भाजपा के लिए परेशानी और चिंता के सबब भी कम नहीं हैं. वह यह नहीं समझ पा रही है कि मांझी का क्या किया जाए? इसका कारण है कि मांझी-काल, राजनीति और प्रशासन के संदर्भ में, बेहतर बिहार की किसी भी स्तर पर कोई उम्मीद नहीं जगाता. यह सूबे में कुशासन और कुव्यवस्था का प्रतीक बन गया . राज्य में 2005 के नवम्बर के बाद कानून का राज कायम हुआ था. वह दौर मांझी के मुख्मंत्रित्व काल में इतिहास की बात हो जैसा हो गया और पिछले साल हालात निरन्तर बिगड़ते चले गए. इस मोर्चे पर पिछला एक साल तो निराशा का काल रहा है.

ऐसा लग रहा था कि राज्य में सत्ता का इंकबाल खत्म हो चुका है. इतना ही नहीं, सत्ता से जुड़े राजनेताओं के परिजनों द्वारा सरकारी पद बेचे जाने की भी चर्चा सार्वजनिक होने लगी. राज्य में विकास कार्य ठप्प है, नाम के लिए भी निवेशकों का आना बंद है. कृषि विकास के सारे कार्यक्रम तो स्थगित हैं ही, हरित क्रांति की उम्मीदों को सरजमीं पर उतारने के मद्देनजर गठित कृषि कैबीनेट को लोग भूल से गए. नई सड़कों के निर्माण की बात तो दूर, पुरानी की मरम्मत भी लगभग बंद हो गई. राज्य सरकार की आर्थिक गतिविधि स्थगित है. कहने को तो धन का आवंटन किया जा रहा था, लेकिन सारा कुछ कागज (संचिका) तक ही सीमित रहा. वित्तीय वर्ष समाप्त होने को आया, पर विकास योजनाओं की मंजूरी या राजस्व वसूली अपने निम्नतम स्तर पर आ गई. सूबे में ऐसी जड़ता को जीतनराम मांझी अपने अट-पट, राजनीतिक या गैर राजनीतिक, बोल से तोड़ने की कोशिश करते रहे. उनके ऐसे बोल राज्य के बयानबाजों को खुराक देने में खूब सफल रहे. अपने ऐसे अट-पट बोलों में वे उन सामाजिक तबकों को निशाना बनाते हैं जो मौजूदा दौर में भाजपा के वोट-बैंक माने जाते हैं. इन तबकों की लालू प्रसाद और नीतीश कुमार से नाराजगी तो अपनी जगह है ही, मांझी को लेकर भी उनमें खासा क्षोभ है, उन्हें स्वीकार करने को वे तैयार नहीं. ऐसे में भाजपा के लिए मांझी को अधिक दूर तक ढोना कई राजनीतिक परेशानी का सबब बन सकता है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा मांझी के साथ कितनी दूरी तय करती है और अपने अपेक्षाकृत पुराने मतदाता-समूहों को कैसे बांधे रखती है या फिर, दोनों नाव की सवारी करती है तो कैसे?■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

एक नज़र

मुखिया संघ की बैठक

मोतिहारी में खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ आम जनता तक पहुंचाने व वंचित बीपीएल परिवारों को राशन कार्ड मुहैया कराने आदि मुद्दों के समर्थन में जिला मुखिया संघ एक बड़ा आन्दोलन करेगा और इसके लिए एक बेहतर कार्य योजना तैयार कर आगामी सोलह मार्च को समाहरणालय के समक्ष धरना करेगा. जिला मुखिया संघ के बलुआ टाल स्थित कार्यालय में हुई बैठक में मुखियों ने अनेक बिन्दुओं पर गहन समीक्षा की और जनता की समस्याओं को ले सड़क पर उतरने का संकल्प लिया. बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष डॉ. एहतेशाम अहमद ने कहा कि कनीय अभियंता एवं पंचायत सचिवों के अभाव में अभिलेख का निर्धारण कार्य काफी धीमी गति से हो रहा है जिस कारण पंचायतों के विकास में अनेक चुनौतियां सामने आ रही है. मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष उमाशंकर यादव, नथुनी साह, रामबाबू यादव, संजीव सिंह, राजेश तिवारी, निर्मला देवी, किरण गुप्ता, रविभूषण प्रसाद, सुमन देवी, विनोद-वरी सहनी, मो. फारूक आजम, अशोक यादव, पूर्व जिला पार्षद रीतम आरा, उमा देवी एवं जिला प्रवक्ता सजावल राम समेत बड़ी संख्या में पंचायतों के मुखिया उपस्थित थे.

अभिकर्ताओं का प्रदर्शन

पूर्वी चम्पारण जिले के सिकराहना अनुमण्डल के ढाका एल आई सी कार्यालय के समक्ष में अभिकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगो के समर्थन में रोष पूर्ण धरना प्रदर्शन किया और कार्यालय में तालाबंदी की. कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुमंडल अध्यक्ष ब्रजनारायण सिंह ने की. इनकी मुख्य मांगें अभिकर्ताओं को बीमा पर सर्विस टैक्स समाप्त करने, बोनस में बढ़ोतरी, ग्रेजुएटी में बढ़ोतरी, बीमा अधिनियम 1938 की धारा 44 बहाल करने आदि थी. शामिल है. मौके पर अभिकर्ता ओमप्रकाश पाण्डेय, ललन तिवारी, साकेत कुमार झा, राज कुमार, शिवशंकर प्रसाद, राजमंगल साह, दिवाकर कुमार, हरेन्द्र ठाकुर, अवधेश कुमार, संजय कुमार, उमेशनारायण सिंह, महेश्वर सिंह, सुनील प्रकाश, अशोक कुमार, सुवंश सिंह, दीनानाथ प्रसाद, प्रमोद गिरी सहित कई एल आई सी अभिकर्ता शामिल थे.

जयन्ती मनायी

महाशिवरात्रि के अवसर पर पतौरा ब्रह्माकुमारीज सेवा केन्द्र पर त्रिमूर्ति 79 वीं शिव अवतरण जयन्ती हर्षोल्लास के साथ मनायी गयी. इस अवसर पर योग भट्ठी का आयोजन किया गया और महाशिव रात्रि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी. योग भट्ठी एवं मुरली वर्ग के बाद परम पिता परमात्मा शिव बाबा का ध्वजारोहन जिला मुख्यालय केन्द्र के प्रभारी बीके सीता, पतौरा केन्द्र के प्रभारी बीके अशोक, अधिवक्ता बंन्दन किशोर, डॉ. अंजू वर्मा एवं अन्य ब्रह्मा कुमारी, बहनो द्वारा किया गया. मौके पर शिव अवतरण के आध्यात्मिक रहस्यम पर प्रकाश डालते हुए बीके सीता बहन ने बताया कि धर्म गलानी के समय परमात्मा का अवतरण भारत की भूमि पर 79 वर्ष पूर्व हो चुका है. मौके पर बीके अशोक, हरिसिद्धि केन्द्र प्रभारी बीके विभा, सिकटिया के प्रभारी बीके मीरा, मोतिहारी की उप प्रभारी बीके भारती, पटना से आयीं बीके हेमा, बीके हरिशंकर, बीके शम्भु, बीके डॉ0 अंजू वर्मा आदि ने शिव के अवतरण पर चर्चा की. इस अवसर पर बीके जोखन, बीके संजय, राजदेव भाई, शकुन्तला माता, विरेन्द्र भाई, अधिवक्ता शिव पूजन, अलावा संकर, हिमांशु, निलम, मनोहर, गायत्री, सुमन, रौशनी आदि उपस्थित थे.

ट्रेनों की मांग

पूर्वी चम्पारण जिले के घोड़ासहन मेरेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों की ठहराव सुनिश्चित कराने एवं सवारी गाड़ियों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेण्ट्स फेडेरेशन ने एक दिवसीय धरना दिया. धरना की अध्यक्षता रामबाबू प्रसाद यादव ने की जबकि संचालन फेडेरेशन के राज्य कोषाध्यक्ष हेन्द्र कुमार पंडित ने किया. धरना को छात्र नेता सूरज कुमार, दीपक कुमार, राहुल कुमार, सीपीआई के नेता बिन्देश्वरी प्रसाद, जतन शर्मा, पवन सिंह, बैद्यनाथ पाण्डेय, गणनाथ प्रसाद, अताउर अहमद आदि ने संबोधित किया. रेल प्रशासन की सूचना पर स्थानीय मजिस्ट्रेट के तौर पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी कृष्णमुरारी सिन्हा, रक्सौल जीआरपी के थानाध्यक्ष विनोद राम, आरपीएफ के एएसआई एन.के.सिन्हा, एसआईडी के एसआई सुरेश प्रसाद साह, स्थानीय थाना के एसआई बसंत सिंह दल-बल के साथ उपस्थित थे. धरना में मुख्य रूप से छात्र बसंत कुमार, पन्नालाल पासवान, सत्यम निराला, अमन कुमार, सोनालाल कुमार, ऋतुराज, नीतेश कुमार, पवन राम, संजीव कुमार सहित दर्जनों छात्र एवं प्रबुद्ध नागरिक शामिल थे. **– इन्तेजारूल हक**

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE
1 YEAR GUARANTY
Contact : 9386595926, 9334115955

सीतामढ़ी

कार्यकर्ताओं की मुस्कान से राजद जीतेगी चुनावी जंग

पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा पर तमाम, भाजपा के वादा खिलाफी एवं जन समस्याओं के सवाल पर आंदोलन के संकल्प के साथ सीतामढ़ी जिला राजद ने विधानसभा चुनाव को लेकर हुंकार भर दी है. शहर के गांधी मैदान में विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश राजद अध्यक्ष डॉ. रामचंद्र पूर्वे एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह ने केंद्र की भाजपा सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी को विधानसभा में सबक सिखाने की नसीहत पार्टी कार्यकर्ताओं को दी. परंतु पार्टी के समर्पित कुछ कार्यकर्ताओं ने आयोजित सम्मेलन को माई कार्यक्रम की संज्ञा देते हुए एक बार फिर कुशवाहा को ठगने एवं भाजपा को जिताने की साजिश करार दिया है. जबकि प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राजद कार्यकर्ताओं के रुझान, ऊफान व मुस्कान के बूते विधानसभा का चुनावी जंग राजद जीतेगी .

वाल्मीकि कुमार

बिहार विधानसभा चुनाव की बारी आने के साथ ही सीतामढ़ी जिले में राजनीतिक सम्मेलनों का दौर शुरू हो गया है. दिल्ली में संपन्न विधानसभा चुनाव के परिणाम से जहां भाजपा खेमे में नयी चुनावी रणनीति पर विचार की योजना बनायी जा रही है. वहीं राजद चुनावी नतीजों को पार्टी कार्यकर्ता व मतदाताओं के बीच परोस कर बिहार में भी दिल्ली जैसा ही परिणाम भाजपा के पक्ष में देने को लेकर ताल ठोंक रही है. परंतु यह साफ नहीं हो रहा है कि चुनाव जाति-पार्टी की पटरी पर लड़ा जायेगा अथवा विकास मुख्य मुद्दा बनेगा. दूसरा पहलू यह है कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बूते ही चुनावी किला फतह करने की तैयारी तो नहीं की जा रही है? जहां तक सीतामढ़ी जिले में राजद की चुनावी तैयारी का सवाल है तो 2014 के लोकसभा चुनाव का बदला विधानसभा चुनाव में लेने की तैयारी तो नहीं चल रही है? टिकट की दा-वेदारी में जातिगत हिसाब किताब क्या हो सकता है? क्या पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को चुनावी अखाड़े में आने का मौका मिलेगा ? कुछ ऐसे ही सवालों को लेकर राजद की चुनावी मुहिम पर चर्चा आवश्यक है.

2014 के लोकसभा चुनाव के बाद पहला मौका था जब सीतामढ़ी जिला राजद के तत्वावधान में सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया गया. 12 फरवरी को शहर के गांधी मैदान में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह व प्रदेश राजद अध्यक्ष डॉ. रामचंद्र पूर्वे, पूर्व सांसद सीताराम यादव व मो. अनवारूल हक, पूर्व विधान पार्शद दिलीप कुमार यादव व जिला परिषद अध्यक्ष इंद्रानी देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन किया. इस दौरान मैदान में बना पंडाल कार्यकर्ताओं से भरा रहा. जिंदाबाद के नारे से ऐसा लगता रहा कि राजद कार्यकर्ताओं की मायूसी दिल्ली चुनाव के परिणाम ने गुम कर एक नई ऊर्जा का प्रवाह कर दिया है. इस बीच कुछ राजद कार्यकर्ताओं ने अपनी भावना से पार्टी नेताओं को अवगत कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी. बीते साल में पार्टी नेताओं द्वारा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा से लेकर जातिगत आधार पर सामाजिक विखंडन का प्रयास तक सम्मेलन में भाषण का केंद्र बना रहा. कुछ ने तो साफ कर दिया कि चुनावी मौसम में टिकट बंटवारे में सही लोगों को तरजीह नहीं दिये जाने को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. पार्टी के

हरिओम शरण नारायण

मनोज कुमार

शिव शंकर नारायण

संजू गुप्ता

प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रामचंद्र पूर्वे ने बड़ी ही चालाकी से राजद कार्यकर्ताओं की ताली यह कहते हुए बटोर ली कि पार्टी कार्यकर्ताओं के रुझान, ऊफान व मुस्कान के बूते ही राजद चुनावी जंग जीत लेगी. ईश्वरीय शक्ति के बाद सत्ता की शक्ति को विकास व बदलाव के लिए आवश्यक बताया. राष्ट्रीय एपाध्यक्ष ने राजनीति के सूत्र के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि भाजपा का वोट पूर्व की अपेक्षा नीचे की ओर खिसका है. भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बेरोजग-ारी की समस्या का निदान एवं कालाधन वापसी का वादा हवा-हवाई होकर रह गया. यह सच है कि बेरोजगारी हटने से ही गरीबी का खात्मा होगा. डुमरा प्रखंड राजद अध्यक्ष सुनील कुशवाहा की अध्यक्षता व संचालन में आयोजित सम्मेलन में पूर्व विधायक सुरेंद्र यादव, जिला राजद अध्यक्ष मो शफीक खां, प्रदेश महासचिव दिलीप राय, चंद्रजीत प्रसाद यादव, तारकेश्वर प्रसाद यादव, शिवचंद्र मंडल, राम कृष्ण कुशवाहा, नंद कुमार राय, गणेश गुप्ता, मनोज कुमार, अभिराम पांडेय, विनोद राय, खुर्शीद आलम, जवाहर यादव, सन्नी श्रीवास्तव व लालबाबू यादव समेत अन्य ने विधानसभा चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने का संकल्प लिया.

अब एक बात यहां विचारणीय है कि अगली चुनाव में जाति के साथ पार्टी का नारा देकर लड़ा जायेगा अथवा दोनों को किनारा कर विकास को मुद्दा बनाया जायेगा. कारण कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान यह देखा गया है कि सीतामढ़ी में जाति के साथ ही पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का प्रयास व्यापक स्तर पर पर्दे के पीछे से किया गया. नतीजा रहा कि विकास का मुद्दा जाति-पार्टी के नारे में दब कर रह गया. चुनावी भाषणों की अब तक परंपरा रही है कि हर एक पार्टी सामने वाले पर विभिन्न प्रकार का आरोप लगाते हुए मतदाता के दरवाजे पर दस्तक देती रही है. परंतु अब मतदाताओं के बीच पहले वाली बात नहीं है. अगर राजद कार्यकर्ता भाजपा की दिल्ली की हार का जयकार करते क्षेत्र में जायेंगे तो लगता नहीं है कि मतदाता कोई नोटिस लेने को तैयार होंगे. कारण कि अब सभी राजनीतिक दलों से जनता विकास का ब्लू प्रिंट मांगने की तैयारी में लग गयी है. साथ ही झूठ की राजनीति करने वालों को सबक सिखाने का मन भी बना लिया है. वैसे चुनावी रणनीति पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की सोच पर निर्भर है कि कैसा होगा. जहां तक सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र का सवाल है तो इस सीट पर वर्तमान में वैश्य बिरादरी के भाजपा के सुनील कुमार पिंटू विधायक हैं.

पिछले लोकसभा चुनाव में भी सीतामढ़ी सीट वैश्य प्रत्याशी को देने की मांग दबी जुबान से उठी थी. परंतु भाजपा गठबंधन के तहत कुशवाहा बिरादरी के राम कुमार शर्मा को टिकट दिया गया. चर्चा है कि तब वैश्य बिरादरी दलगत आधार पर भी उन्हे स्वीकारने को तब तक तैयार नहीं हुई थी, जब तक पार्टी के वरीय नेताओं ने पहल नहीं की. दूसरा यह कि नमो आंधी के बीच राजद से जहां यादव बिरादरी के पूर्व सांसद सीताराम यादव तो जदयू से इसी बिरादरी के डॉ अर्जुन राय चुनावी दंगल में ताल ठोंक रहे थे. नतीजतन जातीय व गैर भाजपा वोटों के बंटवारे ने दोनों की नैया मोदी लहर में डूबो दी. इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर इस सीट से कुशवाहा बिरादरी को टिकट मिलने की संभावना पर चर्चा करते हुए लोगों का कहना है कि वैश्य इसे स्वीकारने की स्थिति में नही है. सीतामढ़ी सीट से भाजपा को बेदखल तभी किया जा सकता है जब किसी मजबूत व साफ छबि के वैश्य प्रत्याशी को ही राजद अथवा जदयू गठबंधन से चुनावी समर में उतारा जायेगा. अगर ऐसा नहीं होता है तो किसी भी सूरत में भाजपा को परास्त करना आसान नहीं होगा.

एक अहम सवाल यह है कि सीतामढ़ी विधानसभा सीट से पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता को राजद मौका देगी अथवा कार्यकर्ताओं पर आयातित प्रत्याशी ठोंक कर नारा बुलंद करने की कवायद की जायेगी. इस पर सम्मेलन के दौरान ही कार्यकर्ताओं ने साफ कर दिया कि पार्टी के नेता व कार्यकर्ता को अपनी भूल में सुधार करना होगा. दूसरी ओर सम्मेलन के समापन के साथ ही दल के अंदर वगावत की चिंगारी लहकने लगी है. सच्चाई चाहे जो हो परंतु चर्चा है कि राजद के ही जिला के एक पूर्व सांसद का भाजपा विधायक से लगाव है. जिसके कारण पिछले कुछ चुनावों के दौरान जानबूझ कर ऐसा राजनीतिक खेल किया जाता है जिसकी वजह से भाजपा की जीत होती रही है. इस बार भी सम्मेलन के जरीये इस खेल की पिच तैयार की गई है. जिस पर एक धन कुबेर नया चेहरा को उतारा गया. वरिष्ठ राजद नेता शिव शंकर यादव ने सम्मेलन में अपनी अनुपस्थिति पर चर्चा करते हुए कहा कि सीतामढ़ी जिला में पार्टी के पूर्व सांसद की मौजूदगी वाले कार्यक्रम से परहेज करते है. कारण कि परिवारवाद को लेकर इनका इतिहास रहा है. पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी व्यक्तिवादी परंपरा का निर्वाह करने में लगा है. नगर राजद अध्यक्ष संजू गुप्ता का कहना है कि राजद सीतामढ़ी में नीति व सिद्धांत विहिन पार्टी बन गयी है. सम्मेलन को माई कार्यक्रम का रूप देकर एक बार फिर एक कुशवाहा को ठगने की साजिश की गयी है. नगर में आयोजित सम्मेलन की जानकारी तक नहीं दी गयी है. साफ लहजे में कहा कि अगर गैर वैश्य को टिकट इस बार दिया गया तो कार्यकर्ताओं के साथ पाला बदलने से परहेज नहीं करेंगे. सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से टिकट की आस लगाये वैश्य बिरादरी के प्रदेश राजद महासचिव मनोज कुमार की बोलती बंद है. मायूसी के साथ कहते है कि समर्पित कार्यकर्ताओं की हकमारी की साजिश की जा रही है, परंतु पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा है.■

feedback@chauthiduniya.com

अन्य ख़बरें

रंग हुआ फीका

मर्यादा पुरूषोतम राम की कर्मभूमि तथा महर्षि की तपोभूमि बक्सर में आयोजित दो दिवसीय विश्वमित्र महोत्सव का रंग फीका हो गया. सरकारी दुविधा के बाद आखिरकार कला, संस्कृति एवं युवा विभाग पटना द्वारा बक्सर में आयोजित विश्वमित्र में एक तरफ शास्त्रीय संगीत के सुर ताल सजे, तो दूसरी तरफ भोजपुरी के रांग रंग के संगीत से महफिल के श्रोता झुम इठे. बक्सर की भाजपा विधायिका प्रो .सुखदा पांडेय ने महोत्सव का उद्घाटन किया. दरभंगा घराने के प्रसिद्ध गायक पं . जगत नारायण पाठक ने ध्रुपद तथा राग भीम पलासी में शास्त्रीय संगीत सुनाया. पार्श्व गायिका पूर्णिमा ने भी अपने संगीत का जलवा दिखाया.भोजपुरी सम्राट भरत शर्मा, अशोक मिश्रा, मोहित कुमार, सत्येंद्र सिंह ने भोजपुरी के सरस गीतों के अलावा देवी पचरा, भजन, कजरी तथा पूर्वी गीतों को गाकर माटी की भीनी सुगंध से श्रोताओं को सराबोर कर दिये. दूसरे दिन फिल्म अभिनेता तथा गायक पवन सिंह होली गीत गाने लगे तो जिला प्रशासन के अधिकारी ने अश्लील बताकर गाने से रोक दिया. श्रोताओं की मांग पर जब इन्हें गीत नहीं गाने दिया तो श्रोताओं ने जमकर हंगामा व तोड़फोड़ किया. अंत में जिलाधिकारी रमण कुमार ने सभी कलाकारों को सम्मानित भी किया. एसपी जयंतकांत, डीसीसी मोबिन अली अंसारी, अपर समाहर्ता अजय कुमार ने बक्सर के सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महोत्सव पर प्रकाश डाला. **– जयमंगल पांडेय**

शिव जयंती पर निकाली झांकी

प्रजापिता ब्रहमा कुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय की सीतामढ़ी शाखा के तत्वावधान में 79 वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के अवसर पर झंडोत्तोलन व दीप प्रज्वलित कर परम पिता परमात्मा शिव की चैतन्य झांकी निकाली गयी. डॉ

रेणु चटर्जी के आवासीय सेवा केंद्र से निकाली गयी झांकी नगर भ्रमण के बाद सेवा केंद्र वापस हुई. कार्यक्रम में बीके वहन, गोपाल भाई, डॉ रेणु चटर्जी, डॉ वीणा गुप्ता, डॉ दिनेश गुप्ता, डॉ अरूण कुमार, राम शरण अग्रवाल, प्रो राज कुमार गुप्ता, डॉ वबिता कुमार, डॉ एसएन सिंह, अनिल सिंह, प्रो सुरेंद्र प्रसाद, नरेंद्र प्रसाद समेत सैकड़ों लोग शामिल थे. **– विम्मी कुमारी**

आम सभा का आयोजन

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज प्रखंड के बसबीट्टा बाजार पर संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में एक आम सभा का आयोजन किया गया. चंदेश्वर नारायण सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में गन्ना मूल्य बकाया भुगतान नही किये जाने, यूरिया की कालाबाजारी व धान की खरीद नही होने समेत अन्य सवालो पर खेत से सडक तक आंदोलन का संकल्प लिया गया. मौके पर मोर्चा के संस्थापक डॉ आनंद किशोर, जिलाध्यक्ष रामतपन सिंह, महासचिव वरूण कुमार सिंह, राम कैलाश सिंह, ओम प्रकाश कुशवाहा, ई. चंदन कुमार, लक्ष्मी सहनी, रामबाबू प्रसाद, वीरेंद्र सिंह व लालबाबू समेत अन्य थे. **– विनोद कुमार**

कैंप कार्यालय का उद्घाटन

सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर प्रखंड के कटरा मोड चौक के समीप गैर राजनीतिक महिला संगठन निर्भया सेना के जिला कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया गया. जिलाध्यक्ष सविता सिंह की अध्यक्षता में प्रदेश अध्यक्ष नीलम पांडेय ने फीता काट कर उद्घाटन किया. मौके पर प्रदेश महासचिव मो ताहा खान, प्रचार मंत्री सत्यम कुमार, मुजफ्फरपुर जिलाध्यक्ष आरती सिंह, महामंत्री सरोज देवी, सीतामढ़ी जिला महामंत्री शिवानी चौधरी समेत अन्य मौजूद थी. **–विभा सिन्हा**

बॉर्डर की सफाई में हंगामा

भारत-नेपाल सीमा पर अवस्थित कन्हमां समसी बॉर्डर पर अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए 11 फरवरी से सफाई आरंभ कर दिया गया. इस दौरान जेसीओ एवं एसएसबी, नेपाल जनपथ पुलिस एवं सीमावर्ती दोनों देश के ग्रामीणों के सहयो से नो मैंस लैंड पर बार्डर को अतिक्रमण मुक्त कराया. इस संदर्भ में एसएसबी कंपनी हेडक्वाटर इंचार्ज श्री मोक ने बताया कि भारत और नेपाल सरकार के संयुक्त निर्देशानुसार प्रशासन एवं ग्रामीणों के सहयोग से शान्तिपूर्वक अतिक्रमण मुक्त कराया गया, कार्य में सीमावर्ती कन्हमां के पूर्व मुखिया मो. जुम्मन एवं समसी के ग्रामीणों, व्यवसायियों के साथ-साथ नेपाल महोतरी के सभासद दीपनारायण साह ने भी सहयोग किया. वहीं दूसरे दिन नेपाल सभासद द्वारा सम्मी के तरफ से जेसीबी के जरीय तलाब के पास बने हुए पक्का से लेकर फुस तक के लगभग 10 से 12 घर को तोड़ा गया. साथ ही नेपाल के तरफ अन्य जगह रखे कटघेरा व झोपड़ी, व पक्का के घर का बना हुआ बरानदा और सीढ़ी को भी तोरा गया. नेपाल सभासद द्वारा जब इंडिया में रखे हुए कटघेरा और झोपड़ी हटाने की बात कही गयी तो लोग हंगामा करने लगे. लोगों ने कन्हमां के पूर्व मुखिया को फोन कर बुलाया. पूर्व मुखिया का कहना था कि अगर नेपाल में रोड बनाना है तो नेपाल में तोरिये इधर नहीं. जिला से सेकेन्ड कमाडर आकर लोगों के साथ बैठक की और तीन कटघेरो वालो को जल्द से जल्द हटाने की बात कही. साथ ही कहा कि बॉर्डर 10 गज तक खाली होगा. 31 मार्च तक सभी मकान वालों को नोटिस मिल जाएगा. ■ **– रूपा कुमारी**

बेगूसराय

सबक नहीं सीख रही है भाजपा

बरौनी रिफाइनरी यूनियन पर बीटीएमयू का कब्जा इसके स्थापना काल से ही था. 2011 के चुनाव में बीटीएमयू को श्रमिक विकास परिषद ने शिकस्त देकर लगभग पांच दशक से इसपर काबिज वामपंथ को सत्ताविहीन कर अपनी उभरती ताकत का एहसास कराया. लेकिन बीटीएमयू इससे निराश नहीं हुआ और कामगारों के हित में कार्य जारी रखा. दूसरी ओर श्रमिक विकास परिषद ने कर्मचारी कल्याण के साथ बरौनी रिफाइनरी की शोधन क्षमता के विस्तार के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर मंत्रालय को समर्पित किया और इसे स्वीकृति दिलाने के लिए प्रयासरत रहा. सफलता भी मिली और 18 जनवरी को बरौनी रिफाइनरी स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र प्रधान ने घोषणा की कि बरौनी रिफाइनरी की शोधन क्षमता का विस्तार 6 से बढ़ाकर 9 एमएमटीपीए किया जाएगा.

सुरेश चौहान

भाजपा अपनी गलतियों से सबक लेने को शायद तैयार नहीं है. तभी तो दिल्ली की पराजय से वह उबर भी नहीं पायी कि बेगूसराय में उसे एक और बड़ा झटका लगा. बरौनी रिफाइनरी यूनियन के चुनाव में पार्टी को मुंह की खानी पड़ी. भाजपा के भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध श्रमिक विकास परिषद के पदाधिकारियों के अतिआत्मविश्वास, सांगठनिक कमजोरी एवं भाजपा नेताओं के अन्तर्विरोध के कारण बरौनी रिफाइनरी के यूनियन चुनाव में वामपंथ के एटक से संबंद्ध बरौनी तेलशोधक मजदूर यूनियन (बीटीएमयू) 50 मतों से जीत हासिल की. बरौनी रिफाइनरी यूनियन का इस चुनाव परिणाम ने एक ओर भाकपा की मजबूत होती सांगठनिक क्षमता को उजागर किया है तो वहीं भाजपा के अन्तर्विरोध को उभारकर सरजमीं पर ला दिया है. दूसरी ओर बीएमटीयू में क्षेत्रवाद हावी रहा.

बरौनी रिफाइनरी यूनियन पर बीटीएमयू का कब्जा इसके स्थापना काल से ही था. 2011 के चुनाव में बीटीएमयू को श्रमिक विकास परिषद ने शिकस्त देकर लगभग पांच दशक से इसपर काबिज वामपंथ को सत्ताविहीन कर अपनी उभरती ताकत का एहसास कराया. लेकिन बीटीएमयू इससे निराश नहीं हुआ और कामगारों के हित में कार्य जारी रखा. दूसरी ओर श्रमिक विकास परिषद ने कर्मचारी कल्याण के साथ बरौनी रिफाइनरी की शोधन क्षमता के विस्तार के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर मंत्रालय को समर्पित किया और इसे स्वीकृति दिलाने के लिए प्रयासरत रहा. सफलता भी मिली और 18 जनवरी को बरौनी रिफाइनरी स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र प्रधान ने घोषणा की कि बरौनी रिफाइनरी की शोधन क्षमता का विस्तार 6 से बढ़ाकर 9 एमएमटीपीए किया जाएगा. साथ ही यहां पेट्रोकेमिकल्स उद्योग समूह की स्थापना की जाएगी. लेकिन श्रमिक विकास परिषद को भाजपा का अन्तर्कलह ले डूबा. श्रमिक परिषद द्वारा अध्यक्ष बदलना पार्टी के एक कद्दावर नेता को नागवार गुजरा और अन्तर्विरोध का स्वर यहीं से प्रारम्भ हुआ जो कालान्तर में गहराता गया अतिआत्मविश्वास से लवरेज श्रमिक विकास परिषद के पदाधिकारी भाजपा संगठन को संज्ञान में नहीं लिया जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा और चुनाव परिणाम ने सारा पोल खोल दिया.

संजय सिंह

शत्रुघ्न प्रसाद सिंह

भाकपा के पूर्व सांसद एवं बीएमटीयू के पूर्व अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद सिंह यूनियन की इस जीत पर कहते हैं कि अहंकार की हार दिल्ली से लेकर बरौनी तक हुई है. यह जीत बरौनी रिफाइनरी के कर्मचारियों की एकता की जीत है. केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र प्रधान ने पिछले दिनों बरौनी रिफाइनरी की शोधन क्षमता 6 से बढ़ाकर 9 एमएमटीपीए करने की जो घोषणा की है इसपर शत्रुघ्न प्रसाद सिंह कहते है कि कारखाने के विस्तारीकरण में जो तकनीकि विकास हुआ है और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जो मांग बढ़ी है इससे 10 एमएमटीपीए की शोधन क्षमता स्वयं प्राप्त कर लेने की स्थिति बरौनी रिफाइनरी ने बना ली है. बरौनी रिफाइनरी के बाद स्थापित रिफाइनरी के साथ पेट्रोकेमिकल कारखाना की स्थापना हुई. लेकिन केन्द्र की सभी सरकार ने जानबूझकर इसे अपने भाग्य के भरोसे छोड़ दिया. यदि सरकार की नीयत साफ है तो इसकी शोधन क्षमता 12 एमएमटीपीए करे तभी पेट्रोकेमिकल कारखाना की स्थापना का औचित्य बनेगा. बिहार का यह एकमात्र कारखाना है जो बेगूसराय के साथ राज्य के विकास से जुड़ा है. जन आन्दोलन के फलस्वरूप प्रस्तावित पेट्रोकेमिकल कारखाना को बरौनी के बजाय गुजरात के बड़ोदरा ले जाया गया. केन्द्रीय सरकार का बेगूसराय एवं बिहार के साथ छल वदस्तूर जारी है. हम विकास के इस सवाल को जनता के समर्थन से सड़क से संसद तक जारी रखेंगे. सभी राजनीतिक दलों को भी दलीय राजनीति से ऊपर उठकर बेगूसराय के विकास की लड़ाई में सहभागी होना चाहिए.

भाजपा के क्षेत्रीय संगठन प्रभारी एवं श्रमिक विकास परिषद के संगठन मंत्री संजय सिंह इस पराजय को भाजपा के कद्दावर नेता के अध्यक्ष पद पाने की महत्वाकांक्षा, व्यवसायिक प्रतिद्वन्दता एवं वर्चस्व से उपजे अन्तर्विरोध का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि हमें अपनों ने हराया. एक ओर भाजपा विरोध पर सभी दल एकजुट थे तो दूसरी ओर भाजपा में अन्दरूनी एकजुटता का अभाव रहा. हम इससे आहत है लेकिन हिम्मत नहीं हारे हैं और कर्माचारियों के हित में कार्य करते रहेंगे.■

feedback@chauthiduniya.com

कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली भारी बहुमत पर सीतामढ़ी व शिवहर जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का माहौल रहा. जिले के अलग -अलग स्थानों पर आप कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाल कर खुशी का इजहार किया. सीतामढ़ी शहर के गांधी मैदान से आप कार्यकर्ताओं ने बैंड -बाजा के साथ नगर में जुलूस निकाली. कार्यक्रम में जिला संयोजक ओम प्रकाश, सचिव दिलीप कुमार सिंह, इरशाद अहमद, डॉ आनंद किशोर, राकेश कुमार टुन्ना, संजीव सिंह, डॉ गोविंद ठाकुर, मुकेश कुमार मिश्र, विजय कुमार यादव, भवेश सर्राफ, संजय कुमार, मुकेश यादव व अजय गाोयल समेत अन्य थे. बैरगनिया में विकास जायसवाल के नेतृत्व में राज किशोर महतो, रामा पासवान, जाहिद हुसैन, अजय साह, ललन साह कानू, रविराज, प्रमोद जायसवाल व सलमान खां समेत अन्य ने खुशी का इजहार किया. शिवहर जिला में अधिवक्ता सतीशनंदन सिंह की अध्यक्षता में विजय जुलूस निकाली गयी. कार्यक्रम में राकेश कुमार, मो हसरत, ओम प्रकाश पासवान, जाबिर अंसारी, दयाशंकर मिश्र, अधिवक्ता चंद्रभूषण सिंह, प्रवीण कुमार, शिबु कुमार व सुरेश राय समेत अन्य थे. ■ *–विकास कुमार*

बेहतर चिकित्सीय सेवा के लिए संकल्पित शबनम आसिफ मेडिकल सेन्टर सम्पूर्ण जिलावासियों के सुखद भविष्य की कामना करता है और रंगों का त्योहार होली आपसी सौहार्द के बीच मनाने का पैगाम देता है।
24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध
हर तरह के ऑपरेशन की सुविधा आधुनिक संयत्रों से किया जाता है।
डॉ. (श्रीमती) शबनम आसिफ
फिजिसियन एवं सर्जन, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ
जान पुल चौक,बेतिया रोड,मोतिहारी
शबनम आसिफ मेडिकल सेन्टर

रामविलास पासवान जिन्दाबाद, चिराग पासवान जिन्दाबाद, पशुपतिनाथ पारस जिन्दाबाद
पुरे देशवासियों,जनप्रतिनिधियों,अधिकारियों व आम जनता खास कर नरकटिया विधान सभा क्षेत्र की जनता को रंगों का त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएँ।
रंगों का त्यौहार होली सबों के घर में खुशियां लाए,
यही अल्लाह से दुआ है.....
परवेज खां
राष्ट्रीय महासचिव, युवा लोजपा, आवास- बलुआ टाल, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण

एक नज़र

पोशाक राशि वितरित

गोगरी अनुमंडल क्षेत्र के माधवपुर पंचायत अन्तर्गत इंदरा माध्यमिक विद्यालय में पोशाक व साईकिल राशि का वितरण किया गया. इस समारोह में पोशाक राशि का वितरण युवा समाज सेवी सह वरिष्ठ भाजपा नेता सह जिप सदस्य प्रतिनिधि अखिल कुमार राय उर्फ मंटू ने किया. वहीं मंटू राय ने कहा कि पोशाक राशि का उपयोग पोशाक खरीद में ही करें. इन्होंने कहा कि विद्यालय में एक समान पोशाक पहनकर आने से एक रूपता आती है. इन्होंने कहा कि छात्र व छात्रा मन लगाकर पढे इसके लिए सरकार हर वक्त आपके साथ है. वहं विद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि नवम के 46 छात्राओं के बीच प्रति छात्र 25 सौ की दर से तथा कक्षा दशम के 122 छात्राओं के बीच 1 हजार रूपये की दर से राशि का वितरण किया गया. मौके पर विद्यालय के सचिव अखिल कुमार राय, अध्यक्ष रजनीश चौधरी, विजय सिंह, सुरेश राय, हरिश कुमार, संजय सिंह, निरंजन राय, शशिकांत मिश्रा, चन्द्रशेखर सिंह, विनोद मिश्र, रजनीश मिश्र, मनीषा कुमारी, नीतू कुमारी, आरजू कुमारी, शबनम प्रवीण, सपना चौधरी सहित दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे.

खेल से बढ़ता है प्रेम

गोगरी अनुमंडल क्षेत्र के कवेला पंचायत अन्तर्गत डुमरिया खुर्द मध्य विद्यालय के मैदान में इमेश खेल संस्थान के तत्वावधान में दो दिवसीय अंतर जिला बॉलीबॉल टूर्नामेन्ट का आयोजन किया गया. जिसका विविधवत उद्घाटन गेंद फेंककर नगर परिषद अध्यक्ष मनोहर कुमार यादव ने किया. नगर परिषद अध्यक्ष ने सभी खिलाड़ियो से परिचय प्राप्त किया. इन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि खेल के माध्यम से समाज के नौजवानों के बीच उत्पन्न कलह दूर होता है और आपस में प्रेम बढ़ता है. इन्होंने कहा कि खेल से संगठित होने का एक नया विचार जागृत होता है तथा इसके द्वारा कुरितियां स्वयं दूर हो जाती है. समारोह को जिला बॉलीबाल संघ के सचिव रविन्द्र झा, कोषाध्यक्ष सह वरिष्ठ पत्रकार शिव कुमार राय आदि ने भी संबोधित करते हुए कहा कि यह दो दिवसीय खेल है. इसमें विभिन्न जिलों से 10 टीमें भाग ले रही है. इद्घाटन मैच कन्हैयाचक व किशनगंज टीम के बीच खेला गया. मैच के निर्णायक की भूमिका में अजय चौधरी थे. इस मौके पर दिनेश चन्द्र मिश्र, अजय ठाकुर, सुभाष चन्द्र चौधरी, अभिनव मुखिया, बुलेट कुमार समेत सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे.

शोक

गोगरी अनमंडल क्षेत्र के हरिपुर गांव के पास टेलिफोन के खंभा से टकराकर बाईक सवार एसएसबी सैनिक बमबम यादव की घटना स्थल पर ही मौत हो गई. वहीं बाईक सवार दो अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गये. बाईकर सवार अन्य दो बरातियों में जर्नादन यादव व केशरी यादव शामिल हैं. घटना की खबर मिलते ही आसपास चल रहे बरातियों ने तीनों को इठाकर इलाज के लिस रेफरल अस्पताल गोगरी लाया. जहां चिकित्सकों ने सैनिक बमबम यादव को मृत घोषित कर दिया. वहीं प्राथमिक उपचार के बाद घायल के गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर ईलाज के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया. जहां घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है. इधर एसएसबी सैनिक बमबम यादव की मौत की खबर मिलते ही पूरा गांव गमगीन हो गया. अपने पुत्र की मौत की खबर मिलते ही मृत सैनिक की माता सुलोचना देवी का रो रोकर बुरा हाल हो गया. वही मृतक की पत्नी प्रिया देवी भी बेसुध जमीन पर पड़ी हुई थी. विदित हो कि मृत सैनिक बमबम यादव अपने पिछे 6 माह का एक पुत्र को छोड़ गये. वे चार भाईयों तथा दो बहन में सबसे छोटे थे. इनके मृत्यू की घटना सुनकर इनके परिवार को सांत्वना देने के लिए लोजपा नेत्री प्रो0 सुहेली मेहता, भाजपा नेता अखिल कुमार राय उर्फ मंटू राय, पूर्व विधायक रणवीर यादव, सदर विधायक रणवीर यादव, जिप अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव, पूर्व मंत्री रामानंद प्रसाद सिंह, एवं राजद प्रखंड अध्यक्ष अखिलेश्वर दास सहित सैकड़ों लोग पहुंचे. ज्ञात हो कि चौथी दुनिया के संवाददाता गीता कुमार यादव का मृत सैनिक चचेरे भाई थे.■ **– गीता कुमार**

गया जिलेवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं
किसानों एवं मगधवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ
आईए हम सब मिलकर मगध के विकास में कदम बढ़ाएँ...
डॉ. रामाश्रय शर्मा
प्रदेश महासचिव
जदयू (किसान प्रकोष्ट)
मो0-9798284541

किसानों को होली की हार्दिक बधाई
माँ फुलमत ट्रेडर्स
सरबदीपुर, परैया, गया
कृषि उपकरणों का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान
प्रो.-रामाधार सिंह
मो.-9798284541

पप्पू यादव की अनोखी प्रेम कहानी

सांसद पप्पू यादव बिहार की राजनिति के जाने-माने चेहरों में से एक हैं. सिर्फ पप्पू यादव हीं नहीं बल्कि उनकी पत्नी रंजीत रंजन ने भी राजनीति में अपनी एक जगह बनाई हुई है. पिछले साल हुए लोक सभा चुनाव में दोनों हीं सांसद चुने गए थे. पप्पू राजद सांसद है तो उनकी पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस सांसद. जितना इन दोनों का राजनीतिक करियर चर्चा में रहा है, उतनी इनकी प्रेम कहानी भी. तो आइए जानते हैं इन दोनों की हसीन प्रेम कहानी के बारे में और कुछ कही-अनकही बातों के बारे में.

राधिका

पप्पू यादव की प्रेम कहानी किसी भी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. एक समय था जब लोग पप्पू को बाहुबली नेता के रूप में जानते थे. पप्पू यादव के जीवन में रंजीत रंजन के आने की कहानी पूरी फ़िल्मी है.

स्टोरी में ट्विस्ट

पटना के बांकीपुर जेल में बंद पप्पू अक्सर जेल अधीक्षक के आवास से लगे मैदान में लड़कों को खेलते देखा करते थे. इन्हीं लड़कों में रंजीत के छोटे भाई विक्की भी थे. इन लड़कों से मिलने-मिलाने के क्रम में विक्की से पप्पू यादव की नज़दीकी बढ़ी. लेकिन कहानी में ट्विस्ट उस समय आया जब पप्पू यादव ने विक्की की फैमिली फैमिली एल्बम में रंजीत की टेनिस खेलती तस्वीर देखी और उसके बाद जो हुआ वो पप्पू के राजनीतिक जीवन में चल रहे भूचाल के बीच एक और तूफ़ान की तरह था.पप्पू फ़ोटो देखकर रंजीत पर फिदा हो गए और फिर शुरू हुई अपने प्रेम प्रस्ताव को लेकर रंजीत तक पहुंचने की लंबी जंग. पप्पू यादव जेल से छूटने के बाद रंजीत से मिलने के लिए अक्सर उस टेनिस क्लब में पहुंच जाते थे, जहां वो टेनिस खेला करती थीं. रंजीत को ये सब बातें नागवार गुज़रती थीं, उन्होंने पप्पू यादव को कई बार मना किया, मिलने से रोका और कठोर शब्द भी कहे. लेकिन पप्पू यादव डटे रहे. अपने प्यार को हासिल करने के लिए पप्पू ने सारी हदें पार कर दीं. उन्होंने कभी पटना, कभी दिल्ली तो कभी लुधियाना के काफी चक्कर काटे थे. पप्पू के लिए अपना प्यार पाना आसान न था.

पप्पू यादव से अपनी शादी के बारे में रंजीत रंजन का कहना है कि दूसरे धर्म में शादी की बात थी. अलग राज्य से होने के कारण हमारी तरफ से ही थोड़ी समस्या थी. उनकी तरफ से तो पूरा सहयोग था.

रंजीत आगे कहती हैं कि उनके ससुर खुले विचारों के हैं. और उनके सास और ससुर ने इस शादी में पूरा सहयोग किया था.

अपने और पप्पू यादव के रिश्ते के बारे में रंजीत ने बताया कि तीन साल तक हमारी दोस्ती चली थी. पूरे संघर्ष के बाद भी उन्होंने मेरा साथ दिया. फ़रवरी 1992 से चल रहे प्रेम प्रसंग के बाद मेरी शादी 1994 में हुई. वो दौर बड़ा संघर्ष वाला था. उस समय एक दूसरे से मिलना, पटना आना जाना बहुत बड़ी बात थी. मैं ख़ुशनसीब हूं कि मुझे बहुत अच्छा पति मिला है.

अपने प्यार को पाने के रास्ते पर चलते हुए पप्पू की जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आए जब उन्हें लगा कि सब कुछ बिखर सा गया है. एक बार तो रंजीत ने यहां तक कह दिया कि वे सिख हैं और पप्पू हिंदू और उनके परिवार वाले ऐसा होने नहीं देंगे. लेकिन इतना होने के बाद भी पप्पू ने अपनी हिम्मत बनाए रखी.

द्रोहकाल का पथिक

पप्पू यादव ने अपनी पुस्तक द्रोहकाल का पथिक में विस्तार से अपने प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है. उन्होंने लिखा है कि कैसे हताश-परेशान होकर उन्होंने एक बार नींद की ढेरों गोलियां खा लीं. उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसके बाद रंजीत का व्यवहार थोड़ा सामान्य हुआ और बात आगे बढ़ी.

रंजीत रंजन के पिता ग्रंथी थे और शुरू में इस विवाह के ख़िलाफ़ थे. लेकिन पप्पू यादव के आनंद मार्गी पिता चंद्र नारायण प्रसाद और माता शांति प्रिया की ओर से कोई समस्या नहीं थे. वे दोनों इस शादी के पक्ष में थे.

पप्पू ने जारी रखी कोशिशें

जब रंजीत के परिजनों की ओर से शादी को मंज़ूर नहीं किया जा रहा था, तो पप्पू यादव रंजीत के बहन-बहनोई को मनाने चंडीगढ़ पहुंच गए. लेकिन वहां भी उनकी दाल नहीं गली और दोनों ने इस रिश्ते को मंज़ूरी नहीं दी. दिल्ली में रंजीत के एक और बहनोई ने भी पप्पू यादव को घास तक नहीं डाली. इस वजह से पप्पू यादव काफी निराश हुए.

शादी के लिए एसएस अहलूवालिया की मदद

इसी बीच किसी ने उन्हें सलाह दी कि उस समय कांग्रेस में रहे एसएस अहलूवालिया उनकी मदद कर सकते हैं. पप्पू यादव उनसे मिलने दिल्ली जा पहुंचे और मदद की गुहार लगाई. पप्पू यादव ने अपनी किताब में इसका ज़िक्र किया है कैसे एसएस अहलूवालिया साहब की पहल से रंजीत के सिख परिजनों को मनाने में मदद मिली. ख़ैर रंजीत के माता-पिता के राजी हो जाने के बाद भी उनके अन्य परिजन तैयार नहीं थे. आख़िरकार शादी की तैयारी हुई और फरवरी 1994 में पप्पू यादव और रंजीत की शादी हो गई.

क्लाइमेक्स

पप्पू यादव की शादी पहले पूर्णिया के गुरुद्वारे में होनी थी, लेकिन फिर तय हुआ कि शादी आनंद मार्ग की पद्धति से होगी. इस बीच रंजीत और उनके परिजनों को लेकर आ रहा चार्टर्ड विमान रास्ता भटक गया और देरी के कारण हंगामा मच गया. लेकिन बाद में पता चला कि विमान का पायलट रास्ता भटक गया था. खैर विमान पहुंचा और लोगों ने राहत की सांस ली.

पूर्णिया की सड़कों को पूरी तरह सजा दिया गया था. शहर के सारे होटल और गेस्ट हाउस सब बुक थे. आम और ख़ास सबके लिए व्यवस्था की गई थी. पप्पू यादव की शादी में चौधरी देवीलाल, डीपी यादव और राज बब्बर भी शामिल हुए. तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी थोड़ी देर के लिए उनकी शादी में आए. और आखिरकर तमाम दिक्कतों से लड़ने के बाद पप्पू यादव और रंजीत रंजन की शादी हो गई और आज दोनों एक सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

02 मार्च -08 मार्च 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग बना अराजकता का अड्डा

सूचना आयुक्त ही उड़ा रहे हैं आरटीआई क़ानून का माखौल

सूचना आयुक्त अरविंद सिंह बिष्ट

आरटीआई कार्यकर्ताओं के साथ हो रही बदसलूकियां, राज्यपाल से हस्तक्षेप की अपील

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के आयुक्त खुद ही सूचना के अधिकार कानून का माखौल उड़ाने में लगे हैं. इसके पीछे उनकी गैर-जानकारी नहीं, बल्कि सरकार और उसके नौकरशाहों को बचाने की मंशा है. संदर्भित विभाग से सूचना नहीं मिलने के बाद ही कोई आरटीआई कार्यकर्ता सूचना आयोग में अपील के लिए जाता है. अपील करने पर सूचना का अधिकार कानून की धारा-19 के तहत आयोग को सुनवाई करने और उचित फैसला करने का अधिकार है. लेकिन शासन और नौकरशाहों को बचाने के लिए सूचना आयुक्त आरटीआई कार्यकर्ताओं की अपील को धारा-19 में नहीं दर्ज कर, धारा-18 में दर्ज कर रहे हैं. धारा-18 केवल शिकायत दर्ज करने के लिए है, इस धारा के तहत सूचना आयुक्त के पास किसी तरह की निर्णयात्मक कार्रवाई के अधिकार का प्रावधान नहीं होता है. यदि सूचना आयुक्तों के इस रवैये की शिकायत की जाती है तो आरटीआई कार्यकर्ताओं को अपमानित किया जाता है और यहां तक कि उन्हें धक्के मारकर कार्यालय से बाहर निकाला जाता है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है और उन्हें गिरफ्तार करा दिया जाता है.

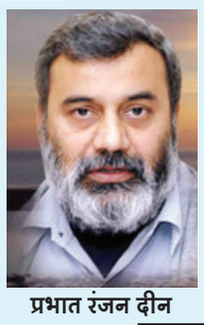

प्रभात रंजन दीन

उत्तर प्रदेश में सूचना के अधिकार का कबाड़ा हो गया है. आरटीआई योद्धाओं की हिफाजत के लिए देश की सर्वोच्च अदालत तक चिंतित है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सूचना आयोग के आयुक्त ही समाजसेवियों और आरटीआई कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकियां कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा पर सवाल बन रहे हैं. उत्तर प्रदेश सरकार मतिशून्य है, उसे अपने किए को संभालने और दुरुस्त करने के विवेक से कोई मतलब नहीं है. इस वजह से उत्तर प्रदेश के सूचना कार्यकर्ताओं की भारी संख्या त्रस्त है और राज्यपाल से संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने और इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग लगातार हो रही है.

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के आयुक्त खुद ही सूचना के अधिकार कानून का माखौल उड़ाने में लगे हैं. इसके पीछे उनकी गैर-जानकारी नहीं, बल्कि सरकार और उसके नौकरशाहों को बचाने की मंशा है. संदर्भित विभाग से सूचना नहीं मिलने के बाद ही कोई आरटीआई कार्यकर्ता सूचना आयोग में अपील के लिए जाता है. अपील करने पर सूचना का अधिकार कानून की धारा 19 के तहत आयोग को सुनवाई करने और उचित फैसला करने का अधिकार है. लेकिन शासन और नौकरशाहों को बचाने के लिए सूचना आयुक्त आरटीआई कार्यकर्ताओं की अपील को धारा-19 में नहीं दर्ज कर, धारा-18 में दर्ज कर रहे हैं. धारा-18 केवल शिकायत दर्ज करने के लिए है, इस धारा के तहत सूचना आयुक्त के पास किसी तरह की निर्णयात्मक कार्रवाई के अधिकार का प्रावधान नहीं होता है. यदि सूचना आयुक्तों के इस रवैये की शिकायत की जाती है तो आरटीआई कार्यकर्ताओं को अपमानित किया जाता है और यहां तक कि उन्हें धक्के मारकर कार्यालय से बाहर निकाला जाता है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है और उन्हें गिरफ्तार करा दिया जाता है. यहां इस बात का ध्यान भी नहीं रखा जाता है कि अपमानित कर जेल भेजे जाने वाले आरटीआई कार्यकर्ता की उम्र कितनी है, वह बुजुर्ग तो नहीं है. इससे जुड़ी शिकायतें मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक की जा रही हैं, लेकिन उनके कानों में तेल भरा है.

कुछ ही दिनों पहले प्रदेश के बुजुर्ग आरटीआई कार्यकर्ता अशोक कुमार गोयल के साथ सूचना आयुक्त अरविंद सिंह बिष्ट ने बदसलूकी की, उन्हें कक्ष से धक्के देकर बाहर निकलवाया. उनका इतने से भी मन नहीं भरा तो पुलिस पर दबाव डालकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई और उन्हें अपमानित कर, गिरफ्तार कर जेल भिजवाया. अरविंद सिंह बिष्ट हाल तक एक संजीदा पत्रकार थे, लेकिन सूचना आयुक्त बनते ही सत्ता दंभ में उतराने लगे. उन्होंने पितातुल्य अशोक गोयल की उम्र का कोई ख्याल नहीं रखा. यहां तक कि हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर के मरीज बुजुर्ग को पुलिस ने रात भर दवा भी नहीं लेने दी. अशोक गोयल ने केवल सूचना ही तो मांगी थी! फिर सूचना आयुक्त ने ऐसी बेजा हरकत क्यों की, इस बारे में अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार ने उनसे पूछने की जहमत भी नहीं उठाई. गोयल साहब की सारी शिकायतें मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक लंबित हैं, लेकिन सूचना आयुक्त की बेजा हरकतें जारी हैं. आरटीआई कार्यकर्ताओं का अपमान जारी है.

अभी पिछले ही दिनों सूचना आयुक्त अरविंद सिंह बिष्ट ने फिर एक बुजुर्ग आरटीआई योद्धा महेंद्र अग्रवाल से बदसलूकी की. उनका कसूर यह था कि सूचना आयुक्त के कक्ष में उनका मोबाइल फोन क्यों बजा? बिष्ट इसे पीठ की अवमानना मानते हैं. अरविंद सिंह बिष्ट को यह मुगालता है कि वे सूचना आयुक्त बनकर जज बन गए हैं. जबकि थोड़ी बहुत भी क़ानून की जानकारी रखने वाला यह जानता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि सूचना आयोग न्यायिक संस्था (ज्यूडिशियल बॉडी) नहीं है, बल्कि वह महज एक प्रशासनिक संस्था (एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी) है.

बहरहाल, महेंद्र अग्रवाल ने आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई हिदायतों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए इंतजाम के बारे में सूचना का अधिकार कानून के तहत सूचना मांगी थी. उल्लेखनीय है कि गौरव अग्रवाल की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. इस पर गृह मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स का गठन करते हुए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों, गृह विभाग के प्रमुख सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को परिपत्र जारी कर तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. कार्रवाई के बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय से सूचना मांगने पर कोई जवाब तो नहीं दिया गया, बल्कि हास्यास्पद तरीके से उस आवेदन पत्र को ऊर्जा विभाग के पास भेज दिया गया. यानी,

कुछ ही दिनों पहले प्रदेश के बुजुर्ग आरटीआई कार्यकर्ता अशोक कुमार गोयल के साथ सूचना आयुक्त अरविंद सिंह बिष्ट ने बदसलूकी की, उन्हें कक्ष से धक्के देकर बाहर निकलवाया. उनका इतने से भी मन नहीं भरा तो पुलिस पर दबाव डालकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई और उन्हें अपमानित कर, गिरफ्तार कर जेल भिजवाया. अरविंद सिंह बिष्ट हाल तक एक संजीदा पत्रकार थे, लेकिन सूचना आयुक्त बनते ही सत्ता दंभ में उतराने लगे. उन्होंने पितातुल्य अशोक गोयल की उम्र का कोई ख्याल नहीं रखा. यहां तक कि हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर के मरीज बुजुर्ग को पुलिस ने रात भर दवा भी नहीं लेने दी.

अशोक कुमार गोयल

महेंद्र अग्रवाल

उस्मानी से उम्मीद

राज्य के मुख्य सचिव रहे जावेद उस्मानी के मुख्य सूचना आयुक्त बनने के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि अब राज्य सूचना आयोग में अनुशासन का माहौल बनेगा और अराजकता दूर होगी. जावेद उस्मानी ने पिछले दिनों राज्यपाल के समक्ष मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली.

मुख्यमंत्री सचिवालय में किस स्तर के अधिकारी बैठते हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. प्रमुख सचिव गृह के कार्यालय ने भी सूचना देने से इंकार कर दिया. डीजीपी ने महेंद्र अग्रवाल को सूचना देने के बजाय सभी जोनल आईजी को निर्देश जारी कर दिया. इन जगहों से नकारे जाने के बाद ही महेंद्र अग्रवाल ने सूचना आयोग में अपील दाखिल की थी. लेकिन मुख्यमंत्री सचिवालय और अन्य नौकरशाहों की हिफाजत करते हुए अरविंद सिंह बिष्ट ने महेंद्र अग्रवाल की अपील को अपील नहीं माना और उसे शिकायत में दर्ज कर लिया. इस मामले को तूल पकड़ता देख, उन्होंने पूरे प्रकरण को मोबाइल बजने से लेकर पीठ की अवमानना से जोड़ दिया, और महेंद्र अग्रवाल के खिलाफ क़ानूनी चेतावनियों भरा नोटिस जारी कर दिया. सूचना आयुक्त नोटिस पर महेंद्र अग्रवाल का जवाब राज्य सूचना आयोग की कानूनी दुर्दशा का सचित्र विवरण देता है.

महेंद्र अग्रवाल ने राज्यपाल राम नाइक को ज्ञापन देकर सुरक्षा की मांग की है और कहा है कि सूचना आयुक्त अरविंद सिंह बिष्ट उन पर मनगढ़ंत मुक़दमे लाद कर फंसा सकते हैं और प्रताड़ित कर सकते हैं. उन्होंने राज्यपाल को यह भी बताया है कि सूचना आयुक्त के अभद्र व्यवहार की राज्यपाल से लेकर स्थानीय पुलिस, संयुक्त राष्ट्र संघ व राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में शिकायत करने से वे बौखला उठे हैं. श्री अग्रवाल ने कहा कि उनकी शिकायतों की पुष्टि सूचना आयुक्त के कक्ष में लगे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखकर की जा सकती है. उसकी सीडी के लिए श्री अग्रवाल ने आयोग से भी आग्रह किया है. महेंद्र अग्रवाल ने राज्यपाल से कहा है कि सूचना आयुक्त अरविन्द सिंह बिष्ट समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के समधी हैं. उनकी पत्नी श्रीमती एमबी बिष्ट एलडीए में सहायक निदेशक हैं और उनका बेटा एलडीए में ही ठेकेदारी करता है. श्री बिष्ट के संबंध न केवल सत्ताधारी पार्टी और सरकार सं नहीं बल्कि ठेकेदारों और बिल्डरों से भी है. अग्रवाल ने अपने खिलाफ साजिश रचे जाने की आशंका जाहिर की है.

इसी तरह सुनवाई के लिए सूचना आयोग पहुंचे आरटीआई कार्यकर्ता नीरज शर्मा के साथ भी सूचना आयुक्त अरविंद सिंह बिष्ट ने पिछले दिनों बदसलूकी की और पुलिस के बल पर उन्हें घंटों कस्टडी में बिठाए रखा. इसपर आरटीआई कार्यकर्ता समाजसेवी डॉ. नूतन ठाकुर, देवेन्द्र दीक्षित आदि भक्तभोगी नीरज शर्मा को लखनऊ के हजरतगंज थाने लेकर गए और सूचना आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई. इस बारे में राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया गया है. राज्यपाल से अरविन्द सिंह बिष्ट के दुर्व्यवहार की जांच कराते हुए उन्हें आरटीआई एक्ट की धारा-17 के तहत पद से हटाने की मांग की गई है. सूचना आयुक्त पर नीरज शर्मा का आरोप है कि उन्होंने न केवल उनके साथ गलत सलूक किया बल्कि एक कागज पर जबरन यह भी लिखवा लिया कि उन्हें मांगी गई सूचना मिल गई है.

महेंद्र अग्रवाल ने राज्यपाल को दिए ज्ञापन में यह मांग की है कि सभी सूचना आयुक्तों और उनके परिवार की संपत्ति की जानकारी आवश्यक रूप से सार्वजनिक की जाए. यह प्रक्रिया हर साल दोहराई जाए. सूचना आयुक्तों के कार्यों को हर साल बदला (रोटेशन) जाए. सूचना आयुक्तों के कार्यालय आने तथा सुनवाई प्रारंभ करने का समय सुनिश्चित किया जाए. सूचना आयुक्तों द्वारा निस्तारित वादों की समीक्षा के लिए एक अलग पीठ का गठन किया जाए. लंबित वादों के निपटारे की समय सीमा निर्धारित की जाए. आवेदकों द्वारा दाखिल की गई शिकायतों और अपीलों को स्वीकार करने अथवा नहीं करने की सूचना देना अनिवार्य बनाया जाए. आयोग में आवेदकों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था की जाए. सूचना आयोग के खर्चों का भी अन्य विभागों की तरह हर वर्ष ऑडिट हो. आयोग की वेबसाइट को नियमित तौर पर अपडेट किए जाने का नियम बने. आयोग की गैलरी और सूचना आयुक्तों के कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरों को काम लायक रखा जाए और उसकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए. तारीख तय करने में सूचना आयुक्तों की निरंकुशता पर कारगर तरीके से अंकुश लगाया जाए और सूचना आयुक्तों को आवेदकों के साथ अच्छा व्यवहार किए जाने की सख्त हिदायत दी जाए. ■

मुख्य सूचना अयुक्त पद की शपथ लेते ज़ावेद उस्मानी

feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश की खबरें इंटरनेट पर पढ़ने के लिए www.up.chauthiduniya.com लॉगऑन करें.

केजरी और ओवैसी बढ़ाएंगे सपा-बसपा की मुश्किलें

सी. लाल

10 फरवरी को दिल्ली विधान सभा चुनाव का परिणाम आया तो भारतीय राजनीतिक इतिहास में आम आदमी पार्टी ने नया इतिहास रचकर राजनीतिक पंडितों व समीक्षकों के आकलन को पीछे छोड़ दिया. मीडिया से लेकर चौराहों, चाय-पान की दुकानों पर केजरीवाल की चर्चा शुरू होकर थमने का नाम नहीं ले रही है. दिल्ली चुनाव परिणाम अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए सदमे से कम नहीं है. इस चुनाव परिणाम से सबसे बड़ा झटका अमित शाह को लगा क्योंकि उन्हें चुनाव प्रबंधन का विशेषज्ञ व कुशल रणनीतिकार माना जाता रहा है, पर दिल्ली की जनता ने उनकी विशेषज्ञता पर सवाल खड़े कर दिए. शाह को बेटे की शादी के दिन ही दिल्ली चुनाव परिणाम ने ऐसा सदमा दिया कि शादी का उत्साह जाता रहा. दिल्ली में भाजपा की हार की समीक्षा में भाजपा और संघ दोनों लगे हुए हैं, वहीं, आआपा की ऐतिहासिक जीत से भाजपा विरोधी सपा, बसपा, राजद, टीएमसी, जदयू आदि दलों के नेताओं ने राहत की सांस ली है.

दिल्ली चुनाव में भाजपा की हार का प्रमुख कारण पिछड़ों की भूमिका रही है. लोक सभा चुनाव में पिछड़े, अतिपिछड़े, दलित व आदिवासी वर्ग ने भाजपा का साथ दिया, क्योंकि नरेन्द्र मोदी ने अपने को चाय बेचने वाला और अति पिछड़ी जाति का प्रचारित किया. अमित शाह सहित भाजपा व संघ के नेताओं, कार्यकर्ताओं ने सामाजिक न्याय व अतिपिछड़ों के मुद्दे को काफी जोर-शोर से उठाया. हरियाणा में जाट या गूजर, महाराष्ट्र में अति पिछड़ी बंजारा जाति की पंकजा मुंडे व झारखंड में आदिवासी या अति पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाने का प्रचार किया गया और जब सरकार बनाने का मौका आया तो अन्य को कुर्सी पर बैठा दिया गया. दिल्ली में जाट, गूजर सहित तमाम अतिपिछड़ी जातियां 40 प्रतिशत से अधिक हैं, जो नाराज होकर भाजपा छोड़ आप के साथ चले गए. यदि अब भाजपा बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश राज्यों के चुनावों के लिए अपनी नीति नहीं बदलेगी तो भाजपा का हर जगह दिल्ली जैसा ही हश्र होगा.

नरेन्द्र मोदी व अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा को मिल रही सफलता से कई दलों पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन दिल्ली चुनाव ने बादल को केवल गरजने वाला साबित किया, इस हार ने भाजपा को अच्छा सबक सिखाया है. लोक सभा चुनाव के बाद एक-एक करके महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में बड़ी विजय मिलने से भाजपा नेताओं में गुरूर बढ़ गया था. दिल्ली ने उन्हें जमीनी सोच बनाए रखने का मौका दिया है, अमित शाह की राजनीति से न केवल दिल्ली बल्कि राज्यों में भाजपा के परंपरागत समर्थक व पुराने नेता दरकिनार हो गए और आयातित नेताओं को महत्व मिलने से कार्यकर्ता हताश हो गए. यूपी में शाह व सुनील बसंल ने डेढ़ दर्जन से अधिक विभाग व क्षेत्रीय संगठन मंत्रियों की छुट्टी कर दी और तमाम तेज तर्रार व जनाधार वाले नेताओं का भविष्य अधर में डाल दिया था. दिल्ली चुनाव परिणामों से उन्हें राहत मिली है.

नरेन्द्र मोदी व अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा को मिल रही सफलता से कई दलों पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन दिल्ली चुनाव ने बादल को केवल गरजने वाला साबित किया, इस हार ने भाजपा को अच्छा सबक सिखाया है. लोक सभा चुनाव के बाद एक-एक करके महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में बड़ी विजय मिलने से भाजपा नेताओं में गुरूर बढ़ गया था. दिल्ली ने उन्हें जमीनी सोच बनाए रखने का मौका दिया है, अमित शाह की राजनीति से न केवल दिल्ली बल्कि राज्यों में भाजपा के परंपरागत समर्थक व पुराने नेता दरकिनार हो गए और आयातित नेताओं को महत्व मिलने से कार्यकर्ता हताश हो गए.

दिल्ली चुनाव में मतों के ध्रुवीकरण का विश्लेषण किया जाए तो भाजपा का मत प्रतिशत 2013 के विधान सभा चुनावों की तुलना में 0.54 प्रतिशत बढ़ा है. परंतु लोक सभा चुनाव में मिले 44 प्रतिशत मतों की जुलना में 12 प्रतिशत मत कम मिला है जबकि आप का मत प्रतिशत लगभग 16 प्रतिशत बढ़ा है. कांग्रेस व अन्य कथित धर्म निरपेक्ष दलों का जो मत प्रतिशत घटा, वह सीधे आप के साथ जुड़ गया है. आप से अन्य दलों को भी काफी खतरा है. आप से पंजाब व उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा. उत्तर प्रदेश में 2014 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सपा का और उसके बाद बसपा का नुकसान होना अवश्यभावी है. आप संयम और परपक्वता से काम ले तो उत्तर प्रदेश में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकती है. दिल्ली में 954 फीसदी से अधिक मुस्लिम मतदाताओं ने आप का साथ दिया है. आप के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और जो युवा भाजपा के साथ जुडे थे वे आप के साथ जा सकते हैं. आप से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा खतरा समाजवादी पार्टी को है, क्योंकि आप अब मुस्लिम वोट की प्रबल दावेदार पार्टी बन गई है. यूपी में सपा का आधार वोट यादव-मुस्लिम व बसपा का दलित-मुस्लिम रहा है. ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया इत्तेहाद मजलिस-ए-मुसलमीन भी बड़ी तेजी से उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने पांव पसारती जा रही है. जिससे भाजपा को फायदा होगा तो सपा, बसपा को नुकसान. कांग्रेस के साथ तो अब मुस्लिम समुदाय जाता दिख नहीं रहा है.

बिहार में 2015, असम व प. बंगाल में 2016 एवं उत्तर प्रदेश में 2017 में विधान सभा चुनाव होने हैं. जीतन राम मांझी के कारण बिहार की राजनीति में नया मोड़ आने वाला है. मांझी बहुमत जुटा गए तो राजद-जदयू-कांग्रेस महागठबंधन पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा और भाजपा इसी राजनीति के तहत मांझी मुद्दे को गरम करने में लगी है. बंगाल में तीन मुस्लिम पार्टियों सहित पांच दलों ने गठबंधन कर ममता के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है. अगर इनका वामपंथी पार्टियों से गठबंधन हो गया तो यह ममता के लिए बड़े खतरे की घंटी है. ऐसे में कांग्रेस-टीएमसी का पुनर्गठबंधन संभव है.

दिल्ली चुनाव परिणाम से सपा को बड़ी राहत मिलने की वजह यह भी है कि सपा के कई विधायक जो भाजपा को अगला ठौर बनाने के प्रयास में लगे थे, उस पर ब्रेक लग गया है. सपा के शीर्ष नेतृत्व ने 70-72 विधायकों व मंत्रियों की छानबीन शुरू कर दी थी, जिनकी भाजपा से नजदीकियों की चर्चा थी. सपाई गलियारे में चर्चा है कि विधानसभा सत्र के बाद ऐसे मंत्रियों को हटाया जाएगा जो भाजपा के साथ पेंच लड़ा रहे थे. ■

feedback@chauthiduniya.com

रायबरेली के लोगों को ऑनलाइन चिकित्सा सुविधा

डॉ. पंकज सिंह

लोग रायबरेली के लोगों को आकस्मिक उच्च चिकित्सा के लिए अब लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगे. अब रायबरेली के डॉक्टरों को रोगियों का इलाज करते वक्त ही पीजीआई के वरिष्ठ चिकित्सकों से सलाह भी मिलने लगी है. रायबरेली के जिला चिकित्सालय में स्थापित टेलीमेडिसिन सेंटर से चिकित्सक ऑनलाइन कसल्टेंसी लेकर उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधा मुहैया करा रहे हैं. टेलीमडिसिन सेन्टर की स्थापना रायबरेली में सात अगस्त 2007 को जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट डॉ. सैयद अल्ताफ हुसैन के प्रयास से हुई. यह प्रदेश का पहला टेलीमेडिसिन सेन्टर है. टेलीमेडिसिन सेन्टर के स्थापना के बाद उसके बारे में प्रशिक्षण देने से लेकर क्रियान्वयन तक सहयोग देने का काम पीजीआई के वरिष्ठ नोडल अफसर (टेलीमेडिसिन) डॉ. एसके मिश्रा ने किया. शुरुआती दौर में पीजीआई केएक टेक्नीशियन को रायबरेली में तैनात किया गया था.

टेलीमेडिसिन से उन मरीजों को लाभ मिल रहा है जिनका इलाज पीजीआई से हो रहा है. अब उन्हें इलाज के लिए लखनऊ पीजीआई नहीं जाना पड़ रहा है. डॉ. अल्ताफ ने बताया कि उन मरीजों की केस हिस्ट्री लेकर ऑनलाइन तरीके से सीधे पीजीआई के डॉक्टरों के पास भेज दी जाती है. उनसे कन्सल्टेंसी लेकर दवाएं वगैरह लिख दी जाती हैं, खून व अन्य पैथोलॉजिकल परीक्षण के लिए स्लाइड बनाकर उसे ऑनलाइन भेजकर पीजीआई से रिपोर्ट मंगा ली जाती है. इससे मरीजों को पैसे, समय व बेवजह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है.

जटिल रोगों का इलाज करते समय रायबरेली जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों के सामने यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीजीआई के वरिष्ठ चिकित्सकों से सलाह-मशविरा कर उसका आसानी से हल निकाल लेते हैं. इस तरह से चिकित्सा के स्तर में भी सुधार आ रहा है. जिला चिकित्सालय रायबरेली में प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को डाक्टरों को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए नई-नई तकनीक बताई जाती हैं. टेलीमेडिसिन सेन्टर में ही प्रत्येक बुधवार को नर्सिंग स्टाफ के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है. बहुत जल्द ही ऑपरेशन थियेटर को भी पीजीआई से ऑनलाइन जोड़ दिया जाएगा. इसके लिए आवश्यक जांच हो चुकी है. इस पहल से रायबरेली में जटिल सर्जरी भी आसानी से हो जाएगी. लखनऊ पीजीआई के सौजन्य से एक मोबाइल टेलीमेडिसिन बस छह दिनों के लिए रायबरेली आएगी. यह बस मिनी ऑपरेशन थियेटर, एक्स-रे मशीन, अल्ट्रा सांउड मशीन, पैथोलॉजी क्लीनिक जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी. यह बस भी पीजीआई से ऑनलाइन तरीके से जुड़ी रहेगी. डॉ. अल्ताफ ने बताया कि यह वैन उन गांवों में सबसे पहले जाएगी जहां उच्च चिकित्सा सुविधों उपलब्ध कराने की सबसे अधिक आवश्यकता है. ■

उत्तर प्रदेश के सीमांत जिलों में हो रही हैं विदेशी जासूसी

हरिशंकर वर्मा/अजय गुप्ता

नेपाल सीमा पर स्थित उत्तर प्रदेश के लखीमपुर-खीरी जिले के सीमांत क्षेत्रों में विदेशी ताकतें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से नेटवर्क संचालित कर भारत के खिलाफ जासूसी कर रही हैं. इसका प्रमाण है आए दिन भारतीय सीमा के जंगली व मैदानी इलाकों में अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का संदेहास्पद अवस्था में बरामद होना. इस गंभीर मामले को खुफिया तंत्र व प्रशासन हल्के में लेकर नजरअंदाज कर रहा है. लेकिन उनका यह रवैया देश की सुरक्षा व आंतरिक गोपनीयता के लिए घातक साबित हो सकता है. प्रशासन और खुफिया विभाग ऐसे संदेहास्पद कैमरे और ट्रांसमीटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं रखते हैं और न ही इन उपकरणों को उच्च तकनीकी जांच के लिए भेजते हैं, खुफिया एजेंसियों के कुछ जानकार इसे चीन की हरकत मान रहे हैं. लेकिन इस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है.

भारत-चीन के बीच स्थित नेपाल भारत का मित्र राष्ट्र है. नेपाल की वजह से चीन भारत में सीधी तरह घुसपैठ करने में नाकाम रहता है. लेकिन वह अपनी भारत विरोधी हरकतें लगातार जारी रखे है. भारत की सुरक्षा व आंतरिक गोपनीयता को लेकर वह भारत में जासूसी का काम कर रहा है. वह अपने खुफिया तंत्र को मजबूत कर रहा है ताकि उसे भारत के बारे में सारी जानकारी मिल सके. पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने सीमांत इलाकों में अपना जाल पहले से बिछा रखा है. चीन भारत पर इलेक्ट्रॉनिक जासूसी कर रहा है. इसके लिए उसने इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली के साथ मजबूत नेटवर्क को संचालित कर रखा है. भारतीय सीमा पर स्थित जंगलों व आसपास के इलाकों में हर वर्ष गुब्बारों के जरिए थर्माकोल से बना डिब्बों में एन्टीना, वायर, शक्तिशाली कंडेंसर, कैमरे लगे ट्रांसमीटर जैसे उपकरण बरामद किए गए हैं. लेकिन इन यंत्रों को लेकर प्रशासन व खुफिया विभाग कतई गंभीर नहीं है. कुछ अधिकारी तो इसे मौसम की जानकारी लेने वाले उपकरण बताते हैं. लेकिन कोई भी अधिकारी ठोस तकनीकी जानकारी के आधार पर कुछ नहीं बताता और बड़े हल्केपन से उस पर पर्दा डालने में ही जुटा रहता है. उनका यह रवैया देश के लिए घातक साबित हो सकता है. बीते चार फरवरी को थाना कोतवाली धौरहरा के ग्राम अभयपुर निवासी गौतम कश्यप को थर्माकोल का डिब्बा मिला जिसमें एन्टीना वायर लगा था. पड़ोस में गुब्बारा तथा डोर भी मिली. इस डिब्बे में कई शक्तिशाली उपकरण लगे मिले. इससे पहले 19 अप्रैल 2014 को भी बेलरायां जंगल की बीट मूर्तिहा में वृक्ष पर टंगी हुई ऐसी ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिली थी. 23 अप्रैल को थाना सम्पूर्णानगर के ग्राम परसपुर में पाल सिंह के खेत में लावारिस हालत में उपकरणों से सुसज्जित डिवाइस पड़ी मिली थी, जिसमें दो शक्तिशाली कंडेसर लगे थे. 29 अप्रैल को थाना निघासन के ग्राम कोरियानी में ग्राम की नसरीन को ऐसा उपकरण मिला था जिसमें वायर, एरियल के साथ गुब्बारा आदि लगा था. दिसम्बर माह में थाना भीरा के एक गांव में इसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटर जैसा यंत्र मिला था. जानकारों का मानना है कि विदेशी ताकतें भारत की बढ़ती ताकत को देखकर उसकी सुरक्षा व्यवस्था और आन्तरिक गोपनीयता में सेंध लगाना चाहती है. इसके लिए गुब्बारे के सहारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आकाश में छोड़कर सीमाई इलाकों की तस्वीरें ली जाती हैं. आकाश में उड़ते हुए टोह लगाते-लगाते कभी-कभार वे जमीन पर गिर जाती हैं. जो लोग इसे मौसम का हाल लेने वाला यंत्र बताते हैं वे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते कि नेपाल से लगे सीमा क्षेत्र का मौसम जानने की क्या अतिरिक्त जरूरत है कि बार-बार ऐसे ही संवेदनशील इलाकों में ये उपकरण भेजे जा रहे हैं? ऐसे यंत्र प्रदेश की राजधानी के मौसम का हाल जानने के लिए क्यों नहीं भेजे जाते, जहां सुरक्षा का अमला लगातार चौकस रहता है? भारत-चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अच्छे संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं. चीनी सेना की आए दिन भारतीय सीमा में घुसपैठ सुर्खियां बनती रहती हैं. लिहाजा, चाइना मेड उपकरणों का इस तरह मिलना संदेह को और पुख्ता करता है. ■

कम्पाइल बाक्स

सीमाई इलाके में मिल रहे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थाने-चौकियों में धूल फांक रहे हैं. पिछले आठ माह से इसमें तेजी आई है. लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद भी जिला प्रशासन इन मामलों की तह में जाने में नाकाम है. स्थानीय नागरिकों का भी कहना है कि जिला प्रशासन व सुरक्षा एजेंसियों को सीमा पर मिलने वाले ऐसे रहस्यमय ट्रांसमीटरों को जांच के लिए भारतीय सेना के पास भेजना चाहिए, ताकि इनकी सही-सही जानकारी हासिल हो सके. लखीमपुर खीरी के पुलिस अधीक्षक अरविंद सेन कहते हैं कि इन उपकरणों से देश को किसी प्रकार का खतरा नहीं हो सकता है. लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अभयपुर गांव में जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिला है उनके बारे में जांच के बाद ही पता चलेगा. इससे पूर्व जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाये गये हैं उसके बारे में उन्होंने अनभिज्ञता जताई और कहा कि इसकी हमें जानकारी नहीं है.

हरीश और बहुगुणा के बीच रस्साकशी जारी

राजकुमार शर्मा

उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार अपनी कार्यशैली से कई क्षेत्र में कीर्तिमान बना रही है. हरीश सरकार ने हाल ही में अपने कार्यकाल का एक वर्ष सफलतापूर्व पूर्ण किया है. गौरतलब हो कि पिछले साल विजय बहुगुणा को लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस हाई कमान ने आनन-फानन में मुख्यमंत्री पद से हटाकर प्रदेश की बागडोर हरीश रावत के हाथों में सौंपी थी. तब से बहुगुणा लगातार हरीश रावत को बदनाम कर उन्हें सत्ता से बेदखल करने के हर संभव कोशिश कर रहे हैं. कांग्रेस हाई कमान पिछले दिनों प्रदेश में संपन्न हुए पंचायत और कैंटोन्मेंट बोर्ड के चुनावों में मोदी लहर को धत्ता दिखाकर विजयी परचम लहराने की वजह से रावत को अभय दान दे रखा है. एक व्यावसायिक घराने की मदद से मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाने वाले विजय अब भी पराजय मानने को तैयार नहीं हैं. बहुगुणा ने एक बार फिर उसी व्यावसायिक घराने की मदद से हरीश रावत की नींद हराम करने की ठान ली है. पूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा ने हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नई दिल्ली में मुलाक़ात की. इस दौरान बहुगुणा ने कांग्रेस अध्यक्ष से स्पष्ट रूप से कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार ढुलमुल तरीके से चल रही है. इससे पार्टी का मिशन-2017 प्रभावित होगा. मुख्यमंत्री हरीश को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना चाहिए. उत्तराखंड सरकार से पूरी तरह खफा विजय बहुगुणा ने कहा कि उनकी कांग्रेस हाई कमान से प्रदेश के कई मुद्दों पर बात हुई. उनका दावा है कि कांग्रेस अध्यक्ष भी प्रदेश में विकास की धीमी रफ्तार की वजह से चिंतित हैं. सोनिया गांधी चाहती हैं कि राज्य में तेजी के साथ विकास हो. प्रदेश में संगठन को सशक्त बनाने को लेकर भी कांग्रेस अध्यक्ष से चर्चा हुई. विजय बहुगुणा ने सोनिया गांधी को जानकारी दी कि दायित्व आवंटन में देरी और प्रदेश हित में की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं की उपेक्षा मुख्यमंत्री रावत खास रणनीति के तहत कर रहे हैं. इससे प्रदेश की जनता में कांग्रेस सरकार के प्रति काफी गुस्सा है. बहुगुणा ने कांग्रेस अध्यक्ष को यह समझाने की कोशिश की जब तक केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को खत्म नहीं करेगा, तब तक प्रदेश में कांग्रेस सशक्त नहीं हो पायेगी. इसके अलावा बहुगुणा ने केदारनाथ में अब तक किए गए विकास कार्य के बारे में भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को जानकारी दी. बहुगुणा ने कहा कि जिस रफ्तार से प्रदेश में पुनर्निर्माण व पुनर्वास का कार्य होना चाहिए था, राज्य सरकार उस मोर्चे पर भी असफल रही है. आगामी चारधाम यात्रा पर भी इसका असर पड़ सकता है.

जो बातें बहुगुणा ने कांग्रेस हाई कमान से कहीं हैं वे सभी निराधार साबित हो रही हैं, मुख्यमंत्री गुटबाजी खत्म करने के लिए हमेशा एक कदम आगे दिखते है. उनके दल की बात तो दिगर है, विपक्षी दलों के कुछ विधायक अपने दल के अनुशासन की परवाह किए बगैर मुख्यमंत्री के जनहितकारी कार्यों की सराहना करते हैं. घनसाली के विधायक भीमलाल आर्य के बाद अब पुरोला के विधायक मालचंद भी रावत की तारीफ कर भाजपा को परेशानी में डालते नज़र आ रहे हैं. गंगनाणी बड़कोट में आयोजित कुंड की जातर में भाजपा के पुरोला विधायक मालचंद ने मुख्यमंत्री हरीश रावत की जमकर तारीफ करते हुए अगली बार भी उनके सीएम बनने की कामना की. यहां जनता को संबोधित करते हुए विधायक मालचंद ने सीएम हरीश रावत की तारीफों के पुल बांध दिए. उन्होंने सीएम को विकास पुरुष का दर्जा देते हुए मंच से ही देवी-देवताओं से कामना की कि अगली बार भी हरीश रावत ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनें. पत्रकारों से बातचीत में भी उनका पार्टी विरोधी रवैया साफ नजर आया. उनके बयान के बारे में पूछे जाने पर विधायक ने कहा कि मेरे चाहने या न चाहने से क्या होता है, बाकी दिल्ली में तो आप हाल देख ही चुके हैं. इसके बाद जब सीएम हरीश रावत के संबोधन की बारी आई तो उन्होंने मेले में शामिल शहरी विकास मंत्री प्रीतम पंवार, पंचायती राज मंत्री प्रीतम सिंह तथा पर्यटन मंत्री दिनेश धनै की तो खुलकर तारीफ की. लेकिन विधायक मालचंद की ज्यादा तारीफ करने से इंकार करते हुए कहा कि यदि उनकी ज्यादा तारीफ की तो ये फंस जाएंगे.

राजनीति के मर्मज्ञ कांग्रेस के भीतर खींचतान का मुख्य कारण राज्य मंत्रिमंडल में रिक्त हुए एक पद के कारण तेज हुई है. बहुगुणा ने एक बार फिर नाराजगी जताकर रावत के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं. एक पखवाड़े में यह दूसरा मौका है जब पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस हाईकमान के दरवाजे पर दस्तक दी, इसके बाद हरीश रावत को भी दिल्ली दौड़ लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा. खाली पड़े मंत्री पद को लेकर कांग्रेस में स्थिति एक अनार, सौ बीमार जैसी है, पूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा अपने खेमे के लोगों को यह सीट देने के लिए भले ही जोर बनाए हों, पार्टी के भीतर दूसरे कद्दावर नेताओं की निगाहें इस पर गड़ी हुई हैं. कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश के निधन से मंत्रिमंडल में खाली हुई एक सीट भरने को लेकर मुख्यमंत्री हरीश रावत जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहते, पार्टी के भीतर दिग्गजों के बीच तलवारें रह-रहकर म्यान से बाहर आ रही हैं. सितारगंज में सरकारी भूमि के पट्टाधारकों को मालिकाना हक दिए जाने के मुद्दे पर सरकार पर दबाव बना चुके पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा अब किसी भी तरह सियासी नफा-नुकसान के गुणा-भाग से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. वर्ग-चार की भूमि के नियमितीकरण पर बहुगुणा की नाराजगी को दूर करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल फैसला ले चुकी है, सूत्रों की मानें तो मंत्रिमंडल के एक पद को बहुगुणा अपने खाते में लाने के लिए सिर से पैर तक जोर लगाने में नहीं चूक रहे हैं. बहुगुणा के सियासी दांव की काट के लिए मुख्यमंत्री रावत को नई दिल्ली का रुख करना पड़ा. यह दीगर बात है कि मुख्यमंत्री के खेमे ने इसे सिरे से खारिज करने की कोशिश की है.

मंत्री पद को लेकर मुख्यमंत्री को चारों ओर से दबाव झेलना पड़ रहा है. मुख्यमंत्री के करीबियों के मुताबिक मंत्री पद पर फैसला हरिद्वार में रिक्त हुई भगवानपुर सीट पर उपचुनाव के बाद लिया जा सकता है. इससे पहले मंत्री पद दिए जाने को सियासी तौर पर मुफीद नहीं माना जा रहा है. उधर, मुख्यमंत्री विरोधी खेमा यह बात मानने के लिए तैयार नहीं है. बहुगुणा नरेंद्रनगर से विधायक सुबोध उनियाल के लिए पैरवी कर रहे हैं तो पूर्व कैबिनेट मंत्री और डोईवाला विधायक हीरा सिंह बिष्ट, जसपुर विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल, पूर्व मंत्री व विकासनगर विधायक नवप्रभात, पूर्व मंत्री व बदरीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी को भी मंत्री पद के दावेदारों में शुमार किया जा रहा है. ■

शिक्षा माफियाओं की बल्ले-बल्ले

शत्रुंजय सिंह रैकवार

उत्तर प्रदेश सरकार के ,बन रहा है आज संवर रहा है कल , के नारे से प्रेरित होकर, पाठ्यक्रम के बगैर पूर्ण हुए ही यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 19 फरवरी से शुरू करा दी गईं. सीबीएसई बोर्ड से टक्कर लेने के लिए यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू कराई गई हैं, जबकि बोर्ड के विद्यालयों में पाठ्यक्रम अभी भी पूरा नहीं हुआ है. शिक्षक नेता विजयकान्त का कहना है कि सरकार का यह प्रयोग यूपी बोर्ड के बच्चों के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ है. पाठ्यक्रम पूर्ण हुए बगैर होने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षाओं से गोरखपुर के साढ़े तीन लाख और प्रदेश भर के लाखों परीक्षार्थियों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है. यूपी बोर्ड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि समय से पहले और अधूरे कोर्स के साथ बोर्ड परीक्षायें आयोजित हुईं. अधूरी पढ़ाई के साथ ही छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल हुईं. सीबीएसई की तर्ज पर माध्यमिक शिक्षा का शैक्षणिक सत्र जुलाई के बजाय अब अप्रैल से ही शुरू किए जाने को लेकर शिक्षा विभाग तत्पर है. इसी वजह से बोर्ड की परीक्षायें पहले आयोजित कराने का अहम फैसला लिया गया. महज सात माह के अल्प शैक्षणिक सत्र का भी आधा समय विविध अवकाश में ही निकल गया. छात्रों को भारी-भरकम पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए न तो पर्याप्त समय मिला, न ही इसके लिए शिक्षा संस्थानों की ओर से किसी तरह की विशेष कोशिश की गई. शायद ही कोई ऐसा स्कूल है जिसमें पचास पाठ्यक्रम पूरा हुआ हो. ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में संचालित स्कूल-कॉलेजों की हालत और भी बदतर है. वहां के छात्रों का भविष्य अधर में फंस गया है. परीक्षा में सवाल कहां से पूछे गए? प्रश्न पत्रों के चयन का आधार क्या रखा गया? मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा? तमाम ऐसे सवाल सामने हैं, लेकिन इनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है. 12 वीं बोर्ड के विज्ञान वर्ग की परीक्षार्थी अनुराधा सिंह कहती हैं कि विज्ञान विषय की तैयारी अधूरी ही रह गई. कॉलेज में पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो सका. सुप्रिया श्रीवास्तव कहती हैं कि पूरे पाठ्यक्रम पर केवल सरसरी निगाह दौड़ाने भर का मौका मिल पाया. स्कूल-कॉलेजों में पाठ्यक्रम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, इससे प्रशासन को क्या मतलब. गोरखपुर के जिलाधिकारी रंजन कुमार कहते हैं कि परीक्षा में नकल रोकना उनका दायित्व है. बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन सकुशल सम्पन्न कराने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है. नकल होगी तो इसके लिए डीआईओएस जिम्मेदार होंगे. आधी अधूरी परीक्षा की तैयारी को देखते हुए शिक्षा माफियाओं ने पहले ही अपनी बिसात बिछा ली. डीआईओएस को प्रभाव में लेकर मनचाहा परीक्षा केंद्र हासिल कर लिया गया. शिक्षा माफिया मनमाफिक केन्द्र व्यवस्थापक और मनमाफिक स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती भी करा लेते हैं. परीक्षा केन्द्रों पर छात्र-छात्राओं को प्रथम श्रेणी में पास कराने के लिए पांच हजार रुपये और द्वितीय श्रेणी के लिए चार हजार रुपए तो तृतीय श्रेणी के लिए ढाई हजार रुपए की वसूली की गई है. ■

गोरखपुर मंडल में इंटर के परीक्षार्थी

जिला	बालक	बालिका
गोरखपुर	35038	35275
देवरिया	38015	36671
महराजगंज	15164	17677
कुशीनगर	18986	22728

गोरखपुर मंडल में हाईस्कूल के परीक्षार्थी

जिला	बालक	बालिका
गोरखपुर	41746	40406
देवरिया	42564	39668
महराजगंज	19421	21495
कुशीनगर	27936	31370

गोरखपुर मंडल में परीक्षा केन्द्र

गोरखपुर	229
देवरिया	277
महराजगंज	105
कुशीनगर	171

उत्तर प्रदेश में शिक्षा नीति की असलियत उजागर

बच्चों के लिए स्कूल या पढ़ाई का नाम लेना भी जुर्म

शहर की दहलीज लांघते ही ग्रामीण इलाकों में गरीबी की दीवार से टकराकर बिखर जाती हैं सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चलो और मीन मंच जैसी योजनाएं.

अभिषेक त्रिपाठी

सुबह के 11 बजे थे, हम कानपुर नगर की सरसौल विकास खंड के लाहौरपुर जूनियर पाठशाला में पहुंचे. यह स्कूल कानपुर नगर जिले के सरसौल खंड के अंदरूनी अंतिम छोर पर फतेहपुर जिले की सीमा पर स्थित है. यहां हमारे सामने एक डरी-सहमी सी छात्रा थी. उसकी उम्र तकरीबन 13 साल भी नहीं थी वह अपनी टीचर के सामने खड़ी कांप रही थी. उसका चेहरा शांत था, उसकी बोलती सी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे. बेचैनी में वह अपने ही हाथों की खाल नोंच रही थी और किसी अनजाने भय से ग्रस्त लग रही थी. उसकी टीचर प्रतिमा कौमुदी ने हमारे कहने पर उससे केवल एक सवाल भर पूछ दिया था. उन्होंने पूछा था कि मुस्कान बताओ तुम रोज स्कूल क्यों नहीं आ पाती हो! बस इतने से सवाल पर उस मासूम का यह हाल हो गया था. काफी समझाने-बुझाने के बाद वह रुंधे गले से यह बता सकी कि अम्मी-अब्बा हमको बकरी चराने के लिए भेजते हैं, स्कूल के लिए तैयार होता देखते ही उसके अब्बू और दादी तक नीम की छड़ी से उसे बेतहाशा पीटने लगते हैं. आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली इस मासूम बच्ची ने बताया कि उसकी दो छोटी बहनें हसीना और शाहीन भी हैं. वे दोनों भी लाहौरपुर प्राइमरी स्कूल की छात्राएं हैं. पढ़ाई करने या स्कूल जाने के नाम पर उन दोनों केघर में भी उनका यही हाल किया जाता है. इन तीनों बहनों को अपने दो भाइयों के साथ मजबूरी में पूरे दिन बकरी चराने जाना पड़ता है या फिर घर में चूल्हा-चक्की करनी पड़ती है. स्कूल जाने का मौका केवल तब मिलता है जब घर में खाने को कुछ नहीं जुट पाता है. उस दिन तीनों बहनें स्कूल में ही पेट भर खाना खाती हैं, और थोड़ा बहुत बचाकर घर भी ले जाती हैं, जिससे उनके दोनों भाइयों का भी पेट भर जाए.

मुस्कान शाहीन और हसीना

बात इतनी ही नहीं, इन बच्चियों के अभिभावक उन्हें समझाने के लिए घर पहुंचने वाली शिक्षिकाओं से भी बुरा बर्ताव करते हैं. जब शिक्षाधिकारी मुस्कान के अम्मी-अब्बू को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए समझाते हैं, तब वो एक ही बात कहते हैं कि तो बकरिया का तुम चरहैयो साहिब और हमार घर का दूसर काम कौउन करिहे ! मुस्कान के अम्मी-अब्बू का यह बर्ताव देखकर समझ में आ जाता है कि स्कूल नहीं आने के नाम पर वो क्यों थर-थर कांपने लगती है. और शायद रोजमर्रा की इसी मारपीट के कारण वह डरे-सहमे व्यक्तित्व की लड़की हो गई है. लेकिन इतनी दुश्वारियों के बावजूद मुस्कान की छोटी बहन और पांचवीं क्लास की छात्रा हसीना से कोई पूछ ले कि वो बड़ी होकर क्या बनना चाहती है, तो हसीना तपाक से कहती है, हम तो बड़े होकर मैडम जी बनेंगे. यानि कि नन्हीं हसीना बड़ी होकर टीचर बनना चाहती है, क्योंकि उसकी शिक्षकाएं और शिक्षक ही उसके रोल मॉडल हैं. दरअसल, गरीबी की शिकार इन मासूमों ने अभी तक जितनी भी दुनिया देखी है, उसमें उनकी स्कूल की मैडम जी ही सर्वश्रेष्ठ हैं. उन्हें देखकर लगता है कि वे स्कूल आते ही अपने सारे दुखदर्द भूल जाती हैं. लेकिन साफ तौर पर मुस्कान और उसकी बहनों जैसे मामलों में स्कूल चलो, सर्व शिक्षा अभियान और मीन मंच जैसे करोड़ों के खर्चे वाली यौजनायें और अभियान असफल रहे हैं, क्योंकि गरीबी स्कूल जाने वाले बच्चों के अभिभावकों को मजबूर किए है, ऐसे अभिभावकों को समझाने पहुंचने वाले शिक्षकों और शिक्षाधिकारियों के बोल वचन उनके लिए कोरे उपदेश साबित होते हैं. साफ तौर पर हुक्मरानों द्वारा बनाई गईं शिक्षा नीतियां शहर की दहलीज लांघते ही गरीबी की दीवार से टकराकर बिखर जाती हैं. केवल लाहौरपुर या सरसौल में ही नहीं, पूरे उत्तरप्रदेश का यही हाल है.

परिवेश का तजुर्बा नहीं होने से भी मुश्किलें बढ़ीं- खंड शिक्षाधिकारी

बच्चों को स्कूल तक लाने में केवल अभिभावकों की गरीबी ही नहीं, शहर से आने वाले शिक्षकों की पारिवेशिक कमी भी कारण है, यह कहना है सरसौल के खंड शिक्षा अधिकारी संजय यादव का. संजय कहते हैं कि शहरों और कॉन्वेंट आदि स्कूलों में पढ़कर आने वाले शिक्षकों को ग्रामीण इलाकों के बेहद गरीब अभिभावकों को जाकर समझाने, और उनके बच्चों को किसी भी तरह स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करने का जिम्मा दिया जाता है. लेकिन ठेठ आधुनिक शहरी परिवेश से आने वाले शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र और गरीबी के परिवेश का तजुर्बा नहीं होने की वजह से वे प्रभावी ढंग से अभिभावकों को प्रेरित नहीं कर पाते हैं. संजय के अनुसार नये शिक्षकों को इस तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए.

खंड शिक्षा अधिकारी संजय यादव

प्राइवेट स्कूलों के दुष्प्रचार ने मारा

शिक्षा विभाग के अधिकारियों और टीचरों का आरोप है कि प्राइवेट स्कूल वाले अभिभावकों के बीच सरकारी स्कूलों के खिलाफ दुष्प्रचार करके बच्चों को बटोरते हैं. सरसौल विकास खंड के गुड़गुड़ियापुर प्राथमिक पाठशाला की प्रधान अध्यापिका कृष्णा श्रीवास्तव, सलेमपुर प्राइमरी की प्रधान अध्यापिका सरोज द्विवेदी और लाहौरपुर प्राइमरी की सहायक अध्यापक नीलम का कहना है कि बच्चों को स्कूल तक लाने में केवल अभिभावकों की गरीबी और व्यवहार ही एकमात्र अड़चन नहीं है, बल्कि कई बार इसमें सरकारी नीतियां भी मुश्किलें खड़ी कर देती हैं. जैसे कि सरकारी स्कूलों के आसपास ही प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दे देना. अब सरकारी शिक्षक आसपास के गांवों में घर-घर जाकर अभिभावकों की काउंसलिंग करते हैं. लेकिन आसपास खुले प्राइवेट स्कूल वाले छल-प्रपंच और सरकारी स्कूलों के खिलाफ कुप्रचार करके, अभिभावकों को बरगलाकर बच्चों को अपने यहां ले जाते हैं. वे अभिभावकों को बताते हैं कि सरकारी स्कूलों में सुविधाएं नहीं हैं, वहां पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षक नहीं आते हैं, आते भी हैं तो पढ़ाते नहीं हैं, वगैरह, वगैरह.

खंड शिक्षाधिकारी संजय यादव का कहना है कि इसके बाद वे अभिभावकों को इन प्राइवेट स्कूलों की हकीकत से अवगत कराते हैं. वे बताते हैं कि सरकारी स्कूलों में एक से एक क्वालीफाइड, एमएड, बीएड और डॉक्ट्रेट किए शिक्षक पढ़ाते हैं. बच्चों को वहां फ्री किताबें, ड्रेस व मिड डे मील भी मिलता है. लेकिन प्राइवेट स्कूलो में बेहद कम पढ़े-लिखे टीचर्स होते हैं, वहां महंगी किताबें खरीदनी पड़ती हैं.

दुष्प्रचार है, पर हालात बुरे नहीं

परिषदीय स्कूलों के शिक्षक और अधिकारियों का कहना है कि उनके यहां शिक्षा और सुविधाओं की हालत उतनी भी खराब नहीं है जितना कि प्रचारित किया जाता है. यहां एक समस्या यह भी है कि दूर-दराज के गांव के अभिभावक दूरी और वाहन उपलब्धता नहीं होने के कारण अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पाते हैं. ऐसे में हर दो-चार स्कूलों के बीच अगर बेसिक शिक्षा विभाग बच्चों को लाने-ले जाने के लिए एक छोटे स्कूल वाहन का प्रावधान कर दे तो शायद प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दी जा सकती है.

पांच किलोमीटर दायरे में नहीं हों प्राइवेट स्कूल

प्रधान अध्यापकों ने ये सुझाव दिए है कि सरकारी स्कूलों के पांच किलोमीटर के दायरे में किसी प्राइवेट स्कूल को मान्यता न दी जाये. ऐसा होने पर शिक्षकों द्वारा बच्चों के दाखिले के लिए किए जाने वाली अभिभावक संपर्क और दूसरी कोशिशें पूरी तरह बेकार हो जाती हैं. सरकारी स्कूलों में पांच से कम उम्र में दाखिला नहीं दिया जाता है जबकि प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, प्री-नर्सरी के नाम पर बच्चों को कम उम्र में ही दाखिला दे दिया जाता है.

सरकारी स्कूलों में पढ़कर बेइज्जती होती है

सलेमपुर प्राइमरी की प्रधान अध्यापिका सरोज द्विवेदी ने तो एक वाक्या यह भी बताया कि एक बार अभिभावक दो बच्चों को लेकर दाखिला कराने आए. उनकी मां बोली अपने पगलेट बिटवा का दाखिला हम इहां सरकारी स्कूल में करवैहें और पढ़ाई में तेज वाले छोटे का प्राइवेट स्कूल मां. हेडमास्टर यह देख-सुनकर दंग थीं कि लोग अपने तेजतर्रार बच्चों को प्राइवेट स्कूल में और पढ़ने में कमजोर बच्चों को सरकारी स्कूलों के भरोसे ठेल देना चाहते हैं. यह मानसिकता दुष्प्रचार का ही नतीजा है. उन्होंने एक प्रसंग तो ऐसा बताया कि जिसमें बीच सत्र में एक अभिभावक ने अपने बच्चे को सरकारी प्राइमरी स्कूल से केवल इसलिए निकाल लिया, क्योंकि गांव वाले उसे ताने देते थे. उस अभिभावक से कहा जाता था कि तुम्हारे पास पैसा है तो बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़वाकर अपनी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो.

बच्चों ने वर्ल्ड बैंक प्रबंधक को दिया था नायाब तोहफा

सरसौल के गुड़गुड़ियापुर प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने हाल में ही शहर में आए वर्ल्ड बैंक चेयरमैन किम यांग जुंग को उनका एक शानदार पोर्ट्रेट भेंट किया था. जिसमें हिंदी में एक छोटी सी प्रेरक कविता भी लिखी थी. इसे देखते ही किम यांग जुंग के मुंह से निकला वाओ ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग वर्क(वाह बेहद खूबसूरत, ये बेहतरीन है). इस पोर्ट्रेट को बच्चों से पाने के बाद उन्होंने बच्चों से कहा कि वे कैसे भी परिवेश से आएं हों, कितने भी गरीब हों, लेकिन यदि वे ठान लें और लगातार मेहनत करें तो वे कुछ भी बन सकते हैं, जैसे कि वो बन गये. उन्होंने बच्चों को बताया कि वे भी बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन दृढ़ संकल्प और मेहनत की वजह से आज वह यहां तक पहुंचे हैं. गुड़गुड़ियापुर के इस सरकारी स्कूल की उपलब्धि केवल इतनी ही नहीं है, हाल ही में स्कूल का निरीक्षण करने आए विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विवेक वार्ष्णेय ने भी सर्किट हाउस में अधिकारियों के बीच इस स्कूल की जमकर तारीफ की थी. खंड शिक्षाधिकारी संजय यादव के अनुसार स्कूल की प्रधान अध्यापिका कृष्णा श्रीवास्तव को उनके पर्सनल नंबर पर फोन करके स्कूल के बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दे सकने के लिए उन्होंने जमकर तारीफ की थी. कृष्णा श्रीवास्तव ने बताया कि सचिव निरीक्षण के दौरान आए तो बच्चों से संस्कृत श्लोकों, प्रार्थनाओं, जनरल नॉलेज के सवालों के सटीक उत्तर पाने के बाद वे संतुष्ट और खुश होकर वापस गए. इसके बाद उन्होंने अगले दिन उन्हें फोन करके तारीफ की. खंड शिक्षाधिकारी के अनुसार हेडमास्टर का नाम राज्यपाल पुरस्कार के लिए भेजा जा सकता है, गौरतलब है कि सरसौल खंड के कई स्कूलों को उनके बेहतरीन परफार्मेंस के लिए अघोषित रूप से मॉडल माना जाता है. यहां की प्रधान अध्यापिका ने मिड डे मील की गुणवत्ता में धांधली करने वाले ग्राम प्रधान के खिलाफ भी मोर्चा खोला और लिखित में शिकायत करने के बाद मिड डे मील की पूरी व्यवस्था अपने हाथ में ले ली.

पिकनिक पर जाते हैं और लाइब्रेरी में पढ़ते हैं

सलेमपुर प्राइमरी की हेडमास्टर सरोज द्विवेदी ने बताया कि वो तो मिसलेनियस फंड से बस अरेंज करके अपने स्कूल के डेढ़ सौ बच्चों को लगातार तीन सालों से चिड़ियाघर, जेके मंदिर, तुलसी उपवन मोतीझील आदि स्थानों पर पिकनिक पर ले जाती हैं. वहीं स्कूल में मेनटेन की गई लाइब्रेरी में बच्चों को हर तरह की ज्ञान-विज्ञान की किताबें पढ़ने, और किताबों को घर ले जाने की सुविधा मिलती है. इस तरह कई हेडमास्टर अपने अपन स्तर पर प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देने की पूरी कोशिश करते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com